राजस्थान विधान सभा

१८ वीं बैठक, दिनांक २० मार्च, १९५३

सदन का कार्य ८ बजकर १८ मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५५५

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीराम

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५५६

श्री अध्यक्ष—श्री लालूराम

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५५७

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान में सिनेमा मोनोपोली अब भी कायम है ?

(२) यदि है, तो किन २ शहरों में और वह कब तक और रहेगी ?

(३) क्या कोटा शहर के किन्हीं महानुभावों ने सरकार के सम्मुख नया सिनेमा खोलने बाबत पिछले दो वर्ष में कोई आवेदन-पत्र दिये हैं और वे किस किस के हैं ?

(४) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(१) जी नहीं।

(२) जी हां। आवेदन-पत्र निम्नलिखित महानुभावों से प्राप्त हुए—

(१) श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा।

(२) मेसर्स गोवर्धनलाल मदनलाल।

(३) श्री रूपनारायण तथा श्री अयोध्याकुमार।

(४) श्री मदनलाल।

चूंकि लाईसेंसिंग ऑथोरिटी कमिश्नर साहब कोटा हैं इसलिये उनको उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये।

Page No.2

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--हां ।

श्री कंवरलाल जेलिया--तो यह मोनोपोली कब तक उठाई जावेगी

श्री टीकाराम पालीवाल--मोनोपोली नहीं है ।

श्री गुरूदयालसिंह संधु--जिन लोगों ने आवेदन-पत्र दिये उनके आवेदन-पत्र कब से सरकार के पास पड़े हुए हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--मेरे पास तारीख नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--अवधि तो बतानी चाहिये, कितने अर्से से उनकी अर्जियें पड़ी हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--उसकी तारीख मेरे पास नहीं है ।

एक सदस्य--क्या राजस्थान सरकार ओपिन एअर सिनेमा चलाने की भी इजाजत देती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--हां, टेम्परेरी दे देती है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--जिन लोगों ने आवेदन-पत्र सरकार को दिये हैं उनके निर्णय होने की कब तक आशा की जावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल--इस बात के लिये वे कमिश्नर कोटा से दरियाफ्त करें ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--कौन कौन से आदमियों को सिनेमा चलाने की इजाजत कानून के अनुसार दी जा सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--इसके लिये अलग रूल्स बने हुए हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या कोटा में एक सिनेमा कम है, इस कमी को सरकार महसूस करती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--नहीं ।

श्री कंवरलाल जेलिया--कितनी आबादी पर सिनेमाघर खोलने की सरकार आवश्यकता समझती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता । यह तो जनता की आवश्यकता पर निर्भर है ।

Page No.3

प्रश्न संख्या ५५८

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर के हॉस्पिटलों की जो ए, बी. श्रेणिएं रखी गई हैं, वे किस सिद्धान्त को लेकर रखी है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—जिन अस्पतालों में ३०० से अधिक रोग-शैया (बैड्स) रखे गये हैं, वह प्रथम श्रेणी के हैं।

जिन अस्पतालों में ३०० से कम व १०० से अधिक रोग-शैया (बैड्स) रखे गये हैं वे द्वितीय श्रेणी के हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा किस श्रेणी में आता है।

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप खुद जाकर देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५५६

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान सरकार के पास राजस्थान सहकारी शीर्ष बेंक के प्रश्न को लेकर किसी सहकारी बेंक के (डाईरेक्टर) संचालक मंडल ने अपनी मांग, अपने बेंक को राजस्थान सहकारी शीर्ष बेंक बनाये जाने के लिये प्रस्तुत कर रखी है ?

(ख) यदि हां, तो वह किस बेंक ने ?

(ग) उस पर राजस्थान सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार के पास कोआॅपरेटिव बंक, कोटा ने अपनी मांग की है।

(ग) इसका निर्णय अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार सहकारी बेंक के प्रश्न को सहकारिता के आधार पर हल करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, करेगी ?

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार के सामने इस बेंक ने जो मांग रखी है उसको मंजूर करने म सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अमृतलाल यादव--माननीय सदस्य स्पष्ट कहें, सुना नहीं ?

श्री कंवरलाल जेलिया--सरकार के सामने कोटा कोऑपरेटिव बैंक ने जो मांग रखी है उसको मंजूर करने में कौनसी आपत्ति है ?

श्री अमृतलाल यादव--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं। मगर फिर भी इस प्रश्न को बार बार उठाते हैं। जब कोटा कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की तो सरकार ने उनके सामने यह सवाल रखा कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स वह का वह नहीं रह सकता, उसमें रद्दोबदल करना होगा और इसके अलावा दूसरी ऐसी कई बातें हैं जिनको बताना मुनासिब नहीं और माननीय सदस्य तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया--माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि मैं कोई डाइरेक्टर नहीं हूं, जिसके लिये वे इस प्रकार का ऐतराज उठा रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव--(अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६०

श्री एच. के. व्यास--Will the Minister incharge for Home be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that one contractor named Shri Kanhayalal has filed a complaint regarding corruption against Shri Brij Bashi, Superintendent, Gardens, Jaipur ?

(b) Is it a fact that there are many serious charges of corruption against the said Superintendent ?

(c) What action has the Government taken ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—

(a) Yes.

(b) No.

(c) Enquiry is being made.

श्री एच. के. व्यास--Since when is the enquiry being made ?

श्री टीकाराम पालीवाल--Soon after the incident took place.

श्री एच. के. व्यास--I want to know how much time has elapsed since the commencement of the enquiry till today.

Page No.5

श्री टीकाराम पालीवाल—I think the Hon'ble Member knows when he puts the question when the incident took place. However, I will later give exact dates if you ask for it.

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that the enquiry is pending since last about a year now ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It is absolutely wrong.

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that it is pending for six months ?

(उप-मुख्य मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री एच. के. व्यास—Then should it be presumed that there is no reply ?

श्री अध्यक्ष—Exact information must be given since when the enquiry took place.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

प्रश्न संख्या ५६६

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister incharge for Home be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that one S. I. Police opened fire on the villagers of Bassi during the first week of February 1953 ?

(b) Is it a fact that the dispute arose out of the desire of the S. I. to keep a girl in the Thana during the night ?

(c) Has the Government conducted any enquiry into the incident ?

(d) How many people died and how many were injured as a result of the firing ?

(e) Did the S. I. receive any tangible injury ? Has any medical officer certified to his injuries ?

(f) If the answer to (c) is in the affirmative, what are the findings of such an enquiry and what action the Government propose to take in the case ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(a) It is unfortunate that the Police had to open fire in self-defence in the last week of February, 1953 in village Bassi.

Page No.6

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(b) No. The S. I. had recovered one Mst. Gulab of village Fatehpur in execution of the warrant under section 100 of the Cr. P. C. issued by the Extra Magistrate, Jaipur, and the girl had to be escorted to the court. He was prevented from doing so by a riotous mob near village Palis.

(c) Yes.

(d) 1 person died and 7 (seven) were injured.

(e) Yes. Two Contused wounds. The Medical Officer Bassi had certified to his injuries.

(f) The firing by the S. I. had been held to be justified and the findings are under examination of Government.

श्री एच. के. व्यास--Is it a fact that the S. I. has deposed in the enquiry that first he gave up his conscience and later on on regaining his conscience he opened fire ?

श्री अध्यक्ष--These are details.

श्री टीकाराम पालीवाल--The enquiry is under examination.

श्री एच. के. व्यास--When does the Government propose to complete the examination ?

श्री टीकाराम पालीवाल--Very soon.

श्री तनसिंह--क्या उन सात व्यक्तियों में से जो घायल हुए थे कोई मरा भी ?

श्री टीकाराम पालीवाल--No.

श्री अध्यक्ष--The reply was already there.

प्रश्न संख्या ५६२

श्री कस्तूरचन्द--क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) हरडा (डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा) के एक नम्बरदार, सुखदेव जाट का मार्च, १९५२ में बुरी तरह कत्ल किया गया ?

(२) उसके बदन पर कितनी चोटें लगी थीं और कितने कातिल पकड़े गये और उनका क्या हो रहा है ?

Page No.7

[श्री कस्तूरचन्द]

(३) क्या मारे जाने के पहले उसने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, कलेक्टर, एस.डी.ओ. को नोटिस दे दिया था कि चन्द बदमाश उसकी जान लेने को पीछे पड़े हुये हैं और उसकी हिफाजत का प्रबन्ध किया जावे ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने उसकी जान बचाने के लिये क्या कार्यवाही की थी ?

(५) यदि नहीं की गई तो उसमें किसकी गल्ती रही है ?

(६) क्या यह सही है कि हरडा के एस. डी. ओ. व गुलाबपुरा के थानेदार भी इस कत्ल के षडयंत्र में शामिल थे जो कत्ल की सूचना मिलते ही जान बूझ कर हेडक्वार्टर से चले गये ?

(७) क्या सरकार के पास इस संबन्ध में कई शिकायतें जनता की तरफ से आई हैं, इन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(८) यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्या सरकार अब इस सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र करने की कोशिश करेगी और करेगी तो कब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मन्त्री)—(१) हां।

(२) उसकी देह पर ४७ घाव लगे हुये थे जिनके परिणाम स्वरूप उसका ३१ मार्च, १९५२ को देहान्त हो गया। ५ अपराधियों को पकड़ा गया और एस. डी. एम. हरडा की अदालत में १९-४-५२ को चालान किया गया। सब अपराधियों को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। जहां कि उनका मुकद्मा चल रहा है।

(३) चूंकि मुकद्मा न्यायालय में विचाराधीन है अतः कोई ऐसा विषय जो कि शहादत में पश किया जाना हो प्रकट करने या विवाद करने योग्य नहीं है। सरकार उचित कार्यवाही कर रही है।

(४) नहीं।

(५) जनता की शिकायतें रद्दी की टोकरी में नहीं डाली जातीं किन्तु उचित कार्यवाही के लिये उचित अधिकारियों के पास भेजी जाती हैं।

(६) उचित कार्यवाही की जा रही है।

(७) उत्पन्न नहीं होता।

Page No.8

श्री किस्तूरचन्द--क्या माननीय मंत्रीजी बतलायेंगे कि कितने कातिल पकड़े गये और उनके नाम क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल-- पाँच कातिल पकड़े गये। उनके नाम मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न के पार्ट (६) का उत्तर नहीं आया जिसमें यह पूछा गया था कि क्या यह सही है कि हरडा के एस. डी. ओ. व गुलाबपुरा के थानेदार भी इस कत्ल में शामिल थे जो जानबूझ कर कत्ल की सूचना मिलते ही हैडक्वार्टर से चले गये ?

श्री टीकाराराम पालीवाल— यह गलत है।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री खेतसिंह—क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जोधपुर खास में मैजिस्ट्रेट्स के कितने कोर्ट्स है ?

(२) हर कोर्ट में ३१ जनवरी सन् १९५३ को कितने कितने मुकदमात जेर तजवीज थ ?

(३) क्या सरकार मुकदमात का इतना अधिक नम्बर होने पर भी जोधपुर खास की एक साथ दो कोर्ट्स एडीशनल एक्स्ट्रा सिटी मजिस्ट्रेट व एडीशनल एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, जोधपुर, की अदालतें भंग कर रही है ?

(४) यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—यद्यपि यह प्रश्न न्याय मंत्री को संबोधित किया गया है तथापि इसका ताल्लुक जी. ए. डी. से है इसलिये चीफ मिनिस्टर साहब इसका उत्तर देंगे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्रश्न संख्या ५६४

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान सरकार ने रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी समितियों के लिए किसी बैंक को आर्थिक सहायता दिलवाई है ?

श्री अमृतलाल यादव--अभी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया— अब सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—प्रयास जारी है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब तक कितनी सहायता रिज़र्व बैंक से प्राप्त हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—अभी तक कोई नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—अंदाजन कितनी रकम मिली ?

श्री अमृतलाल यादव—अंदाज आप लगा सकते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह आपके विभाग का काम है। यह तो मालूम होना चाहिये कि कितनी रकम रिज़र्व बैंक से मिली।

श्री अमृतलाल यादव—हमारी जो बातचीत रिज़र्व बैंक से हुई है उसके अनुसार रिज़र्व बैंक ने १५ लाख रुपये देना मंजूर किया है।

प्रश्न संख्या ५६५

श्री सुगनचन्द जैन—क्या उप-मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) चित्तौड़ में पंचवर्षीय योजना में कहां पर सड़क बनाई जावेगी ?

(ख) क्या उसमें चित्तौड़ से बून्दी तक सड़क बनाने की योजना है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक इसका कार्य चालू हो जावेगा ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) पंचवर्षीय योजना में चित्तौड़ जिले की निम्नलिखित सड़क के बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया :—

(१) चित्तौड़ से उदयपुर सड़क के कच्चे भाग को पक्का करना।

(२) नसीराबाद से निम्बाहेड़ा के कच्चे भाग को पक्का करना।

(३) बून्दी से चित्तौड़ तक की सड़क के जीर्ण भाग को पक्का करना।

(४) सिघाली से बिछार की सड़क के भाग को पक्का करना।

(५) बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ की सड़क को पक्की मुड़ की सड़क बनाना।

(६) उदयपुर, सालूम्बर, धारयावाद, प्रतापगढ़ की सड़क के कच्चे भाग को पक्की व मुड़ की सड़क बनाना।

(७) बारबास से सिघोली मंसूरगढ़ होती हुई पक्की सड़क।

(८) मंगलवाड़ा निम्बाहेड़ा मुड़ की सड़क।

(९) चित्तौड़ कपासिन रोड।

(१०) प्रतापगढ़, अरनोद पीपलोदा मुड़ की सड़क का निर्माण।

(११) छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी तक पक्की सड़क।

(ख) वर्तमान फेयरवेदर सड़क के खराब भागों को पक्का बनाने का कार्य योजना में लिया गया है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार से द्रव्य मिल गया तो सन् १९५३-५४ में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—(अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल—उदयपुर के बारे में तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री गंगासिंह—Will the Home Minister be pleased to state :

What investigation has been made by the Police so far in the case where two guns were stolen from Nagaur Town ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Two guns belonging to the Hon'ble Member who has put this question were reported to be stolen in his absence from his house. A case was registered in Police Station on 16-7-52. Police have not been able to find any clue of theft or the stolen property. The case has been finally reported as untraced.

प्रश्न संख्या ५६७

श्री गंगासिंह—Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) How many constables have been deputed at Police Chawki Kuchera, Tehsil Nagaur ?

(b) What are the names of these constables and since when they are serving there ?

(c) Is it a fact that a constable named Mohanram resident of the same village Kuchera is being kept there for the last three years ? If so, what is the reason for that ?

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—

(क) एक हैड कॉन्स्टेबिल और ६ कान्स्टेबिल ।

(ख) उनके नाम व नियुक्ति की तारीखें इस मुजब हैं :—

(१)	हैड कॉन्स्टेबिल गुमानसिंह	१७-९-४९
(२)	कॉन्स्टेबिल मोहनराम	१७-११-४८
(३)	कां० बिरधाराम	२६-४-५२
(४)	कां० नाथूसिंह	दिसम्बर १९५२
(५)	कां० रूपराम	दिसम्बर १९५२
(६)	कां० जस्सूखां	दिसम्बर १९५२
(७)	कां० गोविन्दसिंह	२७-३-५२

(ग) हां, उसकी वहां उपयोगिता है ।

Page No.11

श्री गंगासिंह--श्री मोइनराम कितने अर्से वहां है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--१७-११-१९४८ से । मैं अपने उत्तर में यह बता चुका हूँ ।

श्री गंगासिंह--४८ के बाद उसका वहां से ट्रान्सफर क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से वहां रक्खा गया है ।

श्री गंगासिंह--जो जिस गांव का है उसको वहीं रक्खा जा सकता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--नहीं रखने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री गंगासिंह--ज्यादातर एक ही आदमी को उन्ही के गांव में रक्खा जाना क्या सरकार अनुचित नहीं समझती ?

श्री टीकाराम पालीवाल--जिसकी जहां उपयोगिता समझी जाती है उसे वहीं रक्खा जाता है ।

श्री गंगासिंह--क्या यह सच है कि उनको वहां इसलिए रक्खा जा रहा है कि वे माननीय शिक्षा मंत्रीजी के साले हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल--यह सही नहीं जैसा कि आप बतला रहे हैं ।

श्री गंगासिंह--अगर सही होगा तब तो उनको वहां से हटा दिया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल--यह फैक्ट नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सरकार जांच तो कर ले कि यह फैक्ट है या नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा--मैं इस मामले को जरा साफ........

(हंसी)

श्री मानसिंह महार--सरकार इन सालों की बीमारी का क्या इलाज करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल-- पीड़ित और उत्पीड़ित दोनों का इलाज होगा ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री तेजसिंह ।

प्रश्न संख्या ५६८

श्री तनसिंह--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि बाड़मेर में बनस्पति घी की खुले आम बिक्री होती है ?

(२) यदि हां, तो सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री भोलानाथ--(१) कस्टम टैरिफ की आइटम संख्या ३४२ (अ) के अनुसार बनस्पती घी के आयात पर प्रतिबन्ध है और बाड़मेर में बनस्पती घी की बिक्री भी गैर कानूनी है।

(२) चोरी से बनस्पति घी लाने वाले व्यक्तियों को मय माल गिरफ्तार किया जाता है और उनके प्रति कानूनी कार्यवाही की जाती है। ऐसे मुकदमात में गिरफ्तारी के लिये विभागीय कर्मचारी और एन्टी स्मगलिंग फोर्स सतर्कता से काम कर रही है।

श्री खेतसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रिफाइन्ड कोकोनट ऑइल भी बनस्पति घी में शामिल है या नहीं ?

श्री भोलानाथ--नहीं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--जोधपुर में जगह जगह जो नकली घी आ रहा है और जो घी की तरह उपयोग में आता है उस घी पर प्रतिबन्ध है या नहीं।

श्री भोलानाथ--बनस्पति घी पर प्रतिबन्ध है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--लेकिन यह घी जैसी वस्तु है, पर नाम बनस्पति न देकर दूसरा दे दिया है उस पर प्रतिबन्ध है या नहीं ?

श्री भोलानाथ--इसके बारे में सेण्टर के इण्डस्ट्री विभाग और राजस्थान के इण्डस्ट्री विभाग द्वारा भी कुछ नियम और स्पेसिफिकेशन बनाये हुए हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया द्वारा उन चीजों का एनेलाइसिस भी किया हुआ है। उसमें सम्मिलित पदार्थ ही बनस्पति घी के नाम से हैं और उन पर प्रतिबन्ध है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट। श्री नारायण चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या ५६९।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

Page No.13

प्रश्न संख्या ५७०

श्री गंगासिंह—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that the villagers of village Kuchera, Tehsil Nagaur are being harassed by the Police stationed at Mundwa on political grounds?

(b) If so, what action the Government is going to take?

श्री टीकाराम पालीवाल—(उप-गृह मंत्री)—(क) ऐसी कोई शिकायत पुलिस मन्डवा के खिलाफ नहीं गुजरी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गंगासिंह—क्या यह सही नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट आई थी सरकार के पास और इस बहुमत पार्टी के पास भी।

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री गंगासिंह।

प्रश्न संख्या ५७१

श्री गंगासिंह—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that no Rajput police Sub-Inspector is being kept in Nagaur District on political grounds?

(b) How many Rajput Sub-Inspectors are serving in Nagaur District at present and out of them how many are in Nagaur Tehsil?

(c) How many other Sub-Inspectors of different communities are there in Nagaur District and out of them how many are in Nagaur Tehsil?

श्री टीकाराम पालीवाल—(अ) यह गलत है कि पोलिटिकल मामलात पर राजपूत सब इंसपेक्टर इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रक्खा जाता है।

(ब) इस समय इस डिस्ट्रिक्ट में चार राजपूत सब इन्सपेक्टर तैनात हैं जिनमें से २ नागौर तहसील में तैनात हैं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(स) राजपूतों के अलावा ३४ सब इंसपेक्टर हैं जिनमें ५ पी. एस. आई. शामिल हैं। अलग २ जाति के निम्नलिखित हैं। इन ३४ में से १५ अन्य जातियों के हैं जो नागोर तहसील में तैनात हैं।

तहसील	जाट	राजपूत	मुसलिम	ब्राह्मण	दीगर
नागोर	४	२	१	४	६
डीडवाना	१	१	०	२	२
मेड़ता	२	०	१	१	२
परबतसर	०	०	०	३	१
नांवा	०	१	०	२	२
योग	७	४	२	१२	१३

श्री गंगासिंह—जिन ४ राजपूत सब इंसपेक्टर्स का जिक्र किया गया है इनमें पुलिस थाने के इंचार्ज कितने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—थानेदार आमतौर पर थाने के इंचार्ज होते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री गंगासिंह ।

प्रश्न संख्या ५७२

श्री गंगासिंह—Will the Home Minster be plesed to state—

How many cases of corruption among Government servants were finally decided by Law Courts during the last one year and with what results ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) सिर्फ ४

(ख) विवरण इस प्रकार है—

(१) स्टेट बनाम रामस्वरूप पेशकार

निजामत तोरावाटी········बरी हुआ ता० १६-५-५२ को।

(२) स्टेट बनाम गोरधनसिंह एस. आई.

··· बरी हुआ ता० २५-५-५२ को। डिपार्टमेन्टल जांच हो रही है।

(३) स्टेट बनाम गोरधनलाल ए. एस. आई. ······ बरी हुआ ता० २२-१२-५२ को।

Page No.15

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(४) स्टेट बनाम भंवरलाल, क्लर्क जयपुर म्युनिसिपैलिटी ...... बरी हुआ ता० २६-१२-५२ को ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the Government given any consideration to this phenomena where all cases put up before the courts have been acquitted ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No, all the cases are not acquitted. Only some cases are acquitted. The Government has given serious consideration to it and has regretfully come to the conclusion that generally this is due to the fact that people who come farther to make evidence in the beginning usually eventually collide with the accused.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the Government taken care to find out, whether their Officers are keen in the beginning but they also become less particular in such matters ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It may be so in some cases.

श्री एच. के. व्यास—Then what steps do the Government intend to take to proceed with these cases more vigorously and more successfully ?

श्री टीकाराम पालीवाल—They have been issued instructions to take more strict steps.

श्री अध्यक्ष—Next. Shri Tan Singh,

प्रश्न संख्या ५७३

श्री तनसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बाडमेर तहसील व शिव तहसील में क्या आबादी है ?

(२) उक्त तहसीलों में कितने अस्पताल और आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) बाडमेर व शिव तहसील की आबादी क्रमश: २८६०१८ और ४५०४५ है ।

(२) बाडमेर तहसील में एक डिस्पेन्सरी है और जसोल नाम का आयुर्वेदिक एड पोस्ट औषधालय है । तहसील शिव में अभी तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं खोली गयी है परन्तु खास ग्राम शिव में एक औषधालय है ।

Page No.16

श्री खेतसिंह—क्या सरकार तहसील शिव में नया अस्पताल अथवा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निश्चय कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अभी बताया कि औषधालय शिव ग्राम में है ।

श्री सन्तोषसिंह—इस अस्पताल के साथ इन्डोर पेशेन्टों की भरती करने की भी व्यवस्था है ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं ।

प्रश्न संख्या ५७४ (३८ आर. आर. एम.)

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) श्री चीफ कन्जर्वेटर ने सन् ५२ में किन किन स्थानों का किन किन कारणों को लेकर भ्रमण किया ?

(ख) उपर्युक्त भ्रमण किन किन स्थानों पर मोटर से कहां से कहां तक एवं ट्रेनों में किन किन स्थानों पर किया ?

(ग) उपर्युक्त भ्रमण में कितना रुपया वर्ष भर में खर्च हुआ ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इन भ्रमणों में अधिकतर कार्य शिकार करने का था ?

श्री अमृतलाल यादव (वन विभाग)—मुझे अभी तक इस सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः सूचना प्राप्त होने पर उसको टेबल पर रखा दूंगा ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रोशनलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने यह प्रश्न सेशन के शुरू होने से पूर्व ही भेज दिया था और जिसको काफी समय भी हो चुका है । ऑफिस से भी माननीय मंत्रीजी के पास सूचना पहुंचे काफी समय होगया है । कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्रीजी सूचना क्यों नहीं दे पा रहे हैं ? मुझे तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इतने समय के पश्चात् भी इस प्रश्न का उत्तर न दिया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—This Question was tabled on 18-2-53. and today is 20-3-53.

(चुप्पी)

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, तो इस प्रश्न के बारे में क्या हुआ ?

Page No.17

श्री रोशनलाल शर्मा--मैं इस प्रश्न को टेबिल पर नहीं रखा कर इस हाउस में ही इसके बारे में जानना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी से, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में समय ले लिया जाय कि वे कब इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)--एक-दो दिन में मैं इसका जवाब दे दूंगा।

श्री रोशनलाल शर्मा--एक दो तो तीन होते हैं।

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)--मैं इसका जवाब नेक्स्ट टर्न पर दे दूंगा।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--अगर इस बीच में केबिनेटरीसफल होगई तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष--Reply will Come.

श्री टीकाराम पालीवाल--(उप-मुख्य मंत्री) यह व्यवस्था की जा सकती है कि पर्टिक्युलर मंत्री को जवाब देने के लिए हाजिर रहें।

(मंत्रीमण्डल में सम्भावित परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए "तो उनको आश्वासन दे दिया गया है" ऐसी हाउस में आवाज)

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--
(प्रश्नकर्त्ता की ओर संकेत करते हुए)
इन्हें आश्वासन दिया गया है।

प्रश्न संख्या ५७५

श्री गंगासिंह--Will the Home Minister be pleased to state—

(a) How many complaints of the use of third degree methods by police came to the notice of the Government during the last one year ?

(b) How many of such cases were inquired into and with what results ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)-- (a) 42.

(b) Out of the above, 17 were challaned, 10 proved false and 15 are pending investigation. Out of the cases challaned 4 have been discharged and remaining are still subjudice.

Page No.18

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५७६ (७२ डी. वाइ. सी. एम.)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister Incharge for Home be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that the sum of Rs 10 lacs lying as fixed deposit in the Jaipur Bank Ltd. into the credit of Late Shri Prithi Singh of Baria, was paid on the morning following his death in an air accident ?

(b) Is it a fact that the son of the late Shri Prithi Singh of Baria namely Shri Digvijay Singh objected to it as a forged payment ?

(c) Has the police conducted any investigation in this case ?

(d) What is the finding of the investigating Officer ?

(e) What steps has the Government taken to punish the guilty.

श्री टोकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मन्त्री)—(a) Yes

(b) This is being investigated.

(c) As above.

(d) The invstigation has not yet been concluded.

(e) Does not arise.

(f) Does not arise.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ५७७ (८१ एल. एम.)

श्री घासीराम—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तिजारा, जिला अलवर, के डाक्टर की जो शिकायत जनता द्वारा हुई थी, उसकी जांच का क्या नतीजा रहा ?

(२) जिस अधिकारी ने यह जांच की थी क्या वे डाक्टर साहब के मकान पर नहीं ठहरे और उनके मकान पर खाना नहीं खाया ।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) डाक्टर तिजारा औषधालय के विरुद्ध जांच जनता द्वारा की गई शिकायत पर कराई गई थी और उसमें शिकायतें साबित नहीं हुई । फिर भी राजस्थान सरकार के आदेश नं० २५१, एम. एच. ता० २-२-५३ के अन्तर्गत तिजारा से स्थानान्तिरण कर दिया गया है ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(३) डी. एम. एच. ओ., अलवर, ने इस सम्बन्ध में जांच की थी और वे डाक्टर के पास ठहरे थे और खाना खाया था।

एक सदस्य--जब जांच से शिकायतें साबित नहीं हुई तो उनका स्थानान्तरण क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री)--ट्रान्स्फर की जांच साबित होने व न होने से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या ओब्लाइज (Oblige) करने के लिए ट्रान्सफर किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री)--ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५७८ (आर. आर. एम.)

श्री रोशनलाल शर्मा--क्या मंत्री, वन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) श्री डूंगरपुर महारावलजी को कौन कौन से जंगल निजी संपत्ति में दिए गए हैं ?

(ख) क्या इस प्रकार राजस्थान में अन्य राजाओं को भी जंगल दिए गए हैं ? हां, तो किन किन को ?

(ग) राजाओं के उन जंगलों पर राजस्थान सरकार का फोरेस्ट एक्ट लागू है या नहीं ? नहीं तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)--पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः इसका भी जवाब मैं अगली टर्न में दे दूंगा।

(उत्तर बाद में प्राप्त हुआ-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरिदेव जोशी--अध्यक्ष महोदय यह एक जरूरी प्रश्न है और इसका जवाब हम आज ही चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)--मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से भी है और वहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई है; अतः सूचना आने पर मैं आपको बता दूंगा।

Page No.20

श्री हरिदेव जोशी--अध्यक्ष महोदय, जंगलों के नाम तो राजस्थान सरकार के पास है। केन्द्रीय सरकार से क्या जंगलों के नाम प्राप्त करने को है ?

श्री अध्यक्ष--When the questions have once been admitted and so far as this question is concerned, this was admitted on the 18th February, i.e., a notice was given clearly more than one month ago - it is expected that their reply should come on the day for which they are tabled. However, they can also be taken on the next turn.

श्री हरिदेव जोशी--अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार से इस प्रश्न को टालने की वृत्ति नहीं कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--We can give some more time.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि इसका ताल्लुक पोलिटिकल डिपार्टमेंट से पड़ता है और बहुत अच्छा होगा कि इसके लिए थोड़ा और वक्त दे दिया जाय ताकि पोलिटिकल डिपार्टमेंट से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके। राजाओं के नाम कौन कौन से जंगल हैं इसकी सूचना पोलिटिकल डिपार्टमेंट ही जंगलात डिपार्टमेंट को देता है। अतः इसके लिए थोड़ा अधिक वक्त और दे दिया जाय, टालने का तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी--अध्यक्ष महोदय, एक माह पूर्व यह प्रश्न पूछा गया था और पोलिटिकल डिपार्टमेंट से इस बीच में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता था और इसका जवाब दिया जा सकता था।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--प्रश्नकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वे सम्बन्धित विभागों से ही प्रश्न पूछें।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Mr. Speeker, Sir, I think a more categerical statement should be given on this question because it is provided for in the rules that the Speaker may direct that a question be placed on a list of questions for answer on a day later than that specified by a Member in his notice if it is known that a longer period is necessary etc. Now my point is, if at any stage the Minister concerned begins to feel that it may not be possible to get the answer on the stipulated day, then what is required of him in the least is that he should take care to approach the Hon'ble Speaker and get it placed for answer later on. In this case I think a sufficiently long time was given and the Member-in-charge concerned must have approached the Hon'ble Speaker so that the question could be placed for answer on a later date for reply.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)--On a point of explanation, Sir, the question of allotment of forests to Rulers is a subject reserved for the

Page No.21

[श्री जयनारायण व्यास]

Political Department which corresponds with the States Ministry because the final allocation was made or was to be made in consultation with the State Ministry, as has been pointed out by my colleague that this question is the subject of correspondence between the States Ministry and the Government of Rajasthan. The Political Department will have to look into this matter, and I wanted ample time because so far as I know this question was never put to the Political Department. I do not know at what stage the question is. So I may draw the attention of the House to Rule 27 in which it is clearly laid down that the notice of a question shall be given in writing to the Secretary and shall specify the official designation of the Minister to whom it is addressed. It has been addressed to the Forest Minister, but later on it is found that there are points which have to be referred to the Political Department because of the relationship of the States Ministry with the Government of Rajasthan. As such I think it is not to evade the issue; but in order to facilitate the giving of a complete reply that I request, sir, is that the question may be postponed only to the next question-day of the Forest Minister. But I want to inform the House that at least 10 days time is required for the Political Department to look into the matter and give a complete reply. Otherwise the reply may not satisfy the Hon'ble Members who put the question.

श्री हरिदेव जोशी—मुझे खेद के साथ निवेदन करना है कि जो कुछ भी मैं इस सबसे समक्ष पाया हूं और जिसे नम्र से नम्र भाषा में अगर कहूं तो माननीय मन्त्री को शील्ड किया जा रहा है।

अगर हम यह भी देखें कि पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट और स्टेट्स मिनिस्ट्री को भी पूछना आवश्यक है तो वह भी केवल यह बात हो सकती है कि डूंगरपुर महारावल को कौन कौन से जंगल निजी सम्पत्ति में दिये गये हैं। बाकी सब नाम और संख्या राजस्थान सरकार के पास है। इसके बाद में कोई चीज स्टेट मिनिस्ट्री के सम्बन्ध की नहीं रह जाती है। सवाल यह है और बहुत अहमियत का है कि आज जंगल नष्ट किये जा रहे हैं। डूंगरपुर महारावल द्वारा तेजी से जंगल काटे व बरबाद किये जा रहे हैं। अगर जो होरहा है उसको जल्दी से नहीं रोका गया तो सब जंगल काट दिये जावेंगे। सरकार को इस पर शीघ्र ही गौर करना चाहिये।

श्री मानसिंह (जमु. राम.)—माननीय अध्यक्षजी, प्रश्नों के इस तरह के जवाबों का हमें कटु अनुभव है और यह तो रोजमर्रा की चीज हो चुकी है। पार्लियामेन्ट में तो इसे देखकर यह रूलिंग दिया गया है चेयर की ओर से कि अगर कोई मन्त्री प्रश्नों का उत्तर प्रश्न-काल में नहीं देता है तो उसे उसी

[श्री मानसिंह]
दिन सेशन खतम होने तक जवाब देना पड़ता है। उसी चीज को यहां भी एडॉप्ट कर लिया जावे तो अच्छा हो।

श्री जयनारायण व्यास--मैं समझता हूं जवाब दे दिया गया है। चूंकि यह मामला पोलिटिकल विभाग से और स्टेट मिनिस्ट्री से भी सम्बन्ध रखने वाला है और इस बारे में स्टेट मिनिस्ट्री से कॉरस्पोन्डेन्स हो रही है ; यह जवाब है। अगर इस जवाब से सन्तोष नहीं होता है तो बात दूसरी है। इसमें भी टाइम सेव करने की दृष्टि से माननीय सदस्य को केवल इस विभाग को ही नहीं किन्तु सम्बन्धित पोलिटिकल विभाग को भी, प्रश्न पूछते समय, सूचना दे देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—What is desirable for the Treasury Benches is that if a question is likely to take a longer time than is prescribed under the rules, they should intimate to this office so that we might defer the date fixed for the question and the time of the House may be saved and matters may be expedited. This is one thing.

So far as the present question is concerned, what I can gather from the nature of this question is that it was perfectly within the jurisdiction of the Government to have kept a record of forests which were given as personal property of His Highness the Maharawal of Dungarpur and to give a reply. Any way, if there is any difficulty they will look sharp and will reply to the question in the next turn.

(विरोधी दल की ओर से हर्ष-ध्वनि)

प्रश्न संख्या ५७६

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचन्द्र।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५८०

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष--श्री मुक्तिलाल मोदी—

प्रश्न संख्या ५८१

श्री मुक्तिलाल मोदी— क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

कोटपूतली में जेल रखने से शाहपुरा के मुकाबले में क्या कम खर्च पड़ेगा?

Page No.23

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं। जहां तक कर्मचारियों के वेतन व कैदियों के भोजन आदि का प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not audible, Sir.

श्री मुक्तिलाल मोदी—आपने कर्मचारियों एवं भोजन आदि के प्रबन्ध के खर्च का तो जिक्र किया पर कैदियों को यहां लाने और लेजाने आदि में क्या खर्च होता है यह भी बताने की कृपा करें ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जयपुर से ले जाने और लाने का खर्चा शाहपुरा से कोटपूतली में ज्यादा पड़ता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो शाहपुरा में फिर जेल क्यों नहीं रक्खी जाती ? खर्च का कितना फरक होगा यह बताने की कृपा और करें ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किस चीज का खर्च ? कैदियों को लाने ले जाने का खर्च ? यह शाहपुरा में कम था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शाहपुरा से अब कोटपूतली में कितना ज्यादा हो गया है यह पूछ रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—एक का भी बता दीजिये फिर मालूम पड़ जावेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—जयपुर से शाहपुरा १ रुपया ९ आने फी सवारी तथा जयपुर से कोटपूतली ३ रुपया ७ आने फी सवारी किराया लगता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो इस हिसाब से एक साल का अन्दाज लगाया जावे तो दूने से भी ज्यादा खर्च कैदियों के लिए इसमें होगा।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—One more supplementary question, Sir. In view of the fact that extra expenditure will have to be incurred, will it not be desirable for the Government to shift the headquarters and locate it at the earlier place ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! This is completely a separate Question.

प्रश्न संख्या ५८२

Next, Sri Sangram Singh.

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

Shri Sajjan Singh.

प्रश्न संख्या ५८३

श्री सज्जनसिंह—Will the Minister for Rehabilitation be pleased to answer:—

(a) How much amount out of the provision of Rs. 1,20,40,000/- in the Budget for 51-52 under the Head "Advances to displaced persons" has been utilised ?

(b) How much, uptil now, has been realised against the advances made to displaced persons?

(c) What specific steps have been taken to ensure the realisation of the advances ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःसंस्थापन मंत्री)—(a) The correct amount of budget Estimates for loans and Advances by the State Government is Rs. 1,25,40,000/- in the revised budget Estimates for 1951-52. The above sum included Rs. 83,40,000/- for Rehabilitation loans. Out of the latter sum a sum of Rs. 60,80,553-14-3 was utilised, the details of which are as follows—

Housing.	16,21,618- 0-0
Rural.	34,26,256- 4-3
Urban.	10,32,672-10-0
	60,80,552-14-3

(b) A sum of Rs. 11,67,896-11-3 has been realised from the Displaced Persons against the Loans and Advances to them.

(c) The following steps have been taken to ensure the realisation of the advances:—

(i) The work regarding recovery of the rural loans has been transferred to Revenue Department for making recoveries of the instalments of loans along with the land revenue.

Page No.25

(ii) A supervisory Organisation has been set up to arrange for the periodical inspection of the accounts of recoveries and ensure that prompt steps are being taken wherever slackness on the part of officials is noticed.

(iii) The Central Government had recently ordered that loans outstanding against the Displaced persons can be adjusted against their verified Claims for Compensation of property left in west Pakistan.

श्री सज्जनसिंह—६० लाख रुपये खर्च किये गये; बाकी बचे लगभग ६० लाख रुपयों का क्या हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य ने पूछा था कि रिकवरी के लिए क्या किया गया, उसका मैंने उत्तर दिया। तब रकम इतनी क्यों दी गई बाकी कैसे बची इसके लिए कहना है कि रिटर्न होने का खयाल करके रकम उधार दी जाती है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करने पर ही रकम उधार दी जाती है; पानी में नहीं फेंकी जाती।

श्री सज्जनसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न तो यह है कि ६० लाख रुपये उधार दिये गये बाकी ६० लाख रुपयों का क्या हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने इसका अभी जवाब दिया है कि रुपया पड़ा है।

श्री सज्जनसिंह—मेरा प्रश्न है कि जो रुपया बच रहा है वह आपके पास डिपॉजिट पड़ा है, खर्च हो चुका है या लेप्स हो चुका है; क्या हुआ है ?

श्री अमृतलाल यादव—वह तो बचा ही है।

श्री अध्यक्ष—What happened to Rs. 60,00,000 ?

श्री अमृतलाल यादव—That is now diposited with the Government.

श्री सज्जनसिंह—सन् ५१, ५२ में १ करोड़ २० लाख रुपये की स्वीकृत रकमों में से ६० लाख रुपया ही खर्च हुवा तो क्या सरकार यह समझती है कि विस्थापितों की तरफ से इस रकम को लिए जाने के लिए कोई डिमान्ड नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने कहा कि उनकी तरफ से डिमान्ड्स कितनी हैं इसका कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वह रुपया जिसको उधार दिया जाता है उसकी वापिसी की शर्तें वह पूरा करता है या नहीं ? इन शर्तों के माफिक ही रुपया दिया जाता है और जो रुपया बच जाता है वह सरकार के पास रह जाता है। साल खत्म हो जाने पर वह रकम लेप्स हो जाती है यह आम बात है सभी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट । श्री तेजपाल ।

प्रश्न संख्या ५८४.

श्री तेजपाल—क्या उपमुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में पंचवर्षीय और कम्युनिटी प्रोजेक्ट से संबन्धित योजनाएं किन किन स्थानों पर चालू की गई हैं ?

(ब) उनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं ?

(स) कितनी आधी पूरी हो चुकी हैं ?

(द) शेष के कब तक पूरे होने की संभावना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मन्त्री)—(a) Community Project schemes have been selected in Rajasthan at the following Places—Alwar, Baran, Dungarpur, Hindaun, Raisinghnagar, Rajsamand and Sumerpur.

(b) None of them has been completed.

(c) None of them have been half-completed.

(d) It is hoped that these will be completed by March, 1955.

श्री मानसिंह—सब से ज्यादा रुपया कौनसे प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सब जगह बराबर खर्च किया जाएगा ।

एक सदस्य—क्या भरतपुर का इसमें नम्बर नहीं है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—जिन जिन के नम्बर थे उनके नाम मैंने आपके सामने पढ़ कर सुना दिये हैं ।

श्री कंवरलाल जेतिया—इन स्थानों के अलावा क्या सरकार का इरादा और ब्लॉक्स कायम करने का है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह निश्चित नहीं हुवा है । संभवतः ३—४ ब्लॉक्स और हो जावें । इस संबन्ध में बात चीत चल रही है ।

श्री कंवरलाल जेतिया—इसकी कब तक आशा की जा सकती है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—जल्दी से जल्दी ।

श्री मानसिंह—क्या डूंगरपुर में बांसवाड़ा भी शामिल है या ये दोनों अलग अलग हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दोनों अलग अलग हैं।

श्री खेतसिंह—जिन स्थानों के लिये बातचीत चल रही है उनके लिये सिलेक्शन होकर स्थान निश्चित कर दिये गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

एक सदस्य—संबन्धित योजना किस आधार पर कार्यान्वित की जाएगी।

श्री टीकाराम पालीवाल—इस सम्बन्ध में एक से अधिक बार बताया गया है।

एक सदस्य—आपने फरमाया कि चार और क्षेत्र सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिये क्या कोई कमेटी मुकर्रर की जावेगी जिसमें सभी जगहों के सदस्य होंगे या सभी जयपुर डिविजन से ही लिये जावेंगे, जैसा कि सुनते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा सुनते ही सुनते हैं लेकिन कोई आधार नहीं है।

अध्यक्ष— नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ५८५

श्री तेजपाल—क्या उप-मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सच है कि जयपुर कमिश्नरी में महुवा क्षेत्र में जो गांव पंचवर्षीय योजना के तहत आधुनिक ग्राम निर्माण के लिये निश्चित किये गये हैं उनके बीच में उसी कमिश्नरी के भरतपुर जिले के जो गांव हैं उनको उस योजना में से छोड़ दिया गया है ?

(आ) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(अ) बीच में कोई ऐसे गांव नहीं पड़ते।

(आ) उत्पन्न नहीं होता।

एक सदस्य—क्या यह सही है कि माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं उनकी संख्या १७० है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री कस्तूरचन्द—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) स्थानीय सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जो केन्टीन (दुकान) है उसको खोलने की इजाजत किस सिद्धान्त पर दी गई है ?

Page No.28

[श्री कस्तूरचन्द]

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इस दुकान में जयपुर के बाजार के मूल्य से ज्यादा देना पड़ता है।

(३) क्या सरकार दूसरी और दुकान खोलने की इजाजत के विषय में सोच रही है और उसमें दवाइयां भी बेचने की इजाजत दी जायेगी ? अगर हां, तो क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) सवाई मानसिंह अस्पताल में विश्रान्ति गृह (केन्टीन) इस उद्देश्य से चालू किया गया था कि अस्पताल के निरीक्षकों तथा रोगियों के सम्बन्धियों को जिनको कि उनके साथ अस्पताल में रहने की आज्ञा दे दी जाती है वहां से जलपान सामग्री की वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

(२) वस्तुओं पर बाजार से अधिक मूल्य लेने की कभी कोई खास शिकायत नहीं आई।

(३) सरकार ने जनता की मांग पर एक दूसरा केन्टीन जिसमें आवश्यक दवाइयां भी रखी जावेंगी सर्व साधारण की सुविधा के लिये और खोलने की आज्ञा दी है।

श्री सन्तोषसिंह—और भी कोई दुकान वगैरह खोलना चाहे तो क्या सरकार उसको इजाजत देगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस सम्बन्ध में दरख्वास्त आने पर विचार किया जायगा।

श्री मोतीलाल—क्या इस दुकान के लिये कोई टेन्डर्स मांगे गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—टेन्डर्स नहीं मांगे गये क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी।

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार ने हॉस्पिटल के अधिकारियों से पूछ कर दुकान देने का फैसला दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, हॉस्पिटल के अधिकारियों की राय ली थी।

श्री एच. के. व्यास—क्या हॉस्पिटल के अधिकारियों की राय इसके पक्ष में थी या विपक्ष में ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप कौनसी दुकान के लिये पूछते हैं ?

श्री एच. के. व्यास—अभी मौजूदा दुकान है उसके लिये पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास—अधिकारियों की राय विपक्ष में नहीं थी।

श्री एच. के. व्यास—क्या जिन व्यक्तियों को दुकान दी गई है वे माननीय मंत्री महोदय के सम्बन्धियों में से हैं ?

Page No.29

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने तो उनकी शक्ल ही पहले बार देखी थी जब वे आए थे।

श्री भैरू सिंह—क्या इसके लिये हॉस्पिटल कम्पाउन्ड में कोई मकान भी बनाया जा रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास—(अश्रव्य)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इस प्रकार की मांग किसी दूसरे व्यक्ति ने भी की?

श्री रामकिशोर व्यास—सबसे पहले इन्होंने ही मांग की।

श्री सन्तोषसिंह—क्या इस दुकान पर दवाइयें कन्ट्रोल रेट से बिकेंगी?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, कन्ट्रोल रेट से बिकेंगी और सरकार का नियन्त्रण रहेगा। इसके लिये एक एग्रीमेन्ट लिखा गया है।

प्रश्न संख्या ५८७

श्री कस्तूरचन्द—क्या व्यापार तथा व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा के असिस्टेण्ट माइनिंग इन्जिनीयर ने मांडिल के एक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर का अभ्रक पिछले तीन महीनों से निर्यात करने से रोक रखा है, जिसका कारण यह बताया गया कि यह उत्पादित अभ्रक अन्य एरिया का है?

(२) क्या यह सच है कि इसकी जांच करने के लिये माइनिंग विभाग भीलवाड़ी द्वारा दो अधिकारी भेजे गये थे जिनकी जांच की रिपोर्ट एक दूसरे के बिलकुल विपरीत है?

(३) क्या इसकी जांच की रिपोर्ट स्पष्ट न होने से माइनिंग विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने पुनः जांच की है?

(४) इस प्रकार के निर्यात को रोकने से सरकार को कितनी हानि हुई है?

(५) इन गलत कार्यवाहियों से मध्यम श्रेणी के अभ्रक के व्यापारियों को जो नुकसान होता है तथा मजदूर बेकार होते हैं, इस असन्तोष को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) हां।

(२) हां।

(३) भीलवाड़ा स्थित स्थानीय खनिज अधिकारी ने अध्यक्ष, खनिज व भूगर्भ विभाग राजस्थान को इस विषय में अपनी राय भेज दी है जो विचाराधीन है।

Page No.30

[श्री रामकिशोर व्यास]

(४) सरकार को कोई हानि नहीं हुई। अब तक की प्राप्त सूचनाओं से यह विदित हुआ है कि सामान अनधिकृत स्थान से चोरी-छिपे निकाला गया है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक सदस्य—क्या पहले भी ये लोग इस प्रकार का कार्य करते हुए पकड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—ये तो अक्सर पकड़े जाते रहते हैं।

एक सदस्य—क्या यह सही है कि दोनों अधिकारी जो जांच करने के लिये गये व उन्होंने भिन्न भिन्न रिपोर्ट्स पेश की हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, यह सही है।

श्री रामदयाल—पहली जांच रिपोर्ट मंजूर क्यों नहीं की गई और दूसरे अधिकारी को जांच करने के लिये क्यों न भेजा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—पहले दूसरे आदमी को भेजा था इस बात की सर्वे करने के लिये कि आया अभ्रक अन्य एरिया के बाहर से खोदा गया है क्योंकि शिकायत यह थी कि अभ्रक पर्टिक्युलर एरिया के बाहर से खोदा गया। उसकी रिपोर्ट थी कि एरिया के बाहर से खोदा गया है। दूसरे ने रिपोर्ट की कि कुछ अभ्रक एरिया के बाहर से खोदा गया है और कुछ इसी में से है।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि माइनिंग इन्जीनियर तीन साल तक ब्राइबरी के केस में सस्पेण्ड रहा था ?

श्री रामदयाल—क्या इस प्रकार अनऑथोराइज्ड तरीके से माइका एक्सपोर्ट की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो जांच के निर्णय के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री एच. के. व्यास—संबन्धित अधिकारी पर यदि आरोप सच पाये गये तो क्या सरकार उसे हटा कर दूसरे अधिकारी को भेज कर उसका फैसला कराने के लिये तैयार है।

श्री रामकिशोर व्यास—जब अधिकारी को चार्ज से बरी कर दिया जाता है तो फिर हटाने का सवाल नहीं उठता।

श्री एच. के. व्यास—जब दोनों अधिकारियों में आपस में मतभेद है तो क्या सरकार ज्यादा जिम्मेवार अधिकारी को भेज कर इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मैं कहता हूँ।

श्री एच. के. व्यास—आपका जवाब "हां" में है क्या

श्री रामकिशोर व्यास—हां, मेरा जवाब "हां" में है।

(विराम)

एक प्रश्न जिसका उत्तर मैंने कल नहीं दिया था उसका उत्तर यदि आपकी आज्ञा हो तो दे दूं। वह प्रश्न नं० ५४८ श्री गंगासिंह का था।

श्री गंगासिंह—Will the Law Minister be pleased to state :—

(a) How many officers were detected indulging in malpractices in the last General Elections?

(b) In how many of such cases proper inquiries were held and with what results?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—There were no officers detected in malpractices in the last General Elections.

(b) The question does not arise in view of the above reply.

श्री अध्यक्ष—Question No. 555. Shri Moti Ram if he wants an answer.

(विराम)

No.

(विराम)

The question hour is over. We come to the Legislative business then.

विधान कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५३

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "that the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1953, be taken into consideration."

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

Then question is "that the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1953, be taken into consideration."

(स्वीकृत)

I think the House does not want to discuss the Appropriation Bill.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--Sir, I beg to move "that the Bill be passed."

श्री अध्यक्ष--The question is "that the Bill be passed."

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

The Bill is passed.

आय-व्ययक पर सामान्य वदा-विवाद

श्री अध्यक्ष--Now we come to the general discussion of the Budget.

(विराम)

I would like that an agreed list of all the speakers should be given to me so that I may regulate the time.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

(श्री जसवन्तसिंह)

श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, आज इस सदन में यह दूसरा मौका है कि हमें हमारे प्रान्त के बजट की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हुवा है। मामूली तौर पर वित्त मंत्री का भाषण एक नीरस भाषण हुआ करता है। हमारे इस सदन में ही नहीं, लेकिन भारत में और अन्य विधान सभाओं में या हाउस ऑफ दी पीपल या दुनिया की दूसरी विधान सभाओं में भी वित्त मंत्री का भाषण साधारण भाषण हुआ करता है जिसमें सिवाय करों यानी टेक्सेशन के और दूसरी बातों में ज्यादा दिलचस्पी सदस्य नहीं रखते हैं। पिछले साल भी इसी सदन में ज्योंही वित्त मंत्रीजी का भाषण शुरू हुआ तो या तो बहुत से माननीय सदस्य इस सदन से उठकर बाहर चले गये या यहीं बैठ २ नींद लेने लगे। परन्तु यह बड़े हर्ष की बात रही कि इस साल मेरे माननीय मित्र श्री जयनारायणजी व्यास, ने, जो भाषण दिया, वह एक बड़ा मनोरंजक भाषण था। (सदन में एक आवाज "धन्यवाद") इसमें हमें बड़ी दिलचस्पी रही। हम भी महसूस करते थे कि हम एक दिलचस्प उपन्यास की कहानी सुन रहे हैं, या कोई एरेबियन एन्टरटेनमेन्ट की कहानी सुन रहे हैं, जिसके लिए हमारे वित्त मंत्री यानी माननीय मुख्य मंत्री, इस सदन की बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जिस कदर बजट बनाया गया उसके बनाने में, जो कष्ट उठाया गया और हर चीज बहुत सरल लगी इसके लिये भी हम उनको बधाई देते हैं। इससे भी ज्यादा जो सुन्दर बात मालूम हुई वह यह कि हमारी आधुनिक हिन्दी एक ऐसी कठिन भाषा बन गई है कि जो हम जैसों के लिये समझना भी नामुमकिन हो जाता है, मगर उनका भाषण एक ऐसी सुन्दर और सरल भाषा में था कि जिसे, मैं ख्याल करता हूं सदन के कोने २ में हर व्यक्ति ने अच्छी तरह समझा। इसके लिए भी हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जब से राजस्थान ४ वर्ष पहिले बना तब से आज तक हमारा बजट बराबरी का बजट यानी बेलेन्स्ड बजट नहीं रहा। हमेशा हमें घाटा देखने को मिला। यह पहला ही अवसर माननीय मुख्य मंत्रीजी को मिला कि उन्होंने एक बेलेन्स्ड बजट इस सदन के सामने रखा। (करतल ध्वनि) यह बजट सिर्फ बेलेन्स्ड ही नहीं लेकिन जैसा कि सब इस

[जसवन्तसिंह]

सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि वित्त मंत्रीजी एक पोलीटिशियन ही नहीं हैं, वे एक बड़े भारी कलाकार भी हैं और उनकी कला का नमूना है बैलेन्स्ड बजट; जितनी बजट में आमदनी दिखाई उतना ही खर्चा दिखलाया और नतीजा शेष में कुछ भी नहीं रहा।

मुझे ऐसे बजटों को देखने का काफी अवकाश प्राप्त हुआ। हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी, और मैं ख्याल करता हूं कि सदन के बहुत से अन्य माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने काफी तादाद में बजट देखे होंगे और कम से कम अखबारों में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन दुनियां में कहीं भी शायद ऐसा बजट हो जिसमें जितनी आमदनी हो उतना ही खर्चा हो यह हमारे राजस्थान के लिए निराली बात बन गई है, और मैं समझता हूं कि हमारा राजस्थान दुनियां के बजट बनाने में पथ-प्रदर्शक बन गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

आमदनी और खर्च की तफसीलों पर आने के पहिले मैं कुछ आम बातें कहना चाहता हूं। हमें यह बतलाया गया है कि राजस्थान के निर्माण के समय भिन्न २ एकीकृत राज्यों से कुल १९,३७,२७,०००) रु० प्राप्त हुए जिनमें से १,२४,३०,०००) रु० ट्रस्ट फन्ड के थे। ३१ मार्च, १९५३, तक इस विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट की कुल रकम १४,६८,८६,०००) रु० की ऐसी है जिसमें ट्रस्ट फन्ड के २४,५७,०००) रु० भी शामिल हैं। ७ अप्रेल, १९५४ में इन्वेस्टमेंट में कुल ६०,६४,०००) रु० नये लगे और ३ साल के दौरान में कुल ५,२३,३६,०००) रु० की कमी हुई। इस विषय पर और कोई इत्तला न तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण में है और न एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में है। इसके माने यह हुए कि इस समय हमारे पास १४,६८,८६,०००) रु० की पूंजी है। यानी राजस्थान सरकार के पास इतनी पूंजी होनी चाहिये क्योंकि ५ वर्ष पहले जब राजस्थान सरकार का निर्माण हुआ था उस समय हमें १९,३७,००,०००) रुपये मिले थे। उसमें से ५ या ५.५ करोड़ रुपया खर्च हुआ और बाकी १४,६८,००,०००) रुपया हमारे पास रहा। लेकिन हमें थोड़ा दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह स्थिति एक भ्रम पैदा करने वाली है। मैं नहीं कह सकता कि जान-बूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है या गलती रह गई है। मुमकिन है गलती से भी यह हो सकता है। इसके लिये मैं हमारे सर्वप्रिय फाइनेन्स सैक्रेट्री से मिला और दर्याफ्त किया और कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे पास १४ करोड़ रुपये मौजूद हैं क्योंकि न तो इसका जिक्र बजट के भाषण में किया गया है और न बजट में कहीं १४ करोड़ के न होने की बात ही आई है। मुमकिन है कि इस प्रकार की गलती सरकार के ध्यान में मेरे बात-चीत करने से पहिले ही आ गई हो या मेरे बात-चीत करने के बाद आई हो लेकिन मेरे पास रात को जो एजेन्डा आया उसमें उन्होंने स्थिति को साफ किया है। जो कोरिजेन्डा हमारे पास भेजा है उसके माफिक हमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया से ३१ मार्च, १९५३ तक करीब ९ करोड़ ओवर ड्राफ्ट के रूप में ड्रॉ कर लिये हैं और सही रकम ८,८२,११०००) रुपया है, जो हमें देना होगा। इसके माने यह हुए कि जो १९ करो हमको उस

[जसवन्तसिंह]

वक्त, जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, मिले थे; उनमें से इस वक्त हमारे पास ५।। करोड़ की रकम रही है। मगर यह बात भी सही नहीं है। यदि आप और गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो भी बड़े बड़े काम हमारे प्रान्त में सरकार कर रही है वे सब भारत सरकार से कर्ज लेकर कर रही है और कर्ज की रकम ६ करोड़ के करीब हो गई है। हमारे पास १९ करोड़ रुपया था जब राजस्थान का निर्माण हुआ मगर अब उसमें से माइनस (minus) रह गया है। सब रुपया जो हमारे पास था वह तो खर्च हो गया है और अब हमारी पोजिशन माइनस हो गई है। इस संबन्ध में माननीय चीफ मिनिस्टर के कुछ भी विचार हों और वे यह कहें कि स्थिति इतनी शोचनीय नहीं हुई है जितनी कि लोग विचार कर रहे हैं, परन्तु मेरे खयाल से यदि इस स्थिति पर अच्छी तरह से विचार किया जावे तो मालूम होगा कि गरीब राजस्थानियों का भविष्य एक ऐसी सरकार के हाथ में पड़ गया है कि यदि इसी तरह से खर्चा होता रहा तो मैं यही कहूंगा कि हमारी स्थिति उन भिखमंगों की सी हो जायगी जो बार बार कर्ज लेते रहते हैं और खुद कमा कर नहीं खाते, वे दूसरों के लोन पर ही निर्भर रहते हैं। मैं यह कहूंगा कि हमें इतना अयोग्य होकर नहीं रहना चाहिये। हम इतने बड़े राजस्थान का निर्माण करके अपनी माली हालत को नहीं सुधार सकते हैं तो हम उन भिखमंगों (beggars) के माफिक ही हैं जो कमाकर खाने के काबिल नहीं हैं। हमें हमेशा मंगतों के माफिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने अपना हाथ फैलाए रखना पड़ेगा। यह कहा जाता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमारी माता-पिता है और माता-पिता से मांगना कोई भीख नहीं होती। लेकिन मैं यह कहूंगा कि एक अयोग्य पुत्र अपने पिता के पास, कुछ न कमा कर, हमेशा मांगने के लिये ही जाए तो वह पुत्र कहलाने के लायक नहीं। कहने की बात अलग है कि हमारी इतनी शोचनीय स्थिति नहीं है, मगर मेरे खयाल से एक गंभीर स्थिति है और उसका नतीजा केवल सरकार पर बुरा पड़ने वाला ही है। गरीब राजस्थानी जनता पर भी आने वाले समय में बहुत बुरा असर पड़ेगा।

अब मैं आय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सरकार ने आय का अन्दाज इस साल १९ करोड़ ४४ लाख रुपयों का बताया है। यदि यह रकम इस साल के अन्त में प्राप्त हो जाए तब तो हम मानेंगे कि यह अन्दाज ठीक रहा मगर मेरे खयाल में यह आमदनी होना मुमकिन नहीं है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आमदनी क्यों नहीं प्राप्त होगी।

सबसे पहले आपके आइटम नम्बर ७ लैण्ड रेवेन्यू में ५० लाख रुपये जागीर खालसा होने पर राज की आमदनी दिखाई गई है। यह मुमकिन है और सत्य भी हो सकता है कि जागीरें इसी साल खालसे हो जावें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--Hear, Hear !

श्री जसवन्तसिंह--मगर हम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि आमदनी का जैसा अनुमान हो रहा है, प्राप्त हो जाए। जैसा कि हमको अनुभव हो रहा है कि जहां जागीरदार द्वारा पब्लिक से आमदनी भली भांति ली जा सकती है वहां राज के महकमे द्वारा नहीं ली जाती है

Page No.35

[श्री जसवन्तसिंह]

क्यों कि वहां बटवारा करने वाले दूसरे इन्टरमीजियेरी ही होते हैं। अभी पिछले दो तीन वर्षों में जागीरदारों को भी आमदनी वसूल करने में बहुत दिक्कतें हुई हैं और जिसका कारण हमारे उस दल के कार्यकर्ताओं ने जहां कहीं अकाल हो या न हो वहां पर जाकर किसानों को बहकाया कि जागीरदारों को रकम मत दो। उधर हमारे कोम्युनिस्टों की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने जागीरों में ही नहीं खालसे में भी इस विष को फैलाया और यह एक ऐसी प्रबल भावना हो गई है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जागीरदारों का रकम तो नहीं आती है, मगर खालसे में भी रकम नहीं आती है। और इस विष को किसी तरह से भी आसानी से नहीं रोका जा सकता और ५० लाख की जगह यदि सरकार २५ लाख रुपया भी इस साल में इकट्ठा कर लेगी तो मैं माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद दूंगा। यह रकम सिर्फ पटवारियों के ही जेबों में नहीं जावेगी बल्कि जिस प्रकार यहां राजनैतिक दलों के अधार पर हमारे यहां पंचायतें बनाई जा रही हैं उनमें भी उसका बहुत कुछ हाथ रहेगा जिससे रुपये आने में बहुत कठिनाई पड़ेगी।

सर्वे और सैटिलमैन्ट द्वारा जागीरदारों से प्राप्त की जाने वाली रकम ४ लाख ३१ हजार रुपये दिखलाई गई है। हमारी सरकार के पास इस समय ताकत है और वह जबरदस्ती जागीरदारों से यह रकम ले भी सकती है। लेकिन मैं इस बारे में खासतौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी से जो हम लोगों से सहानुभूति रखते हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित होगा जब कि एक तरफ आप जागीरदारों से जागीर ले रहे हैं फौरन और इसी साल तथा दूसरी तरफ आप उनसे सैटिलमैन्ट का खर्चा भी वसूल करने जा रहे हैं। यह मामूली खर्चा नहीं है। राज्य के महकमों में जो फिजूल खर्ची होती है वह किसी से पोशीदा नहीं है और करीब करीब जागीर की पूरी आमदनी सैटिलमैन्ट में खर्च हो जाती है। एक तरफ तो आप हमसे चाहते हैं कि हम जागीरें देदें और हम जागीरें देंगे क्योंकि यह समय का तकाजा है और समय के माफिक हमको चलना पड़ेगा। लेकिन हम जरूर सरकार से यह आशा करते हैं कि वह हमारे साथ न्याय करे और यदि न्याय करेंगे तो सर्वे और सेटिलमेंट की यह ४ लाख ३१ हजार रुपयों की रकम सरकार के पास कभी नहीं जायगी। जागीरदारों को इस सिलसिले में जो कठिनाइयां हैं उनके सिलसिले में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। आप एक जागीरदार से ५ हजार रुपये सैटिलमैन्ट का खर्चा लें लेकिन उन के नीचे भोमिये हैं, भोम है, देवस्थान की जागीरें हैं, छुट-भाइयों की जागीरें हैं और अन्य बहुत से खर्चे हैं; जब आप जागीर ले लेंगे तो जागीरदार इस रकम को कैसे प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई शक्ति तो है नहीं। इसलिये यह न्यायोचित नहीं होगा कि जागीरदारों से यह रकम ली जाय।

तीसरी बात यह है कि मातमी और हुक्मनामे के मद में १ लाख २३ हजार की रकम दिखाई गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आशा नहीं कर सकता क्योंकि वे हमारे शुभचिन्तक हैं। मैं बनारस में चार वर्ष पढ़ा हूं। वहां पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट के श्मशान के डोम जमादार बैठे बैठे माला फेरते हैं कि कोई मुर्दा आवे तो उनको पैसा मिले।

[श्री जसवन्तसिंह]
इसी तरह से मेरे खयाल से मुख्य मंत्री भी यह आशा नहीं रखेंगे कि कोई जागीरदार मरे तो हुक्मनामे का पैसा आवे क्योंकि वे हमसे हमदर्दी रखते हैं । यदि वे ऐसी आशा रखते हैं तो वे हमारे शुभचिन्तक नहीं हैं । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस हुक्मनामे के साथ साथ कुछ ओब्लिगेशन्स भी होते थे और यह पारस्परिक होता था । मातमी और हुक्मनामा तभी होता था जब उसके बदले में जागीरदार को सरोपाव मिलता था जो काफी कीमती हुआ करता था। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे मातमी और हुक्मनामा के बदले में सरोपाव देने को तैयार हैं या उनका दृष्टिकोण इकतरफा ही है ? आप ताकतवर हैं इसलिये इकतरफा कॉन्ट्रेक्ट करना चाहते हैं । अगर यह बात है तो मुझे ऐतराज नहीं है । लेकिन यह रकम सरकार किसी भी तरह वसूल नहीं कर सकेगी ।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह है ट्रिब्यूट (रेख चाकरी) के बारे में । इसके लिये ३२ लाख ६० हजार रुपयों की आमदनी दिखाई गई है । ठीक है, यदि हमारे साथ न्याय होगा तो हमें ट्रिब्यूट भी देनी होगी । लेकिन एक तरफ तो सरकार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को यह लिखती है कि रकम रोकली जाय, जागीरदारों को अभी रकम नहीं लेने दी जाय । जहां पर अकाल है वहां पर तो यदि ऐसा किया जाता है तो किसी हद तक ठीक भी माना जा सकता है लेकिन जहां की फसल अच्छी हालत में है वहां भी इस साल जागीरदारों को रकम नहीं लेने दी गई है । क्या सरकार जागीरदारों से आशा करती है कि उनको रकम भी नहीं लेने दी जाय और उनकी आमदनी का सब जरिया बन्द कर दिया जाय, उनसे जागीर लेली जाय और इसके साथ ही साथ ट्रिब्यूट भी लेली जाय ; तो यह बात उचित नहीं है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी हालत में ये ३२ लाख रुपये रेख चाकरी के वसूल नहीं किये जा सकेंगे। आप एक एक जागीरदार को जेल भेज सकते हैं लेकिन ३२ लाख रुपये के बजाय आप ५ लाख रुपये भी इकट्ठे करलें तो भी मैं आपको बधाई दूंगा । इसलिये यह जो सबसे बड़ी रकम राजस्व की दिखाई गई है उसमें इतनी बाधाएं हैं कि वह रकम कभी प्राप्त हो नहीं सकती । अपने भाषण के दौरान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया था कि १० लाख १ हजार रुपया फोर्मर राजस्थान की उन जागीरों से वसूल होगा जो रिज्यूम करली गई हैं । मुझे आज तक यह नहीं मालूम हुआ । फोर्मर राजस्थान के किसी सदस्य को मालूम हो तो पता नहीं कि अब तक वहां की कोई जागीर खालसे करली गई है । मैं नहीं कह सकता कि कौनसी जागीर से १० लाख १ हजार रुपयों की रकम वसूल होगी । बजट में जो भाषा लिखी गई है वह उचित नहीं है । हमारी सरकार को ऐसी भाषा काम में नहीं लानी चाहिये जिसका कोई तथ्य ही न हो ।

स्टेट एक्साइज ड्यूटी–आबकारी के मद में इस साल १ करोड़ ९० लाख १४ हजार रुपयों की आमदनी दिखाई गई है और पिछले साल से इस साल २५ लाख की बढ़ोतरी इस साल बतलाई गई है । इस बढ़ोतरी का जो कारण मेमोरेन्डम में बतलाया गया है वह बिल्कुल गलत है और उन्हीं कारणों से आप २५ लाख की बढ़ोतरी की आशा करते हैं । मैं अर्ज करूंगा कि २५ लाख की बढ़ोतरी तो दूर रही उल्टी २५ लाख की कमी होगी । यदि संबंधित महकमा मेरा चेलेन्ज एक्सेप्ट

Page No.37

[श्री जसवन्तसिंह]

करे तो मैं चेलेन्ज देने को तैयार हूं कि जिन कारणों से आप अधिक आमदनी की आशा करते हैं वह आमदनी कभी नहीं हो सकेगी। यदि चतुराई और योग्यता के साथ काम किया जाय तो २५ लाख के बजाय ५० लाख की आमदनी हो सकती है। इस वक्त हमारे यहां जानकारी का काम कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम पर चलता है। हमारी सरकार की यह शोर्ट साइटेड (short sighted) पोलिसी है। वह ख्याल करती है कि इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी पर मैं कहूंगा कि कान्ट्रेक्ट सिस्टम से ठेकेदारों से रकम एकट्ठी करना मुश्किल हो जायगा। आप इससे जनता के साथ भी बहुत अन्याय करते हैं। ठेके के कारण शराब बहुत कीमती हो जाती है और हरएक के लिए खरीदना मुश्किल हो जाता है। जिनकी शराब पीने की आदत है वे अपने बाल बच्चों को भूखों मारकर भी शराब पीना चाहते है। ठेकेदार शराब में ५० प्रतिशत पानी मिला देते हैं क्योंकि उनको ठेके की रकम ज्यादा देनी पड़ती है। सीलड बोटल sealed bottle की कीमत सरकार ने ३ रु० १ आना में रखी है। आप एक्साइज इन्सपेक्टर को बोतल लेने भेजिये। उसकी आइडेन्टिटि मालूम नहीं होनी चाहिये। यदि आप ३ रुपये १ आना बोटल प्राप्त कर सकें तो शर्त लगाने को तैयार हूं। मार्केट में यही बोतल साढे चार, पांच रुपयों में मिलती है। इसके लिए हम दुकानदारों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनको ठेके की रकम बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। इसके अलावा एक्साइज इन्सपेक्टर्स व दूसरे अफसरों को इन ठेकेदारों को माहवारी दो सौ, चार सौ या पांच सौ रुपयों तक रिश्वत में देने पड़ते हैं। इस तरह से एक एक दुकानदार से उनका वेतन मुकर्रर है। एक तरफ तो आप करप्शन और ब्लेक मार्केटिंग को मिटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसको उत्तेजना और प्रोत्साहन देते हैं; यह कहां तक उचित है? यदि आप गलत सिस्टम पर चलेंगे तो यह जनता के हित में बहुत बुरी बात होगी। जो करप्शन एक्साइज विभाग में फैल रहा है उसे आपको मिटाना चाहिये। मुमकिन है आपको एक साल आमदनी कम हो पर तीन-चार साल के बाद आपकी आमदनी निश्चितरूप से बढ़ जायगी।

इसके अलावा अभीतक जागीरदारों को भी इस बात का हक थी कि वे अपने खुद के इस्तेमाल के लिऐं खुद शराब बनावें। अब वह हक भी रह नहीं गया है। अब काफी एरिया सरकार के पास ऐसा आ गया है जो पहले कभी नहीं था। अगर अब वैज्ञानिक तरीकों से इस बारे में भी तरक्की की जावे तो यह सिर्फ राजस्थान के लिये ही आर्थिक दृष्टि से एक अच्छी चीज नहीं होगी वरन् भारत के लिये भी अच्छी चीज होगी।

अब मैं दूसरे आइटम (मद) पर आना चाहता हूं जोकि एक अच्छा आमदनी का जरिया हो सकता है। वह है आबादी के एरिया में जमीनों की बिक्री। इसकी कुल आमदनी ४ लाख ५३ हजार बताई गई है सिटी इम्प्रूवमेंन्ट की स्कीमें भी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लागू हैं जिसकी रकम ८ लाख ९४ हजार बताई गई है। इस तरह कुल रकम १३ लाख की बताई गई है। इस विषय पर हमारा काफी वाद-विवाद हो चुका है और वे सब बातें अब मैं दोहराना नहीं चाहता। मगर पिछले सेशन में इस सवाल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण आखिर में हुआ था जिसका कि जवाब हम नहीं दे पाये थे। संक्षेप में मैं यह बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह फरमाया था कि "सी" स्कीम जयपुर में जिस प्रकार जमीनें बेची गई

[श्री जसवन्तसिंह]

उससे वे संतुष्ट हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि सर मिर्जा के वक्त में धनाढ्यों को चार-चार आने गज में जमीन दी गई थीं। यह भी कहा गया था कि कुछ जागीरदारों को मुफ्त में भी जमीनें दी गई थीं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—नहीं, नहीं नोमिनल रेट पर।

श्री जसवन्तसिंह—नोमिनल रेट पर दी गई थीं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने आप को राजाओं के स्थान पर समझते हैं। महाराजा जयपुर, जयपुर के मालिक थे और जयपुर का राज्य उनका राज्य था। उनको हक था कि वे चाहें तो मुफ्त में भी दे सकते हैं। अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह दावा हो कि वे महाराजा जयपुर, जोधपुर या बीकानेर की जगह आज हमारे राजस्थान की गद्दी पर आरूढ़ हैं और जिसको चाहे उसको कुछ भी दे सकते हैं तो वे स्पष्ट कहें, पर उनका यह कथन आज के जनतन्त्रवाद के युग में चलने वाला नहीं होगा। आपने फरमाया कि उनके वक्त में तो सात-सात, छ-छ रुपये फी गज पर जमीनें दी गई हैं जहां कि पहिले समय में एक-एक दो-दो रुपये में दी गई थीं। मैं कहना चाहता हूं जयपुर महाराजा ने तो मालिक की हैसियत से लाखों रुपयों की जागीर दे दी हैं। उन पर शंका करने वाला कोई नहीं था। पर आज जनतन्त्र राज्य में क्या प्रधानमन्त्रीजी, क्या मुख्य मन्त्रीजी अथवा कोई भी मन्त्रीजी इस तरह अगर देंगे तो उन्हें भी जबाब जरूर देना पड़ेगा।

पहले इसके कि मैं अंग्रेजी कहावत बताऊं उस कहावत के बारे में जिक्र करदूं, मैं यह भी साफ करदूं कि सर मिर्जा के बारे में जो यह कहा गया कि उन्होंने नौमिनल कीमतों पर जमीनें दे दीं या कम रेट पर दीं या अधिक पर। उन्होंने कुछ भी किया हो पर उन्होंने वह अपने भाईयों को अपने बेटों को, स्त्री को या दोस्तों व रिश्तेदारों को कभी नहीं दी थी। उन्होंने जयपुर नगर को उन्नत, विस्तृत व सुन्दर बनाने के लिये वे जमीनें दी थीं। लेकिन जिस तरह घरेलू तौर पर "सी" स्कीम में जमीनें बांटी गई हैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वह ऑब्जेक्शनेबल है। हो सकता है जिस जमीन को इन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी छ-छ और सात-सात रुपये में दी हों वे ही जमीनें अगर ऑक्शन में आतीं तो तीन-तीन चार-चार रुपये में ही उठती; पर जनतन्त्र के आज के युग में कितना ही बड़ा कोई हो, कितनी ही बड़ी किसी की पर्सनेलिटी हो उनको भी हम यह हक नहीं देंगे कि वह प्राइवेटली किसी भी चीज को किसी को दे दे। अंग्रेजी की कहावत इस प्रकार है, "Coser's wife should not only be chaste but above suspicion" इसलिये हमें जो कुछ भी कार्य करना है उस पर किसी को शक-शुबहा नहीं होना चाहिये।

इसलिये इस विषय पर ज्यादा न कह कर यही अर्ज करूंगा कि अगर उन्हें जनतन्त्री राज्य में एक सच्चे जनतन्त्र के हिमायती के रूप में कर्म करना है तो उन्हें प्राइवेट डीलिंग करना उचित नहीं है। अगर करेंगे तो हम करने नहीं देंगे, जनता उन्हें रोकेगी ऐसा करने से। मुमकिन है हमें नुकसान भी हो ऐसा करने में, पर जनतन्त्र राज्य में इस तरह से काम नहीं होने का है।

[श्री जसवन्तसिंह]

इसी तरह में कोर्ट ऑफ वार्ड्स् के मुतल्लिक कहना चाहता हूं। इस महकमे में भी कितना अन्धेर, है कितना अन्याय बेचारी गरीब बेवाओं और बच्चों पर किया जा रहा है यह भी दो चार शब्दों में मैं कहना चाहता हूं।

मुझे बिल्कुल मालूम है कि हमारे मुख्य मन्त्री इस विषय पर कितने जागरूक हैं और कितनी दिलचस्पी इसमें रखते हैं। दूसरी बातों में वे और हम खूब लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। उनसे लडते हैं पर जहां तक बेचारी बेवाओं और स्त्रियों का सवाल है वहां उनकी हमदर्दी रही है। यह मेरा खुद का अनुभव रहा है। दो-चार मामलों में उन्होंने उनकी हालत देखी और फिर उनसे सहानुभूति ही नहीं दिखाई पर बहुत कुछ करके भी बताया।

पर दु:ख के साथ इस विषय को सदन के सामने लाना पडता है। आज जनतन्त्र का युग आया है। भले ही आया हो, पर है केवल कहने के लिये। पर इस सरकार का ढांचा वही ब्युरोक्रेटिक है, जो पहिले था। बल्कि वही नहीं है उसमें कुछ तरक्की ही हुई है। Pens Corruption and minors efficiency यानि योग्यता कम और भ्रष्टाचार ज्यादा। यह हमारा ब्युरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आज जो है वह ऐसा हो गया है कि निर्दयता के साथ स्त्रियों और ऑर्फन्स (निस्सहायों) के साथ वे जो सलूक आज कर रहे हैं इस डिपार्टमेण्ट में वह दो-चार शब्दों में मैं बताना चाहता हूं।

इस दुर्भिक्ष के वक्त और पिछले दो-चार सालों में भी ऐसा हुआ है कि जहां अकाल नहीं भी हुआ है वहां भी इन बिचारी विधवाओं को हासिल ये निर्दयी अफसर वसूल नहीं करने देते। अकाल की स्थिति में वैसे ही उनके पास कुछ नहीं रहता। एक जगह तो राजनैतिक कार्यकर्ता सभी दलों के भी पहुंचे पर ये ब्युरोक्रेट अधिकारी कुछ नहीं करते। इसके अतिरिक्त जब उनकी यह हालत हुई तो किसी तरह अपना पेट पालने के खातिर अगर वे कर्जा लेने की कोशिश करती हैं तो उन्हें कर्जा भी नहीं दिया जाता। एक छोटी सी शिकायत पर उनके खिलाफ हुक्म दे देते हैं। वह हुक्म कोर्ट ऑफ वार्ड्स में भी आता है। वहां से यह हिदायत निकलती है कि इन अबलाओं और बच्चों को कोई प्राईवेट कर्जा भी अगर देगा तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। उधर तो हमारी सरकार का हुक्म है रकम रीअलाइज की जावे और इधर ये हमारे निर्दयी ब्युरोक्रेट अफसर साल-साल, दो-दो साल तक खाने को पैसा नहीं देते और अगर कहीं से कर्जा लेने की कोशिश भी करते हैं तो कर्ज देने वालों को बहकाते हैं। मैं उन अफसरों से पूंछूं कि अगर एक महीना आपको तनख्वाह नहीं दी जावे तो हम देखें किस तरह दूसरे महीने वे काम चला सकेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूं कि वे सहृदयता से इस मामले का हल करें। मेरा उनसे निवेदन है कि केन्द्र में जयपुर में, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जावे जिसकी सलाह से ये ब्यूरोक्रेट अफसर काम करें तो इन अबलाओं का कल्याण हो सकता है।

इसके अलावा आप फोर्मर राजस्थान का हाल देखिये। इधर तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स इन अबलाओं से काफी रकम लेता है। १८–१८ प्रतिशत और २०–२० प्रतिशत खर्चा वसूल करते हैं

[श्री जसवन्तसिंह]

और उधर जो जागीरें रेवेन्यु पॉवर्स के मातहत अपने अधिकार में करली गई हैं उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दूसरे महकमे के जरिये वसूल किया जाता है। और ४०–४० और ५०–५० पर्सेंट खर्चा उनसे लिया जाता है और कुछ भी काम नहीं किया जाता। यह सोचनीय स्थिति, है, निर्दयता की एक करुण कहानी है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो तजवीज इस बारे में पेश की है उस पर आप ध्यान देंगे।

(श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

अब मैं खर्च के मुतल्लिक दो-चार बातें कहना चाहता हूं। सब से पहले जकात और आबकारी का सवाल है। इसमें एन्टी स्मगलिंग डिपार्टमेन्ट के सामने ६ लाख ५७ हजार का खर्चा दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी और होना चाहिये किन्तु स्मगलिंग डिपार्टमेंट के पास, उसके सुचारु रूप से कार्य करने के लिए क्या साधन हैं? अगर हैं सरकार चाहती है कि एन्टी स्मगलिंग डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी अपने घरों पर ही बैठे रहें और कुछ काम न करें और राजस्थान के इस एक लाख २० हजार वर्गमील के रकबे में अपने आप काम हो जायगा तो दूसरी बात है और इस तरह से ६ लाख ही क्यों एक करोड़ रु० भी अगर रख दें तो वह भी खर्च हो जायगा। प्रश्न तो यही उठता है कि उनके पास इस विभाग को चलाने के लिए क्या साधन हैं? यह मानना ही पड़ेगा कि उनके पास इस विभाग को चलाने के लिए कोई साधन नहीं हैं, आर्म्स और एम्युनिशन्स नहीं हैं। मुझे मालूम है कि इस विभाग के एक-दो कर्मचारी थे उनको माल की चोरी करने वालों से मुकाबला करना पड़ा और उन चोरों को पकड़ने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा किन्तु उनके पास साधन न होने से आखिर उनको अपनी जानें खोनी पड़ीं। अगर उनको अपने बचाव के लिए शस्त्र काम में लाना पड़ता है तो उनको ५–६ महीने जेल में रहना पड़ता। तो आप यह चाहते हैं कि क्या इस तरह से यह डिपार्टमेन्ट जिस तरह काम कर सकता है क्या आप उनके कार्य के लिए कुछ भी बन्दोबस्त नहीं कर सकते हैं? अगर जीप्स या और कोई ट्रेवल करने के लिए जरिया मांगा जाता है तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट टेक्स लगा देता है कि यह खर्चा हटा दिया जाय। अत: ६ लाख ५७ हजार रुपया जो आपने दिया है उसके लिए यही कहूंगा कि आप क्यों यह रकम खराब करते हैं? जब आपके पास साधन हों, आप जब आर्म्स एन्ड एम्युनिशन्स इकट्ठा कर सकें तब ही यह खर्चा करिए। अगर साधन नहीं जुटाते हैं तो इस डिपार्टमेन्ट पर फिजूल खर्चा होगा।

अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। कमिश्नर्स तो बड़े अफसर हैं उनके लिए तो कहना वाजिब नहीं होगा, लेकिन कलेक्टर्स, सब डिवीजनल ऑफिसर्स और तहसीलदारों के सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करूंगा। ये बड़े अफसर जरूर हैं किन्तु कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्त्ता जब सफेद टोपी लगा कर उनके पास जाता है तो वे सिर से पांव तक कांपने लग जाते हैं। (करतल ध्वनि व हंसी)

चाहे कोई अनुचित काम हो और उनका अगर वे कहना न मानें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक हफते में उनका वहां से ट्रांसफर हो सकता है; ये इतनी बड़ी ताकत रखते हैं। म्हारे

[श्री जसवन्तसिंह]

मुख्य मंत्री जी, डिप्टी चीफमिनिस्टर (उप-मुख्य मंत्री) और रेवेन्यू मिनिस्टर (राजस्व मंत्री) भी अगर उनका कहना न मानें तो इलेक्शन के वक्त उनकी भी मुसीबत हो जाय। इसलिए उनका कहना मानना ही पड़ता है। उन्होंने यह एक ब्लेक मार्केटिंग का जरिया निकाला है। गलत शिकायत होने पर ही बदली करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं रह जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि इलेक्शन के वक्त उस सिलसिले में जो भी ट्रांस्फर्स हुए उनसे उनको फायदा हुआ है, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है। किन्तु जब इलेक्शन का सवाल न हो तथा मामूली तौर पर सरकार का कार्य चल रहा हो और फिर इस प्रकार की धांधली होती है तो बड़ी आश्चर्य और दुःख की बात मालूम होती है। दो महीने की बात है, मैं आपको उस व्यक्ति का नाम तो नहीं बताऊंगा और यदि मैं आपको उसका नाम बता दूं तो बेचारे का राजस्थान की नौकरी में रहना मुश्किल होजाय क्यों कि हमारा जैसा नैतिक स्तर है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको बताद्ं कि एक हफ्ते के अन्दर उसका तीन दफा तबादला हुआ है। पहले एक जगह रहा तो दोस्तों ने शिकायत की। मोअत्तिल करना तो एक खिलौने की बात होगई है। एक शिकायत पर उसकी किसी कारण से बदली की गई। पांच दिन के बाद माननीय मंत्री जी के दोस्तों का वहां जाना जरूरी था और जरूरी होने से वहां से भी उसको हुक्म मिला कि यहां से आगे जाओ। एक हफ्ते के अन्दर महज दोस्तों के कहने से उनको हुक्म हुआ कि यहां से भी आगे जाओ। तहसीलदार बदल सकता है किन्तु राज्य की माली हालत कितनी गरीब होती है उसको आप देखें। क्या इस ओर ख्याल किया गया है कि इन ट्रांसफर्स से राजस्थान के कोष पर कितना खर्चा पड़ता है? मैं आपको कहूंगा कि लाखों रुपये ट्रेवलिंग और भत्तों पर खर्च होते हैं। यदि आप न्याय करें, राजनैतिक विचारों को हटा कर न्याय करें तो लाखों रुपया जो खर्च होता है वह आप बचा सकते हैं।

मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक भी दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं मेरे माननीय मित्र और साथी जो मिनिस्टर्स हैं उनके मुतल्लिक दो-चार शब्द कहूंगा और मेरे मित्र जो यहां मौजूद हैं वे उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे।

श्री मोतीराम—सुन ही नहीं रहे हैं किन्तु नोट भी कर रहे हैं।

श्री जसवन्तसिंह—तो बड़ी कृपा है। मिनिस्टर्स का खर्चा ४ लाख ६८ हजार ८०० रुपया बजट में दिखाया गया है। उसमें मिनिस्टर्स और उनके पी० एज० की सैलेरी पर २ लाख ११ हजार ८०० रुपया दिखाया गया है जब कि पिछले साल १ लाख ६० हजार २०० रुपया दिखाया गया था। अतः यह पचास हजार रुपये की बढोतरी क्योंकर की गई? मुख्य मंत्रीजी बता सकेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के हेड (Head) वे हैं और पार्टी के नेता भी वे ही हैं। बजट के देखने से पता चलता है कि राजस्थान में दस मिनिस्टरों की गुंजाइश रखी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान जैसे गरीब माली हालत वाले प्रदेश में दस मिनिस्टरों की गुन्जाइश है, जरूरत है? एक अंग्रेजी कहावत के मुताबिक एक एक मिनिस्टर एक

[श्री जसवन्तसिंह]

"व्हाइट एलीफेन्ट" है। वह इतना बोझल होता था कि उसके पीछे काफी संख्या में दूसरे कर्मचारियों का खर्चा करना पड़ता था। राजस्थान की हालत को देखते हुए सात मिनिस्टरों की भी कोई गुन्जाइश नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की तकलीफों को भी महसूस करता हूं। पार्टी के सब तत्वों का ध्यान न रखें तो पार्टी में मुश्किल पड़ जाय और उनको दुःख उठाना पड़े। मैं नहीं समझा हूं कि क्या तथ्य हैं किन्तु जो माननीय सदस्य अखबार पढ़ते हैं वे जानते हैं और देख रहे हैं कि आजकल मंत्रीमंडल में क्या चहल पहल हो रही है। यह तो बिल्कुल उनके (मुख्य मंत्रीजी के) अधिकारों की बात है कि जिसको चाहें वे मिनिस्टर बनावें। हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं है, किन्तु यह जरूर चाहते हैं कि मिनिस्टरों की संख्या उतनी ही हो जितनी कि हमारा प्रान्त बर्दाश्त कर सके। विरोधी दल के सदस्य और सदन के सदस्य उनको सहयोग देंगे, हमेशा उनको सहयोग देंगे जहां तक कि प्रान्त की भलाई और इसके हित का प्रश्न है किन्तु कांग्रेस पार्टी के हित की बात होगी तो हम विरोधी पक्ष के सदस्य सहयोग नहीं देंगे और विरोध करेंगे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—वाजिब बात होगी तब भी सहयोग नहीं देंगे ?

श्री जसवन्तसिंह—जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वह ठीक बात नहीं है। यह एक दुख की बात है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के हित की बात भी नहीं कर रहे हैं और देश के हित की बात भी नहीं कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट है तथा और भी स्पष्ट हो जाती है।

अब मिनिस्टरों के ट्रैवलिंग एलाउन्स के बारे में थोड़ा कह दूं। पिछले बजट में ६० हजार रक्खे गये थे पर इस साल १ लाख रुपया रक्खा गया है। ठीक है जैसा वे चाहें करें। मुख्य मंत्रीजी भी ये हैं और वित्त मंत्रीजी भी ये हैं, एक लाख क्यों २ लाख रख सकते हैं। सदन में उनकी मेजोरिटी है; पास भी करवा लेंगे। लेकिन आज दुनिया इन सब कामों को आंखें खोलकर देख रही है। प्रान्त के हित की बात भी यह नहीं होगी।

दूसरी ओर मुझे खुशी है इस सिलसिले में कि जहां पिछले साल मिनिस्टरों की कारों के लिए १ लाख ५४ हजार रुपया रक्खा गया था वहां इस साल सिर्फ ३ हजार ही रक्खे गये हैं। इसकी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं। मुझे बड़ी खुशी है। पर साथ ही यह भी कह दूं कि अगर यह बात नहीं है और मोटर का खर्चा और किसी सीगे में डाला गया है तो वे ऐसा बतला दें ताकि अभी जो बधाई दी है वह वापिस ले लूं। (हंसी) लेकिन फिर भी आगे से कम से कम बधाई तो दे दूं क्योंकि वाकई यह बधाई की बात है। जहां पिछले साल १ लाख ५४ हजार रक्खे गये थे जो निर्दयता की फिजूल खर्ची थी वहां इस साल केवल ३ हजार ही रक्खा है। यह वाकई खुशी की बात है और प्रसन्नता की बात है। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो जिससे मैं अपनी यह बधाई वापिस लूं।

अब मैं सरकार के पेंशनरों के मुतल्लिक भी दो चार बातें कहना चाहता हूं। यह मैं कई दफा कह चुका हूं और केवल कह ही नहीं चुका वरन् अनुभव भी कर चुका हूं कि हमारे मुख्य मंत्री एक बड़े हमदर्द व्यक्ति हैं।

[श्री जसवन्तसिंह]

अभी राजस्थान को हुए चार वर्ष हुए। इस अर्से में हजारों की तादाद में गरीब आदमी जिनको पांच-पांच, दस-दस रुपये पेंशन अथवा ग्रेच्युटी मिली है, जिनमें से भी बहुत से मर चुके हैं उनमें से बहुतों को अभी तक उनकी पेंशनें नहीं मिली हैं। हमारे मुख्य मंत्री वित्त मंत्री भी हैं, अतः मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे सुख चैन की नींद कैसे ले रहे हैं जब कि हमारे ही बहुत से कर्मचारी भाई आज अपनी वृद्ध अवस्था में, राज की जीवन भर सेवा करके रिटायर हुए हैं तब उनकी जो पेंशन है, गुजारे के आधार हैं, वही नहीं वे पाते। मैं चाहता हूं कि वे अपने मंत्री-मन्डल को दो तीन महीने की तनख्वाह नहीं दें, फाइनेन्स महकमे की तनख्वाह रोक दें; उस समय तक जब तक कि उनको उनकी पेन्शन नहीं मिल जावे; तब तो यह काम हो सकता है, नहीं तो ये गरीब पेन्शनर मर जावेंगे। तब तो यह काम हो सकता है, नहीं तो ये गरीब पेंशनर मर जावेंगे। ऐसा हुए बिना हमारी इस ब्यूरोक्रेटिक सरकार के इन अफसरों से हम आशा ही कर सकते हैं, यह आशा फलीभूत नहीं हो सकती।

हमारी पुलिस के मुतल्लिक जिक्र करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि ऐसा सब महसूस करेंगे कि पुलिस का खर्चा बहुत ज्यादा है और मैं भी समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा है और होना चाहिये। किन्तु यदि मुख्य मंत्री जी ऐसा अनुभव करते हैं कि जितनी ज्यादा पुलिस रखेंगे उतनी ही अधिक शान्ति कायम रख सकेंगे तो मैं कहता हूं कि यह उनका भ्रम है। जब तक जनता का मोरल उन्नत नहीं करेंगे तब तक यह तो क्या पुलिस पर ३ करोड़ के बजाय ६ करोड़ भी लगावें तब भी पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

आगे इसी सिलसिले में अपने भाषण में ३२ वें पैरा में मुख्य मंत्रीजी ने कुछ शब्द कहे हैं उनको सुनकर हम इस तरफ जो बैठे हैं वे बड़े दुखी हुए हैं। अगर और कोई व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करता तो हमें कोई दुख नहीं होता क्योंकि ये विचार एक छोटे दर्जे की लोकप्रियता के विचार हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ऐसे नहीं समझे जाते। वे पहिले से ही लोकनायक कहलाते हैं, और हैं भी वे यही। उनके विचार उच्च दर्जे के होने चाहिये। हमारे इन मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीगण तो क्या माननीय सदस्यों से भी ऐसी आशा नहीं की जा सकती। फिर भी अगर इनके स्थान पर और कोई ऐसे विचार व्यक्त करते तो इतना दुख फिर मैं नहीं होता हमें, पर हमारे लोकनायक कहलाने वाले मुख्य मंत्रीजी से ये बातें सुनकर दुख हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा है इस पैरे में कि राजस्थान की पुलिस को अपने दल की एक बड़ी संख्या राजाओं के महलों, किलों व अन्य ऐसे स्थानों की रक्षा करने में लगानी पड़ती है जो "बी" श्रेणी के अन्य राज्यों को नहीं करना पड़ता है। सरकार इस मद के खर्च में कमी करने का विचार कर रही है। आप इस खर्च में कमी करिये, जरूर करिये। मैं राजाओं की तरफ से वकालत करने नहीं आया हूं। पर आज हमारे दुर्भाग्य से हमारे नेता सरदार पटेल साहब हमारे बीच में नहीं हैं जो कि राजाओं की सेवाओं की क़द्र करते थे और जो त्याग राजा लोगों ने किया है उसकी प्रसंशा करते थे। बीकानेर की बात करते हुए मैं यह पूछूं कि जहां पर एकीकरण के वक्त से जो करीब ४० गार्डें थीं; एकीकरण स्वीकार करने के

[श्री जसवन्तसिंह]

पश्चात् केवल २२ गारडें मंजूर हुईं और अब सिर्फ ६ गारडें रह गई हैं; अब और भी कमी होगी; ऐसा लगता है। पर अगर आप यह ख्याल करते हैं कि इन गार्डों के हटाने से राजाओं की पोजीशन में फर्क आ जाएगा तो यह गलत बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस राजस्थान प्रान्त का बड़े से बड़ा नेता अगर बीकानेर में जावे तो कोई उनको पूछने और वैसा स्वागत-सत्कार करने को तैयार नहीं होगा, पर हमारे हृदय महाराजा बीकानेर अगर बाहर निकलें तो लाखों आदमियों की तादाद वहां उनका स्वागत करने को इकट्ठी हो जावेगी।

तो गार्डों को हटाकर इस प्रकार छोटे विचार रखकर काम करने से बड़प्पन जाहिर नहीं होता। अगर आप राजाओं के लिये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी आपको पूछ सकते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर जो हैं इनके पीछे क्या है? वे जहां कहीं जाते हैं आर्म्ड गार्ड संगीन लगाये क्यों खड़ी रहती हैं। होम सेक्रेटरी साहब के मकान के सामने भी उनके बचाव के लिये गार्ड खड़ी है। मेरे ख्याल में ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इसके लिये एक रुपये का कारतूस खराब करेगा। (हंसी) और इनको कोई भगाकर भी किस लिये ले जावेगा। यह मुमकिन है कि धनाढ्य लोगों के, सेठ साहूकारों के लडकों आदि को डाकू भी पैसे के लालच में ले जा सकते हैं पर इनको कौन ले जावेगा और लेजाकर करेगा भी क्या इनका। फिर इनके लिये गार्ड क्यों हैं? इनके घर पर गार्ड क्यों है? हमारे डिविजन में कमिश्नर्स हैं उनके पास गार्ड क्यों हैं? आई. जी. और डी. आई. जी. के पास गार्ड क्यों? कलेक्टरों और पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टों के यहां गार्ड क्या कर रही हैं? इन सबके यहां गार्ड क्यों जरूरी हैं और राजाओं के यहां क्यों जरूरी नहीं हैं? यह इसलिये है कि अब इनकी वकत नहीं रह गई है। पर हम व्यासजी से यह आशा नहीं करते थे क्योंकि वे हमारे मित्र हैं। जो निर्दयता का खर्चा, इन अहलकारों और मिनिस्टरों पर किया जाता है उसका कभी स्वप्न भी हम नहीं देख सकते थे, राजाओं की तरह रहने का, उनके लिए तो मुफ्त में कई गार्ड आ जाती हैं उसकी क्या आवश्यकता है? इनके यहां गार्डें रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इनके न रखने से राजस्थान सरकार का बहुत रुपया बच सकता है।

माननीय चेयरमेन मुझे बोलते बोलते करीब एक घन्टा हो गया है और मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर अपना भाषण १० मिनिट में पूरा कर दूंगा, ऐसी आशा करता हूं।

अभी जो बातें मैंने बताई हैं वे तो जनरल बातें हैं। अब मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण प्रान्त का जिक्र करना चाहता हूं जहां से मैं भी आया हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त हमारे शरीर के रूप में है, हमको इसके सभी भागों का बराबर ध्यान रखना चाहिये और सभी हिस्सों के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिये और यदि बराबरी का बर्ताव नहीं किया जायगा तो जो स्वप्न हम देखते हैं, जैसा कि हमारे मित्र माननीय चीफ मिनिस्टर ने कहा वह तो स्वप्न ही रह जावेंगे। जैसे हमारे शरीर के सभी अंगों की हमको बराबर देखभाल करनी पड़ती है उसी प्रकार प्रान्त की भी सेवा करनी चाहिये, वरना जहां कहीं अंगुली में चोट लगी और उससे विस्फोट हो गया तो सारे शरीर में उससे इतनी ही तकलीफ होगी। यदि आप इस राजस्थान को बनाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि जो बीकानेर के साथ अभी व्यवहार किया

[श्री जसवन्तसिंह]

जा रहा है वह नहीं किया जाना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि यह व्यवहार जान-बूझ कर किया जाता है या अनजान में; लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है। इसलिये मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूं कि वे जुल्म क्या हैं?

इस साल नये बजट में बीकानेर के लिये जो नई रकमें रखी गई हैं उनका थोड़ा वर्णन आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे आपको पता लगेगा कि बीकानेर के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया गया है और फिर भी हमारी सरकार यह इच्छा करती है कि हम सद्भावना रखें। सबसे पहले नये आइटम रखे हैं:—

(१) राजस्थान में राजस्व द्वारा जो काम किये जावेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस काम के लिये १,४३,०००) रुपये रखे गये हैं। इसमें बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है।

(२) गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा मदद से जो काम फाइनेन्स किये जावेंगे और जो ऑर्डिनरी रेवेन्यू से खर्च किया जावेगा उसके लिये हमारे राजस्थान में इस साल ५,०००) रुपये रखे गये हैं। लेकिन हमारी सरकार की कृपा है कि बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है।

(३) गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से इरिगेशन, ड्रेनेज आदि कामों के लिये ग्रान्ट मिली है उसके लिये १३,१९,५००) रुपये रखे गये हैं। लेकिन इसमें भी बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। आप सुनते जाइये।

(४) अब आप पब्लिक हैल्थ की तरफ देखिये। मानो बीकानेर वालों को इसके लिये कोई किसी प्रकार के प्रबन्ध की आवश्यकता ही नहीं। इस वर्ष के बजट में चीफ इन्जिनियर, बिल्डिंग एन्ड रोडस, द्वारा किये जाने वाले कार्य के लिये ५०,०००) रुपये रखे गये हैं? ९६,०००) रुपये चीफ इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट द्वारा कार्य कराये जाने के लिये रखे गये हैं। मगर इसमें भी बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। आप सुनते जाइये।

(५) सिविल वर्क्स—के लिये इस साल १४,८४,७०००) रुपये की रकम रखी गई है। हमारी सरकार की अनुपम कृपा हुई कि ३७,०००) रुपये से बीकानेर में एक इन्डियन कौन्सिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च फार्म का कन्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसके लिये हमें सरकार का आभार मानना चाहिये। सरकार जोधपुर में भी एक फार्म खोल रही है। इस तरह से ६९,०००) रुपये बीकानेर जोधपुर के लिये खर्च करके सरकार ने बड़ी कृपा की है।

अब मैं आपका ध्यान केपिटल आउटले से सिविल वर्क्स के संबन्ध में आकर्षित करता हूं। मैं यह कहूंगा कि ६०,००,०००) रुपये की रकम इस साल के बजट में रखी गई है। इसमें हमारे बीकानेर के लिये ९,५०,०००) रुपये की रकम बीकानेर से गंगानगर तक कच्ची सड़क बनाने के

[श्री जसवन्तसिंह]

लिये दी है। मैं समझता हूं कि इसका बिल्कुल दुरुपयोग होगा। कंकर की सड़क एक दो साल बाद बिलकुल खराब हो जावेगी और सड़क की हालत ज्यादा खतरनाक हो जायगी। भोला दोस्त दुश्मन की गरज साजे, वह हालत हो जावेगी।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या हाउस में सोना एक अच्छी प्रणाली है।

श्री जसवन्तसिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो सड़क दो तीन साल तक चलने के बाद ऐसी खतरनाक हो जावेगी कि उस पर चलना मुश्किल हो जावेगा तो फिर उसको बनाने से फायदा क्या?

आप आगे चलिये।

कन्सट्रक्शन ऑफ इरिगेशन, नेविगेशन, एम्बेंकमेंट एन्ड ड्रेनेज वर्क्स:

यह काम पंच वर्षीय योजना के अन्दर में होगा। इसके लिये ८० लाख की रकम रखी गई है लेकिन बीकानेर के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है।

अभी आप देखते जाइये;

केपिटल आउटले ओन इम्प्रूवमेन्ट ऑफ पब्लिक हैल्थ:—इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीकानेर में कोई बीमार होता ही नहीं। इसलिये इस मद में बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है, जहां कि इस मद पर राजस्थान में १,९७,६८० रुपये खर्च किये जावेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं।

अभी आप देखते जाइये कि बीकानेर के साथ हमारी सरकार ने किस प्रकार का बर्ताव किया है।

अब आप केपिटल एकाउन्ट ऑफ सिविल वर्क्स आउटसाइड दी रेवेन्यु एकाउन्ट की तरफ देखिये। इसमें भी २१,५६,१८६ रुपये खर्च करने के लिये रखे गये हैं।

एक सदस्य—On a point of information, Sir, will the Hon'ble Member show how much amount has been given to Bikaner in respect of Bhakra Nangal Project.

श्री **जसवन्तसिंह**—It is not inside Bikaner Division. It is in the Himalayas. इसका भी जवाब दूंगा।

इसमें १,५५,०००) की रकम सरकार ने बड़ी कृपा करके गंगानगर से पदमपुरा तक सड़क के लिये मंजूर की है और इसका श्रेय श्री गुरुदयालसिंह संधु साहब को है कि उनकी वजह से गंगानगर-पदमपुरा की सड़क के लिये मंजूरी हो गई।

अब आप फिर सुनिये, सुनते जाइये।

[श्री जसवन्तसिंह]

केपिटल एकाउन्ट ऑफ अदर स्टेट वर्क्स आउटसाइड दी रेवेन्यू एकाउन्ट रीहेबिलिटेशन:—इस मद में भी १४,१२,०६८) रुपये की रकम रखी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास-- (श्री मथुरादास माथुर के मन्त्री वर्ग की बैंचेज पर बैठने पर) On a point of information, Sir, I thought a new person has been included in the Cabinet.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Your thoughts run very fast !

श्री हरिकृष्ण व्यास--The Member ran faster than my thoughts.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--I sympathise with your slowness.

श्री जसवन्तसिंह--(अपना भाषण जारी रखते हुए) टेनेमेन्ट्स और शॉप्स बीकानेर और गंगानगर में बनने वाले हैं। इसके लिये २,०५,०००) रु० रखा गया है। इसका सम टोटल क्या होता है कि इस साल मामूली काम जो इस साल किये जायेंगे इसमें करीब करीब २ करोड़ रुपया रखा गया है खर्च करने के लिये, उसमें से सिर्फ १४॥ लाख रुपये बीकानेर के हिस्से में आये हैं। इन १४॥ लाख रुपयों में से १२ लाख ऐसे काम के लिए रखे गये हैं जो फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको अपने शरीर को सुरक्षित रखना है तो आपको अपने शरीर के सारे अंगों की परवाह करनी पड़ेगी और बीकानेर के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जायगा तो बीकानेर शायद ही आपके साथ मित्रता का भाव रखे। हमने कुसूर क्या किया ? हमने जो कुसूर किया वह यह है कि जिस वक्त बीकानेर मर्ज हुआ तो हमारे गाढ़े पसीने की कमाई ५ करोड़ रुपये की रकम को हमने राजस्थान को जरूर दी। यह हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं तो वही ५ करोड़ रुपये की रकम बीकानेर की जनता के लिये उन्हीं में वितरित की जाती तो कितना अच्छा होता। उनके गाढ़े पसीने की कमाई उनके काम आती। उन्होंने मेहनत की और लाभ दूसरे उठा रहे हैं। हमारा जो वाजिब हक है वह भी हमें नहीं दिया जाता है।

मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार एक ऐसी जनप्रिय सरकार है तो उसका यह कर्तव्य बन जाता है, अगर वह लोकप्रिय सरकार है, कि उनके प्रति राजस्थान के लोग अच्छा विचार रखें। हमारे मंत्री इस वक्त अपने बड़े बड़े महलों में सोचते होंगे कि राजस्थान में बड़ा चैन और सुख हो रहा है, यहां पर किसी बात की कमी नहीं है, राजस्थान की सब जनता खुश है; लेकिन मैं आपको यह बतलाऊं कि आप इतनी दूर ही नहीं जायं, आप अपनी सर्विसेज को ही देखें। आपके मुतल्लिक आपकी सर्विसेज के क्या खयाल हैं, इस पर एक मिनिट के लिए गौर कीजिये; जनता तो बहुत दूर है। इस तरह से आप अपने शरीर के अंगों के साथ अलग व्यवहार करेंगे तो उसका तो आपको नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपकी जो सर्विसेज रात दिन आपके कॉन्टेक्ट में आती हैं उनका खयाल आपके लिये क्या है। जब वह बड़े बड़े

[श्री जसवन्तसिंह]

अफसर लोग मिलते हैं और बातें करते हैं, और उनकी बातों को आप खुफिया तौर पर सुनें, तो एक मिनिट भी ऐसा नहीं होगा जहां कि सरकार की आलोचना नहीं होती हो। वह यह है कि हमारी सरकार कैसी गंदी सरकार है। उनको संतोष देने के लिए आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप उनको संतुष्ट करें; लेकिन हमारे कर्यालय में ऐसी सूचना आई कि ५-६ महीने पहले हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिये एक हिदायत जारी की कि अगर कोई सरकार की कटु आलोचना करेगा तो उनके साथ सख्ती की जायगी। इस तरह की हिदायतों से वे अफसरों के असंतोष को मिटाना चाहते हैं तो वे बड़ी भारी भूल करते हैं। मैं आपको मित्र के नाते यह कहना चाहता हूं कि आप अपने घर को सम्हालिये, आप अपनी सर्विसेज को सम्हालिये। उनके प्रति आपको सद्भावना रखनी पड़ेगी। इसके बाद में जो राजस्थान की इतनी बड़ी जनता है उसके साथ जो व्यवहार होता है उस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो हमें यह स्वप्न दिखाये गये थे कि राजस्थान बनने के बाद सोने की लंका ही दिखाई पड़ेगी किन्तु आज यहां दुर्भिक्ष, भूखों मरने और अनेकों कष्ट उठाने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। ऐसी हालत में हमारी सरकार थोड़े दिनों तक भले ही खुश रह सकती है लेकिन यह खुशी ज्यादा निभने वाली नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि वे अपने सब अंगों को अपने शरीर की तरह एक समान देख कर समान व्यवहार करे। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री खेतसिंह—(श्री गोपीलाल यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा खयाल है कि मैंने आपकी लोचन शक्ति को पहले पकड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री यादव।

श्री खेतसिंह—मैं तो एक ही मिनिट में चिलम भर दूंगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, बजट स्पीच जब मैंने अपने माननीय प्रधान मंत्री के मुंह से सुनी तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और म यह सोच रहा था कि उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा बजट तैयार किया है, लेकिन जब मैंने उस बजट को देखा तो मुझे बड़ी निराशा हुई और दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता हैं कि उस बजट के अन्दर ऐसी बातें रखी गई ह, और वह बजट इस तरह से बनाया गया है कि कम से कम वैसा नहीं बनना चाहिए था।

उस बजट की मुख्य २ विशेष बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यह हैं:—

(१) सबसे पहली बात यह है कि यह बजट एक धोखे का बजट है। इसमें वास्तविकता को छुपाया गया है और आंकड़ों की जगलरी यानी बाजीगरी की गई है।

[श्री गोपीलाल यादव]

(२) दूसरी चीज यह है कि इस बजट को जो बेलेन्स्ड बजट दिखाया गया है, यह गलत है। यह एक बड़े भारी घाटे का बजट है।

(३) तीसरी बात, इस बजट को कल्याणकारी बतलाया गया है जो स्वराज्य की तरफ एक कदम है; पर वास्तव में वह ऐसा नहीं है। उस तरफ एक छोटे से छोटा कदम भी नहीं लिया गया है।

(४) इसके अलावा चौथी बात जो इस बजट में है वह यह कि गरीब किसान जो कि टैक्स के बोझ से लदे हुए हैं उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि उनके बोझ को बड़े भारी नये २ एग्रीकलचर इनकम टैक्स और ऐसे दूसरे टैक्सों को बढ़ाकर बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है।

(५) पांचवी बात जो इस बजट की है वह यह है कि यह बजट अमीर और गरीब के बीच की खाई का काम नहीं करता है।

(६) छठी बात जो इस बजट म दिखती है वह यह है कि शासन के करने में जो फिजूल खर्ची होती थी वह बदस्तूर कायम रखी है।

(७) सातवीं बात इस बजट में यह है कि लोअर ग्रेड के क्लार्क्स, चपरासी और जितने छोटे २ मुलाजिम हैं उनको लिविंग वेजेज देने का जरा भी कोई प्रयत्न नहीं किया है। उनके लेबर का एक्सप्लॉइटेशन उसी तरह से किया जा रहा है; उन्हें भूखों मारते हुए काम कराये जाने का प्रयत्न है।

(८) यह बजट हमको बताता है कि सरकार सेन्टर से सहायता लेना तो दरकिनार उनसे कर्जा तक लेने में असमर्थ रही।

(९) नवीं बात यह है कि जो रुपया हमको सेन्टर से वाजिब तौर पर पाने का अधिकार था उसको भी हम नहीं ले सके हैं।

(१०) दसवीं बात इसकी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो जकात हमको धीरे २ ५ साल में कम कर देना चाहिए था उसमें एक पर्सेन्ट भी कमी इस बजट में नही दिखलाई गई है।

(११) ग्यारहवीं चीज यह है कि जनता में बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने के लिए, उनको दूर करने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया ह।

(१२) बारहवीं बात इस बजट में यह है कि यह बजट ३ साल के बाद इस बात को स्वीकार करता है कि राजस्थान का राजस्थान के इन्टीग्रेशन का जो उद्देश्य था वह असफल

[श्री गोपीलाल यादव]

साबित हो गया है, और इस तरह हम खर्चा कम करके जनता की भलाई का जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न हमारा गलत था; हमने खुदने मान लिया है।

(१३) तेरहवीं बात इसमें खामी की यह है कि जो करीब साढे उन्नीस करोड़ की संचित पूंजी राजस्थान सरकार को भिन्न भिन्न रियासतों से मिली थी उसमें से एक तिहाई पूंजी राजस्थान सरकार द्वारा खत्म की जा चुकी है और बाकी की भी करीब तीन चार साल में खत्म करके सरकार बिल्कुल दिवालिया हो जायेगी।

श्री एच. के. व्यास--बाकी बची हुई पूंजी भी कर्ज पर गिरवे रखी हुई है।

श्री गोपीलाल यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें बताई हैं उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जाय कि यह कोरा क्रिटिसिज्म है। जब मैं बजट के आकड़ों पर आता हूं और प्रत्येक के सम्बन्ध में बातें बताता हूं तो आपको यह पता चलेगा कि यह बजट एक धोखे का बजट है; इसमें वास्तविकता को छिपाया गया है।

सबसे पहली चीज यह बतायी है कि १२४० लाख यानी १२,४०,००,०००) (बारह करोड़ चालीस लाख) रुपया जनहित के कार्यों में खर्च किया जायेगा। मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई और जब पत्रकार मिले तो मैंने कहा कि यह बजट पहले से अच्छा है कि इसमें जनहित के कार्यों के लिये इतनी बड़ी रकम रखी है। पर जब मैंने बजट को देखा तो मालूम हुआ कि इस बड़ी रकम की आधी रकम जनहित के कामों के लिये मिलती है। यह बात मैं बजट में जो आंकड़े दिये गये ह उनके आधार पर बताऊंगा। पहले म, जनहित के कामों के लिये जो रकमें रखी गई हैं, उसके आंकड़े में बता देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं।

सबसे पहली चीज जो जनहितकारी कामों से सम्बन्ध रखने वाली है वह शिक्षा है।

शिक्षा	२,६१ लाख
मेडिकल	१,१७ लाख
पब्लिक हैल्थ	४५ लाख
एग्रीकल्चर	३४ लाख
रूरल डेवलपमेण्ट	१३ लाख
वेटरनरी	१२ लाख
कोऑपरेशन	७ लाख
इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज़	१९८५०००
मिस्लेनियस	३४ लाख
कोम्युनिटी प्रोजेक्ट	६२ लाख

Page No.51

[श्री गोपीलाल यादव]

कुल ६३९ लाख रुपया होता है। इसमें (बजट में) १२४० लाख बतलाया गया है, वह कहां है। किया क्या गया है कि केपिटल एक्सपेंडिचर जो बन्धों, सड़कों आदि पर करीब ७०० लाख होना है उन तमाम को भी जनहितकारी कामों में जोड़ दिया गया है, जिनका कि शासन से संबन्ध है। पुराने राजाओं के बजट में भी जनहितकारी कार्यों में इसको नहीं रखा गया था। तो इस तरह केवल ६३९ लाख रुपया जनहितकारी कार्यों के लिये रखा गया है; बाकी सब केपिटल एक्सपेंडिचर में है। अगर जनहितकारी भी समझा जाय तो केपिटल एक्सपेंडिचर में सालाना कम खर्चा आयेगा।

२९१ लाख रुपये शिक्षा पर लगाये गये हैं और कहा गया है कि राजस्थान बनने से पहिले राजस्थान में मिली रियासतों में कुल मिलाकर १६१ लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता था। इसको देखकर हर एक देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि राजस्थान सरकार शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है परन्तु इसमें वास्तविकता कुछ और है। इस २९१ लाख की रकम में ४० लाख रुपया तो वह है जो ५ साल की योजना में राजस्थान सरकार को सेंटर दे रहा है, जिसका हमारी राजस्थान सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त रकम में से इन ४० लाख रुपयों को निकाल दिया जाय तो २५१ लाख रुपये रह जाते हैं। जब चार साल पहिले शिक्षा पर १६१ लाख का खर्चा राजा लोग करते थे तो उस समय राजस्थान का दो तिहाई हिस्सा जो जागीर का हिस्सा था वह इसमें शामिल नहीं था। अब वह दो तिहाई हिस्सा भी शामिल कर दिया गया है तो ऐसी हालत में ३ करोड़ रुपया तो शिक्षा पर इस औसत से ही हो जाना चाहिये और इस चार साल के अर्से बाद के नये ग्रेड वगैरह देते हैं। तो कम से कम पुराने राजाओं द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाले खर्चे की औसत ढाई करोड़ और अगर जागीर एरिया शामिल कर देते हैं तो ४ करोड़ रुपये से ऊपर होती है। पर ऐसा नहीं किया जाकर आज हमें सेंटर की सहायता जो कि एक विशेष सहायता है उस ४० लाख की रकम को भी इसमें जोड़ दिया गया है। होना तो यह चाहिये था कि जब सेंटर ४० लाख रुपया शिक्षा के लिये देता है तो ४० लाख का और अपनी ओर से प्रबन्ध करके शिक्षा पर लगाये, पर राजस्थान सरकार ऐसा नहीं करती।

इसी तरह तमाम महकमों, मैडिकल, पब्लिक हैल्थ, एग्रीकल्चर आदि के लिये जो रकम रखी गई है उन आंकड़ों को पुरानी रियासतों के आंकड़ों से कम्पेअर करके देखेंगे तो पता चल जायेगा कि ये रकमें बहुत थोड़ी हैं।

इससे सम्बन्धित एक दूसरी बात के बारे में अभी मेरे मित्र, अपोजीशन के नेता ने कही और मुख्य मंत्रीजी को बधाई दी। बधाई तो मैं उसके लिये नहीं देता क्योंकि वह एक गलती है वह बात यह है कि मिनिस्टरों की मोटरों के मेन्टनेन्स पर जो रखा है उस हिसाब से २५०) रुपये माहवार होते हैं। मेरी समझ में ये ३ हजार रुपये सालाना एक एक मिनिस्टर को भी दे दिये

Page No.52

[श्री गोपीलाल यादव]

जायं तो ठीक है। पर दर असल यह रकम वास्तविकता को छुपाने के लिये रखी गई है। पिछली बार बहुत अधिक क्रिटिसिज्म हुआ इसलिये क्रिटिसिज्म से बचने के लिये इस मद में इतनी सी रकम रखी और दूसरी तरफ से इसके लिये रकम दूसरी रकमों में से ले लेंगे; इस तरह की रकम इस बजट में रखी हैं। तो इस तरह जैसा कि श्रीमान् राजप्रमुख ने कहा कि यह आपकी योग्यता को चेलेंज है, उसी योग्यता से मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को रखा है जो हमारी इन्टेलीजेंस के लिये चेलेंज है। (हंसी)

इसके अलावा दूसरी चीज लेता हूं कि यह बजट बैलेन्स बजट नहीं है। इसमें १९४० लाख की आमदनी और १९४० लाख का खर्चा बताया गया है। दोनों बराबर बताया पर जब आप ५०० लाख रुपये केपीटल एक्सपेन्डीचर की ओर ध्यान देते हैं तो आपको मालूम होगा कि वह खर्चा है, बचत नहीं। इस तरह के खर्चे हमें राजस्थान जैसे प्रान्त में हर साल करने हैं। तो इस तरह राजस्थान सरकार दरअसल २३५० लाख रुपया खर्च कर रही है। उसकी बजाय बजट में १९५० लाख का ही खर्चा बताया गया है, जो गलत है।

इसी तरह देखा जाय तो मालूम होगा कि दर असल बजट में करीब ५००००००) (पांच करोड़) रुपये का घाटा है और रिवाइज्ड बजट, जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स हमारे सामने आयेगी, और आमदनी जो होने वाली बताई गई है वह नहीं होगी, क्योंकि वह आमदनी होने वाली नहीं है, तब इस घाटे का पता चलेगा।

अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। यह बजट वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है। इसके लिए मुझे यह निवेदन करना है कि गरीबों पर जो टेक्स का बोझा पहले था उससे कम नहीं हुआ है। उनकी आमदनी बढ़ाने की कोई चीज इसमें नहीं है। यह ठीक है कि नदी घाटी योजना पंचवर्षीय योजना के अन्दर बताई गई है इसमें कोई शक नहीं कि आगे चलकर इस इलाके के लोगों की आमदनी बढेगी और उस इलाके में गवर्नमेन्ट अधिक टेक्स वसूल कर सकेगी लेकिन जैसा कि मैंने राजप्रमुख महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस के समय कहा था कि हमारे यहां के ८० प्रतिशत लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर नदी-घाटी योजना नहीं बन सकती। जब तक आप उन ८० प्रतिशत लोगों की आमदनी नहीं बढावेंगे तब तक नदी-घाटी योजना से संतोष नहीं हो सकता। जब तक आप ऐसे लोगों के लिए कुओं, तकावी आदि का इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता। तकावी के लिए बहुत थोड़ी रकम इस बजट में रखी गई है।

अब मैं आपका ध्यान सरकार के जो छोटे मुलाजिम हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। इन मुलाजिमों की आमदनी का औसत करीब २०), २५)रु. माहवार पड़ता है। उससे ऊपर उनकी आमदनी किसी भी डिपार्टमेन्ट में नहीं है। मैं यह नहीं समझ सका अब तक कि जब हम वेलफेअर स्टेट बनाने जा रहे हैं तो हमें यह हिसाब क्यों नहीं लगाना चाहिए कि जब हमारे मंत्री जी का खर्चा ५ हजार रुपया माहवार से नहीं चलता तो एक चपरासी का २५ रुपया माहवार से और एक लोअर ग्रेड बाबू का खर्चा ५०) माहवार से कैसे चल सकता है? जब तक आप इसका कोई प्रबंध नहीं

[श्री गोपीलाल यादव]

करते कि उनको लिविंग वेजेज तो दें जिससे कि उनको मामूली आटा, मामूली लकड़ी, मामूली कपड़ा और उनके बच्चों के लिए मामूली शिक्षा का प्रबंध हो सके, तब तक आप वेलफेअर स्टेट कैसे बना सकते हैं ? पांच आदमियों के एक परिवार के लिए बहुत थोड़ा खर्चा किया जाय तो भी कम से कम १५०) रु० माहवार तो चाहिए ही । इस पर यदि यह कहा जाय कि उनकी औरतों को मजदूरी करके कुछ कमाना चाहिए तो आप ५०) रु० उनके लिए बाद दे दीजिए फिर भी कम से कम १००) रु० माहवार उन्हें आपको देना ही चाहिए, लेकिन आप नहीं देंगे। कहेंगे कि हमारे पास रुपयों की कमी है । ठीक है। आपके पास रुपयों की कमी है। परन्तु रुपयों की कमी के कारण आप फिजूल खर्च को तो मिटा नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजूल खर्चा कैसे मिटा सकते हैं । अनेकों डिपार्टमेन्ट हैं जिनमें बहुत सा रुपया फिजूल खर्च किया जा रहा है। उन्हें अगर तोड़ दिया जाय तो बचत होगी और तोड़ने से कोई नुक्सान भी नहीं होगा। इन फालतू विभागों में से एक तो है रिहेबीलिटेशन डिपार्टमेन्ट, दूसरा सिविल सप्लाइज डिपार्टमेन्ट, तीसरा एन्टी करपशन डिपार्टमेन्ट, चौथा लैन्ड रेकार्ड डिपार्टमेन्ट तथा पांचवां एन्टीस्मगिलिंग डिपार्टमेन्ट । इसी तरह से और भी कई डिपार्टमेन्ट्स हैं। उनका काम दूसरे अफसरों के जरिए से किया जा सकता है जो बेकार बैठे हैं। बहुत से आपके मजिस्ट्रेट्स हैं जैसे एक्सट्रा मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट इन तमाम की पल्टन भरी हुई है। तहसीलदारों के क्रिमिनल पावर्स छीन लिये गये हैं और वे बेकार बैठे हुए हैं। नायब तहसीलदारों के पास कोई काम नहीं है। लैंड रेकर्ड्स के अफसरों के पास कोई काम नहीं है। उनका जो काम है वह तहसीलदार, एस. डी. ओ. या कलेक्टर करते हैं। इस तरह से जो फिजूल खर्चा किया जा रहा है उसे रोकना चाहिए। अफसरों की तन्ख्वाओं का तो आपके पास हिसाब है परन्तु उनके टी.ए. और डी.ए. का कोई हिसाब है क्या आपके पास? इसका आप यदि हिसाब लगावेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कितना फिजूल खर्चा होता है। आप एक ऑर्डर निकाल दीजिये कि उसमें ७५ प्रतिशत कमी करनी है। टी.ए., डी.ए. की कमी से आप लाखों रुपये सेव करेंगे और अपने अफसरों का इतना टाइम सेव करेंगे कि वे उस टाइम को लगाकर पब्लिक का काम निकाल सकेंगे। टाइम की इस कमी के कारण जो काम सफर करता है वह सफर नहीं होगा । यहां के अफसर अपना टाइम फिजूल खर्च करते हैं। कोई ऊपर का अफसर डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उसका टाइम तो खराब होता ही है पर नीचे के अफसर जो उसकी हाजरी म रहते हैं उनका समय भी व्यर्थ जाता है। यदि कोई मिनिस्टर किसी जगह पहुंच जाते हैं तो कई अफसर उनके स्वागत के लिये वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह कितने ही रुपये टी. ए. और डी. ए. में फिजूल खर्च हो जाते हैं। हमने पहले के शासन भी देखे हैं और अब भी देख रहे हैं। उनसे यदि पूछा जाता है कि आप दौरा क्यों करते हैं तो उत्तर देते हैं कि नीचे के अफसरों की गलतियों को पकड़ने के लिये और उनको ठीक तरह से काम करने का तरीका बताने के लिये और सुझाव देने के लिये दौरे करते हैं। इस तरह के इन्सपेक्शन साल में एक बार हो जावें तो भी काफी है। एक बार आप इन्सपेक्शन कर लीजिये और एक एक बार नीचे के अफसर करलें तो काफी है। पर दरअसल दौरे करने का मकसद कुछ और ही है । यदि यात्रा के लिये मथुरा जाना है तो भरतपुर का दौरा रख दिया जाता है। आपको यदि बीकानेर में मीटिंग करनी है तो सभी लोग वहां भगे चले जायेंगे। इस प्रकार के

[गोपीलाल यादव]

टी.ए. में यदि कमी करेंगे तो ७५ प्रतिशत कमी हो जायेगी। मिनिस्टरों पर ७५ प्रतिशत कमी कर सकते हैं। ७५ प्रतिशत कमी करने का कहने पर आप यह खयाल करेंगे कि उनकी तनख्वाह एक हजार है सो उसे घटाकर २५० रु० करने का कह रहे हैं पर यह बात नहीं है। वेतन में कमी मत कीजिये पर उनके साथ जो फिजूल खर्चा लगा हुआ है उसे कम कीजिए। आपके बजट में ११-१२ मिनिस्टरों का खर्चा रखा हुआ है। इन बारह आदमियों के बजाय ६ या सात मिनिस्टर ही रखे जावें तो आधा खर्चा कम हो जायेगा। इसके अलावा एक एक मिनिस्टर के बंगले पर बिजली का खर्चा डेढ़ हजार रुपया सालाना लगता है और इसी तरह के और कई खर्चे उनकी कोठियों पर पड़ते हैं। इन सबके बजाय उनको केवल २५०) रु. माहवार मकान किराया के तौर पर दे दिये जावें तो खर्चे में काफी कमी हो सकती है इसके अलावा यदि वे ट्रेवलिंग में कम खर्चा करने लगें तो भी काफी सेविंग हो सकती है। इस तरह से कुल मिला कर ७५ प्रतिशत नहीं तो ६० प्रतिशत कमी तो मिनिस्टरों के खर्चे में भी हो सकती है।

इसके अलावा जितने डिवीजनल ऑफिसेज़ हैं वे सिवाय पोस्ट ऑफिस के काम के दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। कमिश्नर को एक दरख्वास्त दीजिये वह उसे कलेक्टर के पास भेजेगा और कलेक्टर उसे एस.डी.ओ के पास भेजेगा और एस.डी.ओ. तहसीलदार के पास भेजेगा तथा वह तहसीलदार गिरदावर व पटवारी के पास भेजेगा और वहां से वापिस चलते चलते दरख्वास्त कमिश्नर के पास पहुंचेगी और कमिश्नर साहब यह ऑर्डर देंगे कि पटवारी की राय ठीक है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय। फिर इतने अफसर क्यों रखे जाते हैं। सैकड़ों कागज एक मामूली काम के लिए बन जाते हैं जो कई जगहों पर दर्ज होते हैं और कई आदमियों को टाइम लगाना पड़ता है। यह हालत देखते हुए डिवीजनल ऑफिसेज़ बंद किये जाने चाहिये। आपको अपने रूल्स में इस तरह का एमेन्डमेंट करना चाहिए कि जिस चीज से एस.डी.ओ. या इसी तरह के दूसरे अफसर का ताल्लुक नहीं है वह उसकी मारफत नहीं पूछी जाकर सीधी ही तहसीलदार आदि संबंधित व्यक्ति से पूछी जानी चाहिए। इससे काफी समय और पैसे की बचत होगी।

तो आप इस तरह से अगर इस चीज को करते हैं तो बहुत कमी आप इस चीज में कर सकते हैं। इसके अलावा सब से बड़ी चीज पॉवर को डिसेन्ट्रलाइज करना है। इस वक्त यह हो रहा है कि आप लोग ही सब पॉवर्स को लेकर बैठे हैं। राजाओं के जमाने में यह होता था कि राजा को सब पॉवर्स होते थे। उनके पास कोई भी आदमी जा सकता था और अपने दुख-दर्द सुना सकता था और उसका निदान भी हो सकता था। उस समय के राजा लोगों की पोजीशन आज के एक कलेक्टर से ज्यादा नहीं थी। जिस तरह से आज एक जिले के कलेक्टर से हर कोई मिल सकता है उसी प्रकार पुराने जमाने में राजा लोगों के पास भी सभी कोई जा सकते थे और वे उस चीज को मिनटों में तय कर दिया करते थे। उस समय पॉवर सेंट्रलाइज नहीं थी। आप यदि अपने पॉवर कलेक्टर को दे दें तो बहुत ही सहूलियत हो सकती है। आज कलेक्टर के पास पॉवर नहीं, इंजिनीयर के पास पॉवर नहीं, प्रिन्सिपल के पास पॉवर नहीं। अगर इन विभागों में कागजों की भी जरूरत हो तो यहां पर लिखा जाता है। २००), ३००) रुपये की स्टेशनरी तक वे नहीं

Page No.55

[श्री गोपीलाल यादव]

खरीद सकते। इस तरह के मामूली खर्चे भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेण्ट नहीं कर सकते । मेडिकल को ले लीजिये। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर को यह पॉवर नहीं कि वह जरूरत की औषधियां मंगा सके। उसे उसके लिये यहां चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं। यहां से जवाब नहीं आता है तो आदमी भेजना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि कितना अन्धाधुन्ध खर्चा हो रहा है, इसको क्या कहा जाय ? अगर इसे बेवकूफी कहता हूं तो इससे अच्छा पार्लियामेण्टरी शब्द समझ में नहीं आता । यह जो खर्चा हो रहा है, यह जो अन्धाधुन्ध गलतियां हो रही हैं उनके लिये क्या कहा जाय; समझ में नहीं आता।

अब मैं, इसके अलावा, खर्चे में बहुत सी कमियां किस प्रकार की जा सकती हैं, आमदनी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, यह बतलाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट ने अभी इनकम टैक्स की जो लोअर लिमिट थी उसको ऊंचा कर दिया है। वह लिमिट चार हजार की जगह चार हजार दो सौ कर दी है। इससे कम आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लिया जायेगा। आप इस रकम को कुछ और बढ़ा दीजिये। अपनी तरफ से उस पर टैक्स लेते रहिये। आप जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने की सोच रहे हैं उससे गरीब किसान लोग दब जाएंगे। उनको दबाने के बजाय आप इस तरह से ज्यादा आमदनी वालों पर टैक्स लगा दीजिये। इस तरह से बहुत बड़ी रकम आप वसूल कर सकते हैं जो आपको बहुत फायदा दे सकती है।

इसके अलावा जो दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रकार का सुझाव मैंने पहले भी दिया था और आज भी दे रहा हूं कि तालीम लाजमी कर दीजिये । दो करोड़ 91 लाख के बजाय आप 6 करोड़ रुपया इसके लिये रखिये। आप डेढ़ करोड़ या एक करोड़ रुपया ग्राण्ट इन एड रखिये। आप यह कह दीजिये कि प्राइवेट इन्टरप्राइज़ यदि स्कूल खोलेंगे तो 60 परसेन्ट गवर्नमेण्ट देगी। अगर आप दो करोड़ रुपया ग्राण्ट इन एड की तौर पर देंगे तो दो करोड़ रुपया वे लगायेंगे। इस तरह से चार करोड़ हो जायेगा । इस तरह से दो करोड़ रुपया पब्लिक की जेब से, प्राइवेट इन्टरप्राइज से आ जायगा। आप कुछ कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन के नाम से टैक्स लगा दीजिये। ऐसा कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो इस प्रकार का टैक्स देने का विरोध करेगा बशर्ते कि वह पैसा आप कम्पल्सरी एजुकेशन म खर्च करेंगे।

एक और टैक्स मैं सजेस्ट करता हूं सिनेमा एबोलिशन टैक्स। आज जितने भी सिनेमा चल रहे हैं वे बन्द कर दिये जायं। इस तरह से करके आप पब्लिक पर महरबानी करेंगे । उसका टैक्स ले लीजिये। जिस घर में एक बच्चा है उससे अगर आप साल में एक रुपया लेते हैं और दो रुपया दो बच्चों वाले घर में आमदनी के हिसाब से लेते हैं तो इस प्रकार यह टैक्स एडजस्ट हो जायेगा। इस तरह से कर के आप जनता के चरित्र को ऊंचा उठायेंगे और प्रान्त की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। आप अगर सिनेमा में जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक व्यक्ति अपने बाल बच्चों को साथ लेकर सिनेमा नहीं देख सकता। बदकिस्मती से मैं एक दफा सिनेमा म चला गया। मुझे आधे में ही उठकर चला आना पड़ा। बच्चे और बाप सिनेमा में एक साथ बैठकर नहीं देख सकते । सिनेमा में बताया

[श्री गोपीलाल यादव]

जाता है डाके डालना, औरतों को उडाना । मनुष्य के चरित्र को नीचे गिराने की तमाम चीजें सिनेमा द्वारा सिखाई जाती हैं । इस तरह से एक व्यक्ति एक सप्ताह में यदि एक बार भी सिनेमा देखने जाता है तो उसका साल भर में जितना खर्चा होजाता है वह भी बच जायगा और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलेगी । इस तरह से एक तरफ जनता का लाखों रुपया बचा सकेंगे और लाखों रुपया फेमिली बजट में रहा करेगा । इससे जनता का चरित्र भी बचेगा और आपको टैक्स भी मिल जायेगा ।

इसके अलावा एक आमदनी का जरिया में आपको और बता सकता हूं । वह यह कि आज लाखों बीघा जमीन राजस्थान में ऐसी पड़ी है जो किसानों को बांटी जा सकती है । पहले भी बेची गई है लेकिन उसके कुछ नियम नहीं बनाये गये । मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है । चाहे जिसको आप दें किन्तु इतनी तसल्ली अवश्य होनी चाहिये कि अगर 'ए' के पास जमीन नहीं है और 'बी' के पास भी नहीं तो दोनों को मिलनी चाहिये न कि 'ए' को देकर 'बी' को टाल दिया जाय ।

समय-समाप्ति सूचक घण्टी

श्री गोपीलाल यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे कम से कम पैंतालीस मिनिट तो दिये जाने चाहिये । अभी तो मैं समझता हूं कि करीब २५ मिनिट ही मुझे हुए । दूसरी चीज यह है कि मैं जो सुझाव आपको दे रहा हूं यदि वे आपको अच्छे नहीं लगते हों तो मैं अभी बैठ जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--आप पांच मिनिट और बोल सकते हैं ।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि लाखों बीघा जमीन जो बेकार पड़ी हुई है उसको बांटने के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय; जो किसानों में जमीन बांटे उसका रुपया पांच वर्ष की किश्तों में ले लिया जाय । पहले इस जमीन के लिये जागीरदार जमींदार कई गुना टैक्स लिया करते थे । आपको इसमें लेने में क्या हरजा है । इस तरह से आप करोड़ों रुपया जमा कर सकते हैं । यह कोई बेइन्साफी नहीं, यह कोई जनता पर बोझा नहीं । आपकी नजूल की सम्पति करोड़ों रुपयों की राजस्थान के शहरों और बाहर बिखरी पड़ी है । उसका इन्तजाम ठीक न होने से मेन्टीनेन्स के लिये नौकरों आदि की कमी होने से इस सम्पति का नुकसान हो रहा है । जिस वक्त नजूल की सम्पति नीलाम कर दी जायेगी नजूल डिपार्टमेण्ट का खर्चा बच जायगा और इस तरह से करोड़ों रुपयों की आमदनी हो जायेगी । इस तरह नजूल की इमारतों को बेच कर काफी रकम बच सकती है ।

अतः मैं इतना ही कह कर इसको समाप्त करता हूं कि बजट जिस ढंग से बनाया गया उसमें टेक्सेज को छिपाया गया है गरीबों को उससे कोई राहत नहीं हुई है । आपने । कहा था

Page No.57

[श्री गोपीलाल यादव]

कि हम एक वेलफेयर, क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वह मकसद इस बजट से पूरा नहीं होता। मेरे काबिल मित्र और मंत्रीजी स्वयम् महसूस कर रहे हैं कि बाहरी में कुछ नहीं किया गया है और वे कहेंगे कि इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री तनसिंह—हमारी विधान सभा में पेश होने वाले द्वितीय वर्ष के बजट पर सदन में जो आकर्षक भाषण होने चाहिए थे वे माननीय मुख्य मंत्रीजी और विरोधी दल के नेता कर चुके हैं। इन दोनों, एक सदन के नेता और दूसरे विरोधी दल के नेता, के भाषण होने के बाद में बहुत कम ऐसा बचता है जो दूसरे लोगों के लिए आवे क्योंकि ये दो बड़ी चक्की के पाट हैं जिसमें पिसने के बाद दाना शायद ही कोई बचता हो और यदि बचता है तो इसलिए कि उसको कोई खास कारण हों पिछली बार विरोधी दल के नेता ने बजट का जो क्रिटिसिज़्म किया था वह बड़ी निर्दयता के साथ किया था और इस बार दयनीयता से। शायद इसलिए दयनीयता से किया कि मुख्य मंत्रीजी उनके पुराने मित्र हैं, या शायद इसलिए कि दोनों पार्टी के बीच में एक सम्बन्ध होता है; यानि ऊपर के पाट का सम्बन्ध उस खीले से होता है जिस खीले पर थोड़ा सा बजन जाने पर वह हल्का हो जाता है और सम्भवत: उसी स्थान पर कुछ वजन की ठोकर लगने से ऊपर का पाट हल्का हो गया हो और शायद उसी वजह से दो एक कण बच गए हैं।

("कौनसे कण हैं" इस तरह की आवाज)

कण कौनसे हैं यह तो आप स्वयम् ही अनुमान लगा लीजिए।

तो उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन कण ऐसे रह गये हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। पहिले तो विरोधी दल के नेता ने यह बताया कि पहिले तो बजट एक मंत्री द्वारा पेश हुआ था और इस बार मुख्य मंत्रीजी द्वारा पेश हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी दृष्टि से तो उधर बैठने वाले मंत्री ही हैं।

("८९" इस प्रकार की आवाज)

८९ नहीं ९० समझ लीजिए; इस प्रकार साधारण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये और इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पेश किये गये बजट में कोई अन्तर नहीं है। कारण इसका यह है कि बजट की नीति मुख्य मंत्रीजी की हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम यह देखते है कि उधर की ओर बैठने वाले जितने भी हैं वे सब मंत्री का स्तर रखते हैं। इसलिए मैं तो यह भी मानता हूं कि उधर की ओर बैठने वाले यदि पत्थर भी पानी में डाल दें तो वे भी तैरने लग जायं। और इधर का जहाज भी हो तो मुझे शक है कि शायद वह भी पानी में तैरे दूसरी बात यह भी है कि आज कल जो गृह मंत्री हैं और उस समय जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने पिछले सेशन में यह बतलाया था कि एक साधारण सी बात पर, जोधपुर दरबार की मृत्यु होजाने पर जुलूस निकाला गया था, राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से। अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक लाभ तो समय आने पर सभी उठाया करते हैं और इसलिए मैं यह कहूं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में जो अनर्गल प्रचार फैलाया गया था वह किसी राजनैतिक लाभ की दृष्टि से ही फैलाया गया था और यदि मैं यह कहने की धृष्टता करूं तो

[श्री तनसिंह]

भ्रम्य होऊंगा कि यह सब जानबूझ कर किया गया था। आज भी बहुत से ऐसे पहलू हैं। मेरे एक मित्र एक कांग्रेसी मित्र से मिलने के लिए गये थे। कार्य तो उनका यह था कि उन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई मुकदमा था और वह कोई किताब लाने के लिए गये थे। कांग्रेसी मित्र ने मिलते ही कहा था कि आजकल राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है; उन्हें आश्चर्य हुआ। जिस बात के लिए वे गये थे उस बात पर तो बात चीत नहीं हुई और, अचानक किसी दूसरी बात पर बातचीत हो गई। तो इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि जो कुछ वास्तविक हुआ है वह जानबूझ कर किसी निश्चित योजना के अनुसार ही हुआ है। इसलिए जो आर्थिक स्थिति पहिले थी और अब भी है उसमें और इसमें कोई अन्तर पड़ा हो, यह मैं नहीं मानता हूं। यह जरूर हुआ है कि न्याय और व्यवस्था के नाम को लेकर हालत बड़ी चिन्ता जनक बताई गई और उससे विरोधियों को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन (preventive detention) में रख कर राजनैतिक स्वार्थ हल किया गया, ठीक इसी प्रकार अब आर्थिक स्थिति चिन्ता जनक बता कर राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं।

दूसरी बात यह बताई गई है कि पिछली बार तो बजट घाटे का है और इस बार सन्तुलित बजट है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसा अभी बतलाया गया है कि इस सन्तुलित बजट में और इस घाटे के बजट में कोई अन्तर है तो मैं कहूंगा कि कोई अन्तर नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में इधर उधर चर्चाएं फैल रही हैं। एक मित्र ने पहिले कहा था "यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत्" ठीक वही कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं यह नीति देख रहा हूं कि राजस्थान सरकार अपने पैसों पर किस प्रकार लेविशली खर्च की नीति अपनाती जा रही है। वह कभी अपनी इस अर्थ नीति के विषय में गम्भीर नहीं है। एक और उदाहरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय राजस्थान के राजप्रमुख के भाषण पर उस अधिवेशन में धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्रस्तावक महोदय भाषण दे रहे थे उस समय उन्होंने यह कहा था कि इस समय अर्थ विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने हाथ में लेलिया है इसलिये आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है कि दो मंत्री महोदय के चेहरों पर मुस्कराहट थी, जिनके पीछे बहुत संदर्भ था और यह कहना चाहिए कि उनकी मुस्कराहट में कोई असंख्य रहस्य भरे हुए हों। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के घाटे या संतुलन के विषय में कोई भी गंभीर नहीं है अतः इस घाटे में और संतुलन में कोई अन्तर नहीं है।

तीसरी बात जो विरोधी दल के नेता ने बताई थी कि पिछला बजट ऐसा था कि जिसे बहुत नीरस कहा जा सकता है। जो भाषण नीरस था वह उक्त मंत्रीजी ने भी खुद में नीरस होना स्वीकार किया था। इस बार मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिया गया भाषण विरोधी दल के नेता

[श्री तनसिंह]

के कथनानुसार सरस है और इसलिए भी सरस है कि हाउस के सभी सदस्य उपस्थित रहे हैं। खैर। मैं यह जरूर कहूंगा कि सरसता जरूर है और वह सरसता ऐसी है कि एक आदमी हंसने की चेष्टा करता है और चेष्टा में उपक्रम करता है रोने का और उस समय उसके चहरे पर जो सरसता होती है वही हालत हमारे बजट की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसकी गहराई में जायं तो काफी कंगाली है और ऊपर से यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि यह हमारा संतुलित बजट है और इसके द्वारा हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। यह उपक्रम केवल दिखाने मात्र का है।

एक बात और इस बजट के भाषण के संबन्ध में और क्रिटिसिज्म के विषय पर निवेदन करूंगा कि पिछली बार विरोधी दल के नेता ने बताया था कि हमारे बजट के भाषण में आंकड़े नहीं दिए गए हैं और दिए जांय तब ही हम विचार-विमर्श कर सकते हैं। इस बार, अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों की भरमार कर दी गई है। आंकडों का और कागजों का इतना बोझ लाद दिया गया है कि इनको पढ़ने के बजाय अगर सोते समय तकिया बना लिया जाय तो अच्छा होगा। इतना बोझ लाद दिया गया है कि इसको पूरी तरह पढ़ा भी नहीं जासकता। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा और बताया इसको "बाजीगरी" जैसा कहना चाहिए। इसमें केवल आंकड़ों की भरमार है। जो इस बाजीगरी में सिद्धहस्त हैं वे ही इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं तो इन आंकड़ों की बाजीगरी में इतना सिद्धहस्त नहीं हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि इसकी व्यवहारिकता सदन में नहीं, बाहर देखनी चाहिए। अगर इन आंकड़ों की व्यवहारिकता बाहर नजर नहीं आती है तो यही मानना चाहिए कि इनमें सच्चाई नहीं है। इन आंकड़ों में बताया गया है कि इतनी इतनी रकम निर्माणकारी कार्यों में खर्च की जायगी, सरकार इतनी रकम व्यय करेगी, तो वह रकम किस किस हल्के में व्यवहारिक रूप में होती है यह देखने की बात है।

हमारे उस इलाके के अंदर जहां से मैं आया हूं, पिछला बजट पास हुआ है या नहीं यह भी पता नहीं है। अगर हुआ होगा तो भी उनको ज्ञात नहीं है। इसमें जो खर्च बताया गया था वह भी रकम खर्च की गई है या नहीं, इसका भी अन्दाज वहां की जनता को नहीं हो सकता जब तक कि उस क्षेत्र की जनता की आंखों के सामने कोई काम नहीं हो जाता। इस प्रकार अध्य महोदय, हमारे इस प्रान्त में कुछ विशेष कारण हैं। इन कारणों के आधार पर मैं यह साफ कहूंगा कि हमारे प्रान्त में सीमाएं बनाली गई हैं। यह जो आंकड़े हमारे सामने रखे गये हैं उनमें हमें तभी पूर्णतया विश्वास होगा जब कि हमारे सामने प्रोपोर्शनेटली हर स्थान पर वहां की आबादी के लिहाज से या जरूरत के लिहाज से आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र के लिए खर्च किया जायेगा। तभी हम मान सकते हैं कि हमारा बजट ठीक है। उसका क्रिटिसिज्म हम तभी कर सकते हैं जब कि यह साल पूरा हो जायेगा और हम देखलेंगे कि कितना काम हुआ है और किस तरह से हुआ है और कहां हुआ। तभी हम सभी तौर से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आज नहीं।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत साल के बजट के लिये लोगों ने बहुत तरह से क्रिटीसिज्म किया। कइयों ने इसे दुखभरी कहानी कहा, तो किसी ने पुलिस का बजट कहा, किसी ने कहा कि यह अयोग्य व्यक्ति के हाथ से बना हुआ बजट है, तो किसी ने कहा कि यह बहुत घाटे का बजट है। इस बार के बजट में जितनी आय बताई है उतना ही खर्चा बताया गया है। न बचत है और न कमी और न चोर चुरा सकता है। यह बहुत उत्तम बजट पेश हुआ है। इससे मुझे ऐसा ख्याल हो रहा है कि हमारे प्रान्त के कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं····

एक माननीय सदस्य--आपके अच्छे दिन आ रहे हैं·····

श्री खेतसिंह--(अपना भाषण जारी रखते हुए) होसकता है मेरे भी हों। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी इस बजट के पेश होने से अपने को और सारी जनता को कम से कम इतनी तसल्ली आ चुकी है कि अब हमारा प्रान्त का बजट घाटे का नहीं वरन् बराबर का है; चाहे वह ऊपरी ही क्यों न हो। जैसी कि मारवाड़ी में एक कहावत है "मरदों का दिवाला मसानों (श्मशानों) में ही निकला करता है"। अपन कम से कम दीवाला तो नहीं निकाल रहे हैं, जैसे तैसे काम तो चला रहे हैं, बड़ी शान के साथ। इसके अतिरिक्त मुझे सुनकर खुशी हुई कि विरोधी दल के नेता ने यह फरमाया कि इन १२ महीनों में हम जागीरदारी खत्म कर रहे हैं, और प्रोग्रेसिव स्टेप उठा रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि वे जागीरें सरेन्डर कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के दिन और अच्छे आ रहे हैं और जागीरदार समुदाय भी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। (इससे उत्तम क्या होगा) लेकिन बजट का अच्छा होना तभी माना जायगा जब कि उस प्रान्त की जनता को राहत मिले। दर असल बजट में जो पूंजी रखी गई है वह उस कार्य के लिये खर्च हो, जिससे जनता को इमदाद और राहत मिले। इसलिये अक्सर मैं शेरगढ़ का खास उदाहरण देता हूं। हमारे उधर की जनता के लिये कुछ रुपया खर्च किया जायगा तो जनता समझेगी कि वास्तव में बजट अच्छा है, घाटे का नहीं है। इतनी इमदाद दी जाय ताकि वे महसूस कर सकें कि बजट घाटे का नहीं, बचत का है। उनको इतनी मदद दे दी जाय जिससे उनको सन्तोष हो जाय। इस विषय में गत वर्ष कई प्रार्थनायें मौके की थीं। वे मौके थे मैंने जैसे वहां शेरगढ़ में स्कूल खोली जाय, अस्पताल खोले जायं, अकाल के लिये मदद दी जाय, हमको तकावी लोन ठीक मिले, पानी का प्रबन्ध ठीक हो, हमें वहां बीस बीस मील तक पानी नहीं मिलता है। आपको इस चीज के लिये उसको राहत देनी चाहिये। हमें बड़े २ आश्वासन मिले थे कि प्रजातन्त्र का राज है, आपको किसी बात की परेशानी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी का जमाना है हर बात आपकी सुनी जायगी। कई बार हमारे मंत्रियों ने उधर दौरा भी किया, लेकिन इमदाद कितनी दी, यह नहीं कहा जासकता। हमको शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर आप लोग स्कूल के लिये मकान बनवादोगे तो हम हाई स्कूल खोल देंगे। उधर लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी एक मकान बनवाया गया जिसको सुनते हैं, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस् ने हाई स्कूल के लिए एप्रूव कर दिया है। अभी तक उस स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाया। मुख्य मंत्री शायद सुनना चाहते हैं कि वह मकान क्या है। वह मकान बालेसर स्कूल का है। मकान की व्यवस्था बहुत सुन्दर है मौका बड़ा सुन्दर है। अगर वहां एक बार हाईस्कूल बना हुआ देख लिया जायगा तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री जयनारायण व्यास—मैं साल में चार दफा देखा करता हूं।

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता के लिए अर्ज करूं कि वहां अकाल बड़ा भयंकर रहता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां गत सात वर्षों से पानी नहीं बरसा है। उस ओर स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए। बीकानेर की तरफ आपका स्पेशल ध्यान हो सकता है क्योंकि वहां के नेता बड़े बड़े हैं फिर भी हमारी ओर भी कुछ ध्यान दिया जायगा तो हम समझेंगे कि कुछ हमारी ओर भी ध्यान दिया गया है। कोरे लूणकरनसर और नोखा की तरफ ही नहीं, हमारे शेरगढ़ की तरफ भी सरकार ध्यान दे।

तकावी के सिलसिले में जो १० हजार रु० सेंक्शन किये गये हैं वे वहां की हालत को देखते हुए बहुत कम हैं। वहां के लोगों की इतनी नाजुक हालत है कि उनके पास पहिनने को कपड़ा नहीं, बोने के लिए बीज नहीं। अगर उन लोगों को कुछ तकावी के रूप में रकम दी जाती है तो उन लोगों को बैल खरीदने के लिए पैसा मिल सकता है, उनका उपयोग आगामी वर्षाकाल में कर सकते हैं और वहां के लोगों को जीवन निर्वाह की सहूलियत मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि जब कि हमारा बजट बड़ा अच्छा है मुख्य मंत्री कुछ ज्यादा रकम की सेंक्शन दिलवायेंगे।

इसके अलावा अस्पताल के लिए भी कई बार सवाल उठाया गया था। वाकई में वहां अस्पतालों की बहुत कमी है। सरकार की ओर से यह जवाब दिया जाता है कि पांच हजार की आबादी पर अस्पताल खोलने की सरकार की योजना है। मेरा तो निवेदन है कि यदि आप एक लाख पर भी अस्पताल खोलें तो वहां के लोगों को राहत मिल सकती है। अगर आप वहां की एक लाख की आबादी के पीछे भी एक अस्पताल खोल देते हैं तो आपकी योजना सफलीभूत होने लगेगी। वहां शेरगढ़ में सिर्फ एक डिस्पेन्सरी है जिसकी हालत का भी गत वर्ष के बजट के दौरान में मैंने जिक्र कर दिया था। इसके सिवाय १ लाख २० हजार की आबादी वाले इस इलाके में न तो कोई डिस्पेन्सरी है और न कोई आयुर्वेदिक पोस्ट ही है। अगर वहां डिस्पेन्सरी नहीं तो एक आयुर्वेदिक पोस्ट भी खोल दिया जाता है तो कुछ सहूलियत हो सकती है और जनता को यह ज्ञात हो सकता है कि सरकार हमारी ओर तवज्जुह दे रही है, इलाज का प्रबंध कर रही है।

इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जल-कष्ट वहां बहुत है, पानी दूसरे गांवों से लाना पड़ता है। अब तक हालत यह है कि सुबह जल्दी उठकर पानी लाने के लिए जाते हैं जो दूसरे रोज पानी लाकर अपने बाल बच्चों को पिलाते हैं, पांच-पांच सात-सात कोस से पानी लाकर पिलाना पड़ता है। अगर इस विषय में इमदाद दी जाय या बोरिंग मशीन आदि से वहां भी एक दो कुएं खुदवा दिए जायें तो जनता को काफी इमदाद मिल सकती है। कम से कम भी रिलीफ के हेड से भी जल-पीड़ा निवारण के लिए कुछ अवश्य किया जाय ताकि पानी पीने के लिए तो उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट को न केवल बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है बल्कि उसका हिन्दी अनुवाद भी हमें

[श्री खेतसिंह]

दिया है, जिसे देखकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके साथ ही बजट भाषण में काफी सरसता रही है। जिस वक्त भाषण सुन रहे थे तो हमें यह मालूम नहीं हुआ कि यह एक नैराश्य भरी कहानी है या दुखभरी कहानी है। उसे देखते हुए और सुनते हुए हमें काफी हर्ष हुआ। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ईश्वरीसिंह— अध्यक्ष महोदय, यहां लोगों ने बातचीत की बजट री, वा सुनी। बजट की सबांने आ बात पाई गई। अपोजिट पार्टी का नेता ने कुछ जागीरदार हा, वाने बड़ी बड़ी धमकी दी कि कांग्रेस ओ करे है, वो करे है और कही कि यह हो जायगा, वह हो जायगा। मैं पैलां सुन्या करतो हो कि जयपुर में कोई जयपुर देखन आयो और यहां वेंरो मतीजा मिल्यो। वे कही कि काकोजी कोड़े आया। तो वाने कही कि जयपर देखबा आयो। बजट २ बार आयो और राजप्रमुख साब भी आया हा। वाने भी धन्यबाद की बड़ी कोशिश करी। आज मंत्रीजी भी कोशिश कर रिया है (हंसी) परन्तु इणमें जनता रो, मजूरां रो कोई सवाल नहीं आया, यां रो फायदा वोने कोई मिल्या हा। २० साल से दुनिया देख री है। कांग्रेस वाला या कहया करता हा कि या बातां होंगी वा बातां होंगी। हरेक जगा के किसानां रो बाझ बढ गयो है। वे किसान सुखी हो जायला, तो राजस्थान, हिन्दुस्तान में सब सुखी हो जायगा, तो आज कोई भी जिक्र वाके वास्ते नहीं करयो। बात तो आ है कि किसानां रे वास्ते नई नई लागां है वे लाग रही है। मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहूंगा कि एक चारण रे लडको हो। १७,१८ वर्ष रो हो जद वरी आंख्यां खराब होगी। तो वे माताजी के आगे गयो के आंख्यां में फायदा हो जाय तो चारण माताजी थारो रूप थारी नजर से (अश्रव्य)

तो दुनिया में कांग्रेस का राज है। सारां ने फायदा मिल्यो है पर किसानां और मजूरां ने छोड कोई फायदा नहीं मिल्यो। उल्टो किसानां माते नया नया टिकस जिस्या कि तम्बाकू को है पूरा का पूरा ४३) रुपया इसी साल में बढ गया है और हरेक पर बकरी आदि पर लाग लगा दी है। और बजट री बात जिण दिण हुई है वी दिन आ कही है कि २८ लाख रुपया कुआ में हो जायगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं बजट में किसान और मजूरिया की बाता आणी चाहिए। नोकरपेशा है वांकी आणी चाहिजे। नौकरपेशा लोगां ने १८) १८) रुपया मिले हैं। वे १८ रुपया खातर अपना देश छोडकर हजारां कोस जावे है। उणारे लोगांरे वास्ते कोई बात नहीं उठाई गी है। उणाके वास्ते जो लोग नोकरीपेशा है एक पैसा भी नहीं बढाया गया है या फायदा नहीं पहुंचायो है तो मैं जाणूं कि सरकार इण तरह सूं नहीं चलेगी।

दुनिया में सरकार अकाल घोषित करे है। लेकिन जहां जरूरत है वहां नहीं करे है। सीकर इलाका बीकानेर से ३५ कोस यानि ७० मील पर लगा है। वहां पर कई गांव इस्या है जिके में एक दाणा पैदा नहीं हुयो। वो के मा छूट नहीं दी गई है। तो मैं जाणूं कि आप लोग इसी नीति रखोगा तो लगान कतई भी नहीं दिया जायलो।

श्री भैरूंसिंह (केलवा)- माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त स्टेट्स का इन्टिग्रेशन हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई और पटेलजी की काफी तारीफ हुई कि राजाओं को खतम कर दिया

Page No.63

[श्री भैरूंसिंह केलवा]

गया और स्टेट्स का मर्जर बहुत अच्छा हुआ, और हम भी फेडरेशन में सम्मिलित हुए। लेकिन फेडरेशन में सम्मिलित होने की जो जिम्मेदारी पटेल जी की है, उतनी ही राजाओं की है परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रजा भी उनके साथ थी और फेडरेशन का सहयोग इसलिए दिया कि सेन्टर के साथ दूसरे प्रान्तों का जो ताल्लुक है उसी तरह का ताल्लुक हमारे साथ हो जाय और हमारा दुख-सुख जो हो वह सुने। उनको तो हम क्या सुनें। वह जरूर हमारा दुख सुने और इस पिछड़े हुए प्रान्त को भी प्रजातन्त्र के तरीके पर चलाने में उनको कामयाबी हो। तो फेडरेशन में मिलने या किसी प्रान्त में मिलने की जो खुशियां उस वक्त मनाई गई उन्हें नहीं भूलना चाहिए था। राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके लिए खुद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। विशेषताएं जरूर काफी हैं। इस तरफ रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ लम्बे चोड़े हैं जहां मदद देनी चाहिए, भील एरिया है जहां कोई इनकम नहीं होती है, रेगिस्तान में कोई भी इनकम नहीं होती है। राजस्थान जैसे बड़े प्रान्त को देखते हुए उसकी आमदनी कम है। सेन्टर से जो सहायता मिली है वह बिलकुल कम है। मैं यह मानूंगा कि या तो मंत्रीजी में इतनी योग्यता नहीं है कि ज्यादा इनकम लाकर हमारा काम चला सकें या दिल्ली के मंत्री इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। दोनों में से कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। बाकी प्रजातन्त्र के जमाने में यह मानना कि हम खर्चा कम करें और कमी के तरीकों से चलें, यह बिलकुल गलत है। प्रजातन्त्र यानी डेमोक्रेसी का जो तरीका है वह वास्तव में खर्च का तरीका है और उसमें खर्च होता ही है। इस तरह मोटरों में कम खर्चा करो और तनख्वाहों में कमी करो इत्यादि; यह तो एक वाहियात सी बात मालूम होती है। खर्चा होता है, वह होना चाहिए। लेकिन जब पिछड़ा हुआ प्रान्त फेडरेशन में मिल जाता है तो केन्द्र की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका और दूसरों का लेवल एक हो। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा मदद दें। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान का जितना विस्तार और एरिया है, उसमें जितनी समस्याएं हैं, जागीरदारों का सवाल है, माफीदारों का सवाल है आदि अन्य कई चीजें हैं, डकैतों का लेन्ड भी है; इतनी बातें होते हुए भी जो सहायता दी जाती है वह बहुत कम है। तो हमें हिन्दुस्तान के साथ दूसरे प्रान्तों के बराबर मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जिस तरह से हुआ वह ठीक नहीं हुआ। यह बजट गत साल भी देखा था उसमें थोड़ा बहुत हेर-फेर होकर यह बजट आया है। इसमें कोई अन्तर नहीं है। यह तरीका प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है।

इस बजट में हम उम्मीद करते थे कि कुछ तरक्की होगी। इससे यह मालूम हुआ है कि इन बजटों से हमारे राजस्थान का कार्य चलना मुश्किल है और शायद और तरीका हमें अख्तियार नहीं करना पड़े। इसमें खाली आश्वासन दिया जाता है और काम ठीक नहीं होता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पंचवर्षीय योजना रखी गई है। जैसा कि इन्डिपेन्डेंट होने से पहिले कहा गया था कि स्वराज्य मिलने के बाद सब मिल जायगा, दूध, दही की नदियां बहने लगेंगी, उसी तरह पंचवर्षीय योजना के लिए कहा जाता है कि

Page No.64

[भैरूंसिंह केलवा]

पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद सब लोगों को आराम हो जायगा, काश्तकारों की आमदनी बढ़ जायगी, और हरेक काम में आसानी हो जायगी। लेकिन अभी तक की प्रोग्रेस को देखते हैं तो वह निराशाजनक ही मालूम होती है।

यह भी गलत तरीका है कि यहां के कार्य हमेशा केन्द्र से मदद लेकर किये जाते हैं। हम हमेशा राज्यों की तरफ देखते रहे हैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं जानते। इस तरह पंचवर्षीय योजना बना कर आम लोगों की आदत को बिगाडना है कि वे हमेशा राज्य की तरफ देखते रहें। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि यह पैसा भी ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा है। मेरे हल्के में तो बहुत से लोगों की यह शिकायत है कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम भी पार्टी बेसिस पर होता है मेरे एरिया में प्रोजेक्ट हैं और उनके सिलसिले में ऐसा कर रखा है कि हम लोग भी एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर बना दिये गये हैं किन्तु वह शो के लिये ही हैं। उन एडवाइजरी कमेटियों के पास कोई अधिकार नहीं है। दो-चार पटेलों को बुला लिया है और उसमें मुझे भी रख लिया गया है और यह सब नाम मात्र को है। जिस तरह दूसरे महकमों का काम होता है उसी तरह इसका भी काम होता है। वहां दो तहसीलों में २०-२२ लाख की रकम रखी गई है जो कि बिल्कुल नाकाफी है। वहां अगर २ करोड़ की रकम लगाई जाय तो दो तहसीलों में बंध बन सकते हैं, वर्ना फालतू होगा यह रुपया खर्च करना। इससे कोई काम पूरा नहीं होगा और न कोई मतलब ही हल होगा। यादवजी ने जैसा कहा कि लोग अपने गांव छोड कर नहरी इलाकों में जायंगे वह बात सच है क्योंकि लेबर और किसान इतने कंजर्वेटिव हैं कि वे भूखों मरना पसंद करेंगे पर अपना घर छोड कर नहीं जायेंगे। गत अधिवेशन में भीलवाड़ा के संबन्ध में किये गये प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि भीलवाड़ा में अच्छे होर्स पॉवर का पॉवर हाउस तो हैं परन्तु बिजली लगाने के लिये खंभे नहीं हैं, बिजली लगाने के लिये रुपया नहीं है। इसी प्रकार इस तरह की मामूली रकम से शुरू किये गये प्रोजेक्टस का भी यही हाल होगा, वे अधूरे छोड़ दिये जायेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होगा और इन पर लगाया हुआ पैसा इस तरह फिजूल जायेगा। इसके माने यह नहीं है कि मैं कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट्स बनें। मैं इसके पक्ष में हूं। परन्तु बात यह है कि हमारे यहां जो योजनाएं बनती हैं वे अधूरी बनती हैं, पूरी नहीं बनतीं और अगर पूरी बनतीं हैं तो फाइनेलाइज ठीक तरह से नहीं होती और इस तरह इन योजनाओं पर जो पैसा खर्च किया जाता है व्यर्थ जाता है और उससे जो हमें फायदा होना चाहिये वह नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम के लिये जो रकमें दी गई हैं वे इतनी अपर्याप्त हैं जैसे कि हमारे यहां एक कहावत है कि "ऊंट का मांस पकाया जाय और उसमें जीरे का बघार दिया जाय तो जीरे का कुछ पता नहीं चलता" यह कहावत यहां चरितार्थ होती है।

Page No.65

[भैरूसिंह केलवा]

दूसरी बात यह भी है कि इस तरह केन्द्र से सहायता लेते रहने से लोगों में राज्य की तरफ देखने की गुलाम वृत्ति पैदा हो जायगी और लोगों में खुद अपने पैरों पर खड़े होन की भावना पैदा नहीं होगी। डूंगरपुर में कभी फेमिन के नाम से पैसे दिये जाते हैं, कभी किसी नाम से दिये जाते हैं। तो इस तरह करते रहने से वे लोग योग्य भी नहीं बनेंगे और हमेशा सरकार की ओर देखते रहेंगे। जो उत्पादन की योजनायें हैं उनको गौर से देखने पर पता चलेगा कि हमारी आबादी के अनुपात से बहुत कम उत्पादन हो रहा है। ग्रो मोर फूड कम्पेन से कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है वह सरकार के प्रयत्नों से हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। आबादी बढ़ जाने के कारण यह थोड़ा बहुत उत्पादन हो रहा है जो कि आबादी के लिहाज से बहुत कम है।

अब मैं आपके सामने यह बता देना चाहता हूं कि एक दो सीगे तो ऐसे हैं जो महज पार्टी प्रोपेगण्डा के लिये ही हैं। मिसाल के तौर पर जो आठ-दस मंडल बने हुए हैं वे अपने आदमियों को मदद देने के लिये ही हैं उनसे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है।

Excise के लिये पहले भी मैंने एक बार अर्ज किया था तो मजाक उड़ाई गई थी। उसके बाबत में फिर अर्ज करना चाहता हूं। लोगों की आदतें दरअसल इतनी बिगड़ गई हैं कि हालांकि एण्टी स्मगलिंग (Anti smuggling) के लिये सरकार को खर्चा करना पड़ता है पर लोगों का मोरेल इतना खराब हो गया है कि वे आदतें निकलती नहीं हैं, न राज्य की इन्कम ही बढ़ती है और न जनता को फायदा होता है। ऑफिसर्स भी रिश्वत लेते हैं। राजस्थान में जो शराब निकलती है वह इतनी खराब होती है कि शायद इतनी खराब और कहीं भी नहीं होगी; सरकार की इन्कम का ख्याल रखा जाता है। बेचारे उन गरीब लोगों की तन्दुरुस्ती का कतई खयाल नहीं रखा जाता जिन पर इस खराब शराब के पीने से बुरा असर पड़ता है। क्योंकि मजदूर के लिये शराब के अलावा कोई रिक्रियेशन नहीं है। भारतवर्ष में और कई जगह जो शराब बनती है, सबसे वर्स्ट शराब राजस्थान में बनती है। इस शराब में पानी भी मिलाया जाता है और चोरियें जो होती हैं वे अलग हैं। हालां कि मैं तो इस बात का एक्सपर्ट नहीं परन्तु यह मानी हुई बात है कि राजस्थान में जैसी खराब शराब बनती है वैसी और कहीं नहीं बनती।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान मेडिकल डिपार्टमेण्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे इलाके में नहरू की बहुत शिकायत रहती है। फसल के समय में वहां के लोगों के नहरू निकल जाते हैं जिससे वे लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, बैठे रहते हैं। कुंभलगढ़ और गोगूंदा के इलाकों में रिसर्च कराये जाने की कई बार मांग की गई पर कोई सुनवाई नहीं की गई। अब नये मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। यह इतनी खराब बीमारी है कि आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इसके लिये रिसर्च होना बहुत जरूरी है। पहले इसके लिये डा० चौपड़ा आये और घूमघाम कर गये। उनके पास ट्रेवलिंग के पैसे भी नहीं थे। इधर उधर से उधार लेकर वापस गये। उनके पास चार्ट्स भी तैयार हैं। मेरा खयाल है कि विकास योजना में इस काम को लिया गया होगा। सरकार की तरफ से भी इस के बारे में रिसर्च होगा तो वहां के लोगों को लाभ होगा।

[श्री भेरूसिंह केलवा]

अब में राजस्थान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में सदन के सामने में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट की नीति ही समझ में नहीं आती। या तो ऐसा ऑर्डर होना चाहिये कि २००) रुपये जमा करादो और चाहे जितनी मोटरें चलाओ, या ट्रेफिक का हिसाब देख कर रखा जाय। पर इसमें परमिट भी रखे हैं और डिस्क्रिशन ऑफिसर के हाथ में रखा है। इस तरह के अधिकार रहने से ऑफिसर बेईमानी करते हैं और इच्छा के माफिक परमिट दे दिये जाते हैं। इससे बहुत भ्रष्टाचार फैलता है। इस नीति के बारे में मैं सरकार की ओर से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है। या तो खुला कम्पीटीशन रख दिया जावे जिससे कि पब्लिक को दो-दो, चार-चार आने में मोटरों वाले पहुंचावें या कोई और स्पष्ट नीति हो।

मोटर मालिकों की भी यही हालत है। जिंदा रहने के लिये मोटर चलाते हैं क्योंकि कमाई का और कोई जरिया नहीं है। उनको कहो कि और कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते तो कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और कोई दूसरा धंधा ही नहीं। अनएम्प्यलॉमेंट का मसला उनके सामने है। यह तो स्पष्ट है, जैसा कि फाइनेन्स कमीशन ने भी कहा है कि मोटरों पर जितना हाई टेक्सेशन राजस्थान में है उतना और कहीं नहीं है। इस पर भी पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट वाले इनको तंग करते हैं, वह जुदा है। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट और पुलिस विभाग द्वारा इन लोगों को तंग करना कम हो जाय तो भी इनको काफी राहत मिल सकती है। इस तरह देखा जाय तो यह लोग नाम मात्र को जीते हैं। इसके अलावा सरकार की एक और नीति समझ में नहीं आती। कांकरोली से चारभुजा और देसूरी को जो मोटर जाती है वह मोटर स्टेशन पर आनी चाहिये परन्तु मुसाफिरों को एक माइल दूर छोड़ा जाता है, मोटर को वहां जाने के लिये अलाऊ नहीं किया जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से टांगे वाले नाराज हो जायेंगे। बड़ी अजीब पॉलिसी है कि तांगेवाले नाराज हो जायेंगे। इस तरह सब को खुश करने की पॉलिसी से कैसे काम चलेगा। इससे मुसाफिरों को कितनी तकलीफ होती है। मैं यह नहीं कहता कि कांकरोली जाने वालों को मोटर में बैठने दिया जाय लेकिन दूर जाने वालों को तो मोटर में बैठने दिया जाय। तो इस तरह सरकार की पॉलिसी समझ में नहीं आती।

श्री गोपीलाल यादव--ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक बड़ी सीरियस स्थिति हाउस में पैदा हो गई है। हाउस के बहुत बड़े तबके के लोगों के अधिकार छीन लिये गये हैं। उनको बोलने नहीं दिया जाता, बैठने नहीं दिया जाता। इसलिये आप दूसरे सदस्यों को कहें कि अगर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो तो उसको तोड़ें। पिछले साल बजट पर बहस के समय जिस प्रकार हम लोग अपने विचार रखते थे उससे भी अधिक उग्र रूप से उस ओर से विचार रखे जाते थे, पर इस बार तो किसी को नहीं बोलने दिया गया है और उनको कहा गया है कि इनको भी कोई मत सुनो, इनको सुन लोगे तो बागी हो जाओगे। आप इस हाउस के प्रिविलेज की रक्षा कीजिये। (हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह बजट बहुत अच्छा है और यही वजह है कि विरोधी पक्ष को इस पर ज्यादा

[श्री बद्रीप्रसाद]
नुक्ताचीनी करने का मौका नहीं मिल रहा है । बजट में शिक्षा एवं जनकल्याणकारी अन्य कार्यों पर काफी रकम रखी गई है। बजट में आमदनी के जरिये बढ़ाने के लिये कोई बेजा टैक्स नहीं लगाये हैं। यह मानी हुई बात है कि दुनिया में कोई सरकार बगैर टैक्स लगाये नहीं चल सकती और कोई सरकार दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसका कार्य बगैर टैक्स लगाये चलता हो। यह बात जरूर है कि जो जितना टैक्स देती है उसको उसका रिटर्न सही रूप में मिलना चाहिये।

मुख्य मंत्रीजी का भाषण मैंने गौर से सुना और मुझे सब जगह हर बात में संतोष हुआ, लेकिन एक बात के लिये जो मुझे असंतोष हुआ। वह यह कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह प्रतापगढ़ है; जिसको एक छोटी सी रियासत होने का सोभाग्य प्राप्त था, वहां से मैं आया हूं। राजस्थान की १८-१९ रियासतें मिलीं और एक बड़ा राजस्थान बना। इसके बाद छोटी रियासतों की जो दशा हुई वह किसी से छुपी नहीं। उनके लिये इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। यह बात तो है कि जिन छोटी रियासतों में हैडक्वार्टर्स हैं वहां तो थोड़ी रोनक बनी हुई है हालांकि वहां पर भी रजवाड़ों के जमाने में जो रोनक थी वह उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं है। पर जहां हैडक्वार्टर बनने का सोभाग्य नहीं मिला वहां की रोनक धीरे धीरे लुप्तप्राय हो गई है। ऐसी हालत में आस पास के एरिया को देखते हुए सरकार को देखना चाहिये कि कौनसी जगह हैडक्वार्टर होने के लायक है। वहां हैडक्वार्टर बनाये और अगर यह संभव नहीं हो सके तो कम से कम वहां पर छोटे २ कारखाने खोल कर वहां की हालत को ठीक बनाये रखने के लिये प्रयत्न किये जायें।

साथ ही यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट में काफी रकम शिक्षा, मेडिकल, सिंचाई, सड़कों आदि के लिये रखी गई है। लेकिन जैसा कि अमूमन हमारे राजस्थान में होता है कि यहां जब वर्षा होती है तब बराबर नहीं होती; किसी भाग में ज्यादा होती है तो किसी भाग में कम। ठीक यही हाल कहीं ऐसा न हो इन खोली जानेवाली हमारी स्कूलों, अस्पतालों आदि के बारे में भी हो; यानि ये एक ही तरफ के हिस्से में खोल दी जावें और बाकी सारा भाग खाली रह जावे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डबल मेम्बर कॉन्स्टीट्यूएन्सी से आया हूं। यहां पर जिन जिन लोगों के भाषण हुए हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की बातें रखी हैं। मैंने सोचा कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं इसलिये मैं भी यहां पर अपनी मांगें रखना उचित समझता हूं। नयी स्कूलें खोलना, अस्पताल खोलने, नयी सड़कें बनाना तो ठीक है, बेजा बात नहीं है, लेकिन जहां पर पहले से सड़कें बनी हुई हैं और अब खराब हो गई हैं उन्हें कम पैसा लगाकर ठीक कराना ज्यादा जरूरी है। जिन छोटी रियासतों के राजाओं ने सड़कें आदि बनवाई थीं उनको आप पूरी तरह से आज मेन्टेन नहीं कर पा रहे हैं। (करतल ध्वनि) यदि आप ५० या २५ मील नयी सड़कें बनाते हैं तो १०० मील बनी बनाई सड़क को खराब करते हैं। इसका मतलब यह है कि मेन्टेनेन्स ठीक नहीं कर पाते। मध्यभारत का बोर्डर मेरे इलाके के पास आया हुआ है। वहां भी सड़क है और उसके

[श्री बद्रीप्रसाद]

पास ही राजस्थान की १३ माइल सड़क का एक टुकड़ा आया हुआ है। इस सड़क और उस सड़क की हालत का मिलान करेंगे तो रात-दिन का अंतर पायेंगे। मध्य भारत एक छोटी और राजस्थान एक बड़ी रियासत है। यहां के इंजीनियरों को बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है और अपने आपको दूसरों से ज्यादा काबिल समझते हैं। यहां के बजट में भी काफी रकम रखी जाती है। फिर क्या वजह है कि यहां पर काम अच्छी तरह से नहीं किया जाता? मैंने इस बारे में छान बीन की। मंदसोर के इंजीनियरों से मिला। उनसे बातचीत हुई तो मुझे पता लगा कि मध्यभारत में मेटल्ड रोड बनाने के लिये जितनी रकम दी जाती है उतनी हमारे यहां नहीं दी जाती। यही हालत गवर्नमेन्ट बिल्डिंग्ज की भी है। लाखों रुपयों की इमारतें खड़ी हैं जिनकी आज मरम्मत भी नहीं हो पाती। गो कि हमारी रियासत छोटी थी परन्तु वहां पर शानदार ऑफिसेज, अस्पताल, स्कूलें, रोड्स आदि बनी हुई हैं। मैं आप से क्या अर्ज करूं कि हजारों-लाखों रुपये लगा कर इमारतें बनाई गई थीं किन्तु उनकी मरम्मत के लिये २,४ हजार रुपये राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर सकती और वे इमारतें बरबाद हो रही हैं। स्कूलों और अस्पतालों का आज साढे चार-पांच वर्ष से व्हाइटवाश तक नहीं हुआ है। यह अफसोस की बात है।

दूसरी बात में आपसे यह निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ हालांकि काफी बड़ी जगह नहीं है लेकिन ठीकसर जगह है। वहां पर काफी बच्चे पढ़ते हैं। वहां हाई स्कूल बिल्डिंग की कमी है। अभी पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर साहब का वहां पर दौरा हुआ था, उनसे भी अर्ज किया था। उन्होंने नोट भी फरमाया था। लेकिन उस पर अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दिन दिन हालत खराब होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में वह बिल्डिंग बन जायगी। उसमें ज्यादा खर्च का सवाल नहीं है। यही हाल सभी जगहों का है। आप यदि थोड़ी-थोड़ी रकम उन पर लगाते रहें तो लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है। यदि आप के पास पैसा नहीं है तो पहले नया काम रोक दीजिये और जो पुराने रोड्स बिल्डिंग्ज हैं उनको मेन्टेन (maintain) करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अस्पतालों की कमी है, औषधियों की कमी है। सब जगह यदि अस्पताल नहीं खोल सकते तो कम से कम यह तो होना चाहिये कि जहां जहां पर तहसील हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर तो अस्पताल खोले जायें। प्रतापगढ़ में अरनी तहसील है। वहां न तो कोई अस्पताल है और न कोई और तरह का इन्तजाम है। मैं आशा करता हूं कि आगामी साल में वहां जरूर अस्पताल खुल जायंगे। साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ से अभी तक हमारी पुरानी रियासत ने सड़क बनाने का विचार किया था उसकी पैमायश हो चुकी थी और सड़क बनाने का कुछ सामान भी वहां पटका (रखवा) दिया गया था लेकिन फिर मर्जर हो गया और वह काम अधूरा ही रह गया और उसके बाद बजट में इस के लिये कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। आप कोई काम करना शुरू करते हैं और फिर उसे बन्द कर देते हैं और फिर कभी शुरू कर देते हैं; इससे कोई फायदा नहीं होता।

[श्री बद्रीप्रसाद]

मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि महरबानी करके, जब कि इस साल शिक्षा के लिये आपको काफी रकम मिलने वाली है, हमारे यहां भी एक इन्टरमीडियेट कॉलेज खोलें; हमारे यहां छात्रों की संख्या काफी है।

सिंचाई के लिए बजट में काफी रकम दी गई है। मैं आपको यह बताने को तैयार हूं कि यहां पर पानी काफी मिल सकता है और सिंचाई के लिये उपयुक्त जमीन है और कम पैसा खर्च करने से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस साल आप जरूर इस ओर ध्यान देंगे।

साथ ही प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी और चित्तौड़ पहुंचने के लिये सड़क बनानी चाहिये। गवर्नमेन्ट की यह पॉलिसी है कि तहसील हैडक्वार्टर्स को सड़कों से मिलाया जाय। मैं आशा करता हूं कि छोटी सादड़ी और चित्तौड़ को प्रतापगढ़ से पक्की सड़क द्वारा अवश्य मिलाया जायगा, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत! साथही मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के लिये विशेष रूप से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चित्तौड़ एक ऐतिहासिक जगह है। पहले तो इसे राजस्थान की राजधानी बनाने का प्रश्न चल रहा था पर अब जब कि एक डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर चित्तौड़ को बनाया है तो इसकी उन्नति अवश्य होनी चाहिये। इसके लिये बजट में ज्यादा से ज्यादा गुंजायश करनी चाहिये और इसे अच्छा बनाना चाहिये।

श्री सन्तोषसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, आज हम दूसरी बार इस हाउस में बजट पर बहस करने आये हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसमें जो विशेष बात है वह यह है कि उन्होंने बजट में जितना रुपया जमा में बताया है उतना ही खर्च भी बताया है और पोते बाकी में क्रोस बताया है। माननीय उपाध्यक्षजी इस क्रोस का बहुत बड़ा मतलब है और यह क्रोस जान बूझ कर लगाया गया है क्योंकि माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि एसेम्बली में वक्तन फवक्तन हमारे माननीय सदस्य हमेशा प्रश्न पूछेंगे कि फलां स्कूल की छत टूट गई है, फलां बांध टूट गया है: इस तरह के सवाल होंगे तो आसानी से जवाब दिया जा सकेगा कि हमारे पास धनकी कमी है; बजट में क्रोस लगा हुआ है, बचत कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जान बूझ कर ऐसा बजट इस सदन के सामने पेश किया है।

इसके बाद में आपको बताऊंगा कि हमारे यहां वेजिटेबल घी के बारे में जब सदन में सवाल पूछे जाते हैं तो माननीय मंत्री महोदय जबाब देते हैं कि वेजिटेबल घी का राजस्थान में आना कतई बन्द है। इसमें भी एक चाल मालूम देती है। वह चाल यह है कि या तो ये लोग या कोई दूसरे वेजिटेबल घी के कारखाने से मिले हुए मालूम देते हैं। उनको यह बता दिया जाता है कि आप अपने वेजिटेबल घी के टीन पर वेजिटेबल घी का नाम न लिखकर वनस्पति या कोकोजम आदि लिख दिया करें। दूसरे नाम से राजस्थान में आने की मनाई नहीं है। अगर आप घी का नाम लिखेंगे तो राजस्थान में आने नहीं दिया जायगा। वेजिटेबल घी के राजस्थान में आने से कितना नुकसान हो रहा है इस बात का माननीय मंत्रीगण

[श्री संतोषसिंह]

विचार नहीं रख रहे हैं। राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य पर इस घी का कितना बुरा असर पड़ता है, इसका भी मंत्री महोदय को ध्यान नहीं। उनका ध्यान तो सैन्टर के मिनिस्टरों के आदेश-पालन में रहता है। इससे उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमा लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। माननीय मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत प्रार्थना करूंगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो वेजिटेबिल घी के नाम से या दूसरे नाम से धोखा देने के लिहाज से इस राजस्थान में आने लगे हैं उनको रोका जाय; चाहे उस पर वेजिटेबिल घी लिखा हुआ हो या नहीं। इस बात पर अवश्य विचार करें।

माननीय मंत्री महोदय ने गत सेशन में एप्रोप्रियेशन बिल के जवाब में बताया था कि हमारे यहां कोढ़ियों के निवास-स्थान के लिए बराबर प्रबन्ध किया गया है। हमारे जोधपुर में कोढ़ियों के लिये एक कोलोनी बनी हुई है। उसके अन्दर सिर्फ एक कम्पाउन्डर रखा हुआ है। वहां जाकर मैंने खुद ने देखा है। कोढ़िये मांगकर खाते हैं। सरकार थोड़ा, नाम मात्र का, खर्चा कर रही है। जैसा कि पहले मैंने सदन में बताया था कि हमारी सरकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मोटरों का परमिट आदि देती थी जिससे वे अपनी आजीविका कमा लेते थे। पहले राजा लोगों के समय में भी यदि राजा लोग किसी पर खुश हो जाते थे तो उनको मोटरें या जागीरें इनायत किया करते थे। जब हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देखा कि मोटरों के परमिट आदि से अब काम नहीं चलने वाला है, उसके जरिये जो आमदनी होती थी वह बन्द हो जाने से उन्होंने कमाई का नया क्षेत्र ढूंढ निकालने की कोशिश की और उन्होंने कोढ़ियों के नाम से चन्दा इकट्ठा करना शुरू किया। पिछले महीने में फरवरी की चार या पांच तारीख के हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में एक खबर छपी थी कोढ़ियों के लिये चन्दा इकट्ठा करने के सिलसिले में एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता जोधपुर की राजमाता के पास गये और उनसे कहा कि मैं कोढ़ियों के लिए चन्दा लेने आया हूं। राजमाताजी ने जवाब दिया कि क्या सरकार कोढ़ियों के लिए कुछ नहीं करती, यह तो बड़ी शर्म की बात है। कोढ़ियों की इमदाद तो सरकार को करनी चाहिये। अब यह बताने की जरूरत नहीं कि इस वर्ष जो हमारी सरकार जो कांग्रेसी सरकार है वह अपने आपको महात्मा गांधी के आदेशानुसार चलने का दावा करती है। महात्मा गांधी, आप लोग जानते होंगे सेवाग्राम में रोज प्रातः एक कोढ़ी की मल्हम पट्टी अपने हाथ से किया करते थे और फिर बाद में दूसरे काम के हाथ लगाते थे। वे कोढ़ियों की मल्हम पट्टी करना अपने हाथ से ज्यादा अच्छा समझते थे। उन्हीं को गुरू मानने वाले उनके ज्यादा नजदीक अपने आपको बताने वाले कोढ़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके खाने, पीने, पहिनने आदि को छीनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है।

इसके साथ जैसा कि मैंने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि कुत्तों को बाड़े में बन्द कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष, इससे पहले कुत्ते बाड़ों में बन्द रखे जाते थे। किन्तु आज-कल यह नियम हटा दिया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इन कुत्तों को छोड़ कर जो कि हरेक

[श्री संतोषसिंह]

चलने फिरने वाले को काट खाते हैं, जनता के स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचाई है। इस नुकसान को समझते हुए इस तरफ भी सरकार को ध्यान अवश्य देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, यह जो कुत्तों का वाड़ा है उसके लिए मेरा निवेदन है कि जन स्वास्थ्य के हित के लिये इन कुत्तों को इकट्ठा करके एक जगह रखना बहुत आवश्यक है। जयपुर में होस्टल के पीछे जहां मैं रहता हूं इतने कुत्ते हैं कि जिसकी हद नहीं।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह बताना चाहता हूं कि, हमारे यहां राजस्थान में मादीन जानवरों की निकासी शुरू करदी है। ये स्टेटें जब मर्ज नहीं हुई थीं तब मादीन जानवरों की निकासी नहीं होती थी। जिस वक्त इन राज्यों का एकीकरण हुआ मादीन जानवरों का बाहर निकलना शुरू हो गया। यहां तक कि एक दफा मादीन जानवरों के काटने तक का हुक्म हो गया; यह तो बड़े शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि सरकार को इन मादीन जानवरों की निकासी पर क्या आमदनी होती होगी। यदि कुछ कस्टम की तौर पर कुछ आमदनी होगी तो वह नहीं के बराबर है। मारवाड़ में हमारे किसान वर्ग और गांव के निवासियों की आजीविका, विशेषकर खाने-कमाने का जरिया पशु पालन व खेती है। अध्यक्ष महोदय, यदि मादीन जानवरों की निकासी जारी रही तो हमारे देश में पशुओं का उत्पादन कम हो जायगा और इसके साथ उनके जरिये खाद के प्राप्त न होने से हमारी खेती की पैदावार भी बहुत कम हो जायगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह जो मादीन जानवरों की निकासी हो रही है अगर बन्द न की गई तो राजस्थान के लिए अच्छी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर हमारी सरकार अपने बजट में बड़े बड़े मकानात, अस्पतालों के भवन आदि बनवाने के लिये पैसा रख रही है किन्तु हमारी सरकार गरीब भिखारियों की ओर तवज्जोह नहीं देती। हजारों भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। सांगानेर दरवाजे के बाहर आप देख सकते हैं कि भांति-भांति के स्वांग किये भिखारी आपको देखने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अपने आपको लोकप्रिय के नाम से पुकारती है। इस लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार को सब से पहले इन गरीब भिखारियों की ओर ध्यान देना चाहिये। इनके लिये सारा काम करना चाहिये।

इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजप्रमुख के भाषण में हमने सुना था कि ऊन का कारखाना जयपुर में खोला जायगा। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह ऊन हमारे प्रान्त में पोकरन फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर में पैदा हुआ करती है। कच्चा माल तो वहां पैदा होगा और उसके लिये मिल यहां बनाई जाती है। मेरा निवेदन है कि जयपुर में ट्रान्सपोर्ट के लिये भी ज्यादा खर्चा पड़ेगा, यहां मजदूरी भी मँहगी पड़ेगी इसलिये दिक्कत रहेगी। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि मिल पोकरन, ओसियां या बीकानेर में से किसी जगह बनादी जाय तो वहां जो लोग बेकार बैठे हैं उनको भी काम मिल जायगा और उनकी रोटी

[श्री संत बक्षसिंह]

का प्रश्न भी हल हो जायगा। फिर कभी ऐसी फैक्ट्रियां खोलने का सरकार का इरादा हो तो सरकार को चाहिये कि वह उस डिवीजन के लोगों से सलाह मशविरा करे कि किस प्रकार कारखाना बनाया जाय और कहां बनाया जाय जिससे जनता को लाभ पहुंच सके।

अब म कुछ खानियों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार खानियों के बारे में बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठी है। खानियों की तरफ कतई तवज्जोह नहीं दे रही है। ऐसी बहुत सी खानियां हैं जो राज्य में किसी प्रकार का रेन्ट न देते हुए कई वर्षों से मुफ्त चलाई जा रही हैं।

हमारे चूने के पत्थरों की खानों के ठेके के बारे में मैंने कहा था उसका दावा कोर्ट में चल रहा है। फिर भी सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं दे रही है। मेट के लिए, अध्यक्ष महोदय, २० साल से एक ही ठेकेदार काम कर रहा है। मोनोपोली देना सरकार ने बंद कर दिया है और कहा गया है कि अब कोई मोनोपोली नहीं दी जायगी, किन्तु मोनोपोली के बजाय लीज कर दी गई है। जो दूसरी खानियां थीं वे भी लीज में आगई हैं और इस तरह से बगैर देखे भाले पट्टे हो रहे हैं। सरकार घाटे में होते हुए भी घाटा डालने में हिचकिचाहट नहीं कर रही है क्योंकि पहले रॉयल्टी का २५ रुपया था और अब पांच रुपया ही कर दिया गया है

सरकार ने बांध बंधाने के लिए काफी रकम बजट में रखी है। इसके बारे में मैं कहूंगा कि हमारे जोधपुर में बांकली बांध, झोगड़ावास और हेमावास ये तीन बड़े बांध हैं। चौथा सटपड़ा बांध है। अगर इन चारों बांधों को बंधा दिया जाय तो इनसे काफी सिंचाई हो सकती है। ये काफी बड़ी और अच्छी योजनाएं हैं। जोधपुर में जो सूरपुरा बांध है जिसकी नहरें ठीक नहीं हैं और वह पूरा भरता नहीं है। अगर इस बांध की नहरें ठीक करादी जायें तो इससे हजारों मन नाज पक सकता है। इसके अलावा खोखरिया बांध है। हेमावास, झोगड़ावास और खोखरिया बांध इस प्रकार के बांध हैं कि इनके नीचे काफी पड़तल जमीन है। अगर इस जमीन में सिंचाई हो तो काफी फायदा राजस्थान की जनता का हो सकता है और सरकार को भी काफी आमद हो सकती है। इसके अतिरिक्त दादिया बांध है, जो बाली देसूरी में है। अगर इसको बांध दिया जाय तो इसके नीचे जितने कुएं हैं उनमें पानी पहुंच जायगा और इससे सिंचाई काफी हो सकेगी। फलावट के पास एक नदी आती है। उस नदी को बांध दिया जाय यानी उस नदी के पानी को रोक दिया जाय तो उससे भी उसके आसपास की जमीन की सिंचाई हो सकती है। ये जितने बांध मैंने बतलाए हैं उन बांधों के बंधाने के विषय में सरकार के पास कोई योजना नहीं है और मैंने इसी लिए यह बात यहां रखी है कि अगर इनको बांधदिया जाय तो इससे काफी सिंचाई हो सकती है और लोगों को राहत मिल सकती है।

बिलाड़ा परगना में एक जसवन्त सागर नाम का बड़ा बांध है। उसके पानी के विषय में आए साल लोगों में झगड़ा होता है। इस साल भी झगड़ा हुआ था सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। उन लोगों के पास तलवारें, बन्दूकें और लाठियां थीं। कलेक्टर ने इस संबन्ध में एवार्ड दे दिया। माननीय मंत्री जी ने भी आदमी भेजा और किसी भी तरह से इस झगड़े को निपटवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदयजी से कहूंगा कि इस बांधकी नहरों में मिट्टी आ गई है

Page No.73

श्री संतोषसिंह]

और इस वजह से बोरी तक पानी नहीं पहुंचता है और इस कारण ही यह झगड़ा उठा हुआ है। अतः इन नहरों को साफ कराने का बन्दोबस्त कर दिया जाय तो यह झगड़ा भी रफा हो जायगा और सिंचाई भी हो सकेगी। मैंने इस बांध के संबन्ध में एक योजना भी दी थी और लिखा था कि यह सालाना झगड़ा मिट सकता है। किन्तु मेरी इस योजना की तरफ सरकार ने कोई तवज्जुह नहीं दी।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अगर आप महात्मा गांधी हॉस्पिटल के संबन्ध में पूरा टाइम दें तो सारा किस्सा कह सकता हूं क्योंकि इसमें काफी समय की जरूरत है। वह पांच मिनिट में तो पूरा नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष, जो मैंने १७ तारीख को एडजॉर्नमेन्ट मोशन रखा था उसके मुतअल्लिक माननीय अध्यक्ष ने आगे बोलने के लिए आश्वासन दिया था उसके मुतअल्लिक भी मैं दो चार बातें बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—बजट की डिबेट में जनरल पॉलिसी पर ही डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक पोइन्ट हो तो आप उसको डिमान्ड्स पर लाना चाहें तो लाइयेगा। किसी खास पद के बारे में आप वाद-विवाद करियेगा। अतः जनरल पोलिसी पर ही क्रिटिसिज्म होना चाहिए।

श्री संतोषसिंह—तो माननीय अध्यक्ष, हॉस्पिटल के संवन्ध में मैं कट मोशन पर बोलूंगा। मैंने पहले खानियों के बारे में कहा था और इस संबन्ध में मैं कहूंगा कि जियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर देखा जाय तो जियोलोजिस्ट्स हमारे राजस्थान में हैं ही नहीं। जो खानियां पहले राजस्थान में चालू थीं उनका ठेका वक्त पर नहीं देने से एवं समय पर रुपया वसूल नहीं करने से राजस्थान को काफी नुकसान हुआ है। जब पुरानी खानें ही नहीं सम्हलती हैं तो नई खानें तो क्या निकलेंगी ? इसलिए माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है और मारवाड के लिए यह कहूंगा कि यहां सोना निकल सकता है, चांदी की खानें हैं और यहां पैट्रोल और बंगाल कोल भी निकल सकता है। इस तरह से हमारे उदयपुर में माइका की बड़ी खाने हैं। कई खानियां जिनका एरिया २५-२५, ३०-३० और ४०-४० स्क्वायर माइल्स की रखी गई हैं उनको लीज पर दे दिया गया है। तीन साल बाद चार स्क्वायर माइल्स ही देने चाहिए थे किन्तु सरकार ने इसके कोई टुकडे नहीं किए हैं। अगर दूसरा कोई लीज को लेना चाहता है तो वह भी नहीं दी जाती। दरख्वास्तें देते हैं तो कहा जाता है कि अभी हमने पोलिसी तय नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—You are turning over same pages.

श्री संतोषसिंह—मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Page No.74

श्री अध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, मैंने भी तो अपना नाम दिया है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका भी नाम आ जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I agree if my friend wants to speak.

श्री अध्यक्ष—If once a member is asked to speak and he does not do so he loses the chance.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा थी कि इस बजट के सिलसिले में मैं अगले दिन कुछ बातें कहता। लेकिन आज ही कैसे मेरी बारी आ गई है और इसलिए मैं कम से कम जो बातें मुझे कहनी हैं उनको मैं शुरू तो आज ही कर देता हूं।

अब तक जो इस बजट के सिलसिले में बातचीत हुई उसका ताल्लुक आंकड़ों से था कि इतनी आमदनी है, इतना खर्चा है और किस किस में क्या है और कितना है। मेरा ख्याल है कि इस बजट पर विचार करते समय माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर और मुख्य मंत्रीजी को दाद देने के पहले जो सदन के सामने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर गौर करना हमारा कर्तव्य है।

यह बजट किस प्रकार का है, कैसा इसका ढांचा है, इसका सही नक्शा किस प्रकार का है; यह इस रिपोर्ट के अन्दर हमारे सामने पेश है। इसमें न सिर्फ यह बताया गया है कि ठीक तरीके से हिसाब-किताब पेश नहीं किया गया है बल्कि जैसा कि इस रिपोर्ट के चेयरमेन साहब ने बताया है कि सरकार हिचकिचाहट दिखा रही है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने हिसाब-किताब पेश करने की। मैं नहीं जानता कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इस मामले को वहीं तक छोड़ दिया क्यों? इस बारे में क्यों पर्स्यू किया और हमको यह मौका दिया कि हाउस कमेटी में पेश हुए कागजातों को मानने के बाद इन कागजातों को लेने से इन्कार करे और यह प्रस्तुत हो जाय। तो इस बजट का सब से पहला नमूना यह है कि सरकार किसी भी छानबीन से घबरा रही है। जब मैं इस बजट में प्रस्तुत आंकड़ों का जिक्र करूंगा तो यह साबित हो जायगा कि सरकार किस प्रकार की छानबीन से घबरा रही है। घबरा वह इसलिये रही है कि उसने हमारे सामने बजट पेश नहीं किया है; उन्होंने जगलरी मेनिप्युलेशन तक की मिसाल हमारे सामने पेश की है।

मैंने अखबारों में या रिपोर्टों में कहीं इस तरह का बजट नहीं पढ़ा है और न देखा है। कम से कम आज तक ऐसी मिसाल मेरे सामने नहीं आई जिसमें रुपया, आना, पाई तक आमदनी और खर्चा बिल्कुल बराबर टोटल निकलता हो। इस बजट में १९४४ की आमदनी और खर्च भी १९४४ बताया गया है। आखिर यह किस प्रकार हो गया। ऐसी कौनसी विशेषता है इस राजस्थान में और

Page No.75

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजस्थान के बजट में जिसमें रुपया, आना, पाई तक के आंकड़े आमदनी और खर्चे के बराबर आते हों। मैं यह कहूंगा कि इसमें एक चीज है जो हमें इस हकीकत की और इशारा करती है कि इस बजट के तैयार करते समय फाइनेन्स के जो सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों को आधार मानकर बजट तैयार करना दूर रहा यह बजट तो पहले ही तैयार कर लिया गया कि हमें बेलेन्स्ड-बजट पेश करना है। इसके बाद आंकड़े कम ज्यादा किये गये जिसका नतीजा यह हुआ कि आंकड़े जरूरत से ज्यादा कम कर दिये गये, १९४४ की जगह १९५४ कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिये यह हमारे और किसी दूसरे के लिये विश्वास देने के काबिल चीज नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज और सम्बन्ध रखती है। बजट पेश हुआ, बजट के आंकड़े छपे, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का भाषण छपा। उसके बाद साइक्लोस्टाइल किया हुआ एक पर्चा हम लोगों के पास पहुंचा जिसमें पैरेग्राफ नं० ८ में यह चीज और जोड़ लेनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ था। वह चीज क्या थी। वह यह था कि जिस समय राजस्थान की सिक्योरिटीज का हवाला दिया गया है उसमें यह बताया गया हैं कि १४ (चवदह) करोड़ रुपये से ज्यादा की सिक्यूरिटीज हमारे पास हैं, और इस बात को वहीं पर छोड़ दिया गया। फिर अचानक करेक्शन स्लिप आई और उसमें कहा गया कि ९ करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट हमने बेंक से इम्पीरियल बेंक से ले लिया है, ओवर ड्राफ्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल, ऐसा अन्दाज है, उसमें से ५० लाख रुपया कम हो जायगा और ५३-५४ में ५० लाख रुपया और जोड़ देंगे जिससे ओवर ड्राफ्ट में कमी हो जायगी। मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले बजट अधिवेशन में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में प्रान्त की आर्थिक स्थिति का जिक्र हुआ था। उस सिलसिले में मैंने बयान दिया था कि इस प्रान्त को सिक्यूरिटीज को बरबाद कर दिया गया है। उसके बाद ही लीडर ऑफ दी हाउस ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि यह मिथ्या बात है, यह बेबुनियाद बात है; सिक्यूरिटीज हमारी जमा हैं; पांच या छः करोड़ रुपया खर्च हुआ, बाकी वैसा का वैसा जमा है। उस समय इस बात को छिपाया गया था कि इम्पीरियल बेंक से हमने एक बहुत बड़ा ओवर ड्राफ्ट कर लिया है। उस समय बजट में इस बात को छिपाया गया था। उस समय के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के भाषण को पढ़ेंगे तो आपको साफ पता लग जायगा कि हमारे पास सिक्यूरीटियां मौजूद हैं, कहीं गई नहीं हैं। तो अचानक यह कैसे हो गया? ओवर ड्राफ्ट ले लिया, यह क्या बजट पेश करने का तरीका है? "सप्रेसियो वेराइ (Suppressio veri) हकीकत को छिपा देना," गलत तरीके से अन्दाजा लगाया गया है, जो सामने आजाय। अगर इस विषय में और ज्यादा छानबीन की जाय और इन आंकड़ों पर ठीक तरीके से गौर करें तो पता लगेगा कि जो हमारी लाइबेलिटीज का प्रश्न पेश किया गया है, यह जो सरकार के ऊपर कर्ज है, जो इसके ऊपर लाइबेटीज का हवाला दिया गया है, मेमोरेण्डम में नहीं बजट में जो पूरे पूरे आंकड़े छपे हैं उस पर करीब चार लाख का ब्याज देना पड़ता है। भारत सरकार से कर्ज लिया हुआ है उस पर। साढे चार लाख रुपया प्रोवीडेण्ट फण्ड और ट्रस्ट फण्ड इत्यादि के हैं। इसके लिये नीचे एकान्त में इटालिक्स में हैड छपा है जिसमें लिखा है कि जो ओवर ड्राफ्ट ले लिया गया है उसका ब्याज देना पड़ता है। १८ लाख रुपये का यह खर्च है। यह खर्च का मद है, ऐसी बात नहीं है। केपिटल इन्वेस्टमेण्ट हो, यह भी बात नहीं। यह जो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

३८ लाख रुपये का आइटम है यह इन्टरेस्ट चार्जेज के नाम से है । जो ओवरड्राफ्ट लिया गया है उसका ब्याज देना पड़ता है । राजस्थान सरकार ने कितना ओवरड्राफ्ट ले लिया है उससे अन्दाज लग सकता है । करेक्शन स्लिप नहीं आती या छपता नहीं, तो भी यह छिपाये छिपाने की बात नहीं थी । बजट छप चुका, मेमोरेण्डम शाया हो चुका, फिर साइक्लोस्टाइल होकर के एक चीज आती है कि ३८ लाख का ब्याज देना पड़ता है आखिर यह कैसे छिपाया जाय ? जिस गवर्नमेण्ट को अपनी सिक्यूरिटीज पर गर्व है हमारी मौजूदा गवर्नमेण्ट को बयान करने से पहले यह सोचना चाहिये ।

अगर उसे इम्पीरियल बेंक और दूसरी बेंकों के ओवरड्राफ्ट के बारें में ३८ लाख रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं तो वह प्रान्त की अच्छी आर्थिक हालत दिखाने वाला बजट नहीं है । अपनी तसल्ली के लिए, भले ही समझने के लिए कह दें कि हमारा बजट बेलेन्स्ड बजट है ।

दूसरी चीज जो मैंने इस बजट में विशेषतया जो पाई है वह यह है कि कई २ जगह जहां खर्चे के तखमीने देने चाहिए थे, डिटेल्स देने चाहिए थे, वह डिटेल्स नहीं दिये गये हैं और मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाऊंगा कि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिनिस्टर्स के बारे में, कौन्सिलर्स, डिप्टी मिनिस्टर और प्राइवेट सेक्रेटरीज़ के बारे में जो मद है, वह पिछले बजट में १,६६,०२० का खर्चा हुआ । रिवाइज्ड एस्टमीमेट में वह इस साल २,११,००० रु० पर पहुंच गया है । खासियत उसकी यह है कि पिछले साल तो हरेक आइटम के अलग २ आंकड़े दिये गये थे, मंत्रियों की तनख्वाह के लिए इतने, डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह के लिए ६,८३० रु० और प्रत्येक मद के अन्दर अलग अलग आंकड़े दिये गये थे । लेकिन इस बार खासियत यह है कि पूरा का पूरा एक ब्रेकेट लगा दिया गया है और उस ब्रेकेट के आगे लिख दिया गया है कि मंत्री भी आ गये, डिप्टी मिनिस्टर भी आ गये, कौन्सिलर भी आ गये और सब मिलाकर २,११,००० रु० का खर्चा आ गया । आखिर ऐसा क्यों किया गया ? क्या फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब एक ही व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपने काम काज की इतनी सहूलियत देखी कि जब चाहा शायद वे केबीनेट में रद्दोबदल कर सकें, शायद मंत्रियों की तादाद बढानी पड़े या शायद घटानी पड़े; तफसील नहीं देने का हकीकत में महज यही कारण हो । अलग अलग खर्चा वहां रख दिया गया तो आगे जाकर फिर तब्दीली करने में दिक्कत नहीं हो । इसलिए इस बार बजट में जो आंकड़े रखे गये हैं वे इस तरह से रखे गये हैं; नहीं तो फिर सबको एक साथ रखने का आशय क्या है ? यह एक चीज है । काफी मदों में ऐसा हुआ है, यह दूसरी खासियत इस बजट की है ।

इसके बाद इस बजट के सिलसिले में अर्ज करता हूं कि बजट हकीकत बतलाने वाला बजट नहीं है, बल्कि हकीकत को छुपाने वाला यह बजट दिखता है । हमारा बजट बेलेन्स्ड बजट बताया गया है लेकिन इसमें असलियत को छुपाया गया है । राजस्थान की आर्थिक स्थिति गम्भीर है । बेलेन्स्ड होना तो दूर करोड़ों रुपयों का डेफिसिट हकीकत में बजट में है । उसको छुपाने के इरादे से यह सब चीजें की गई हैं ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब मैं थोडा सा इशारा करना चाहूंगा उन मदों की तरह जो कि बजट में प्रोवाइड की गई हैं। कोई भी बजट की मुख्य बात यह होती है कि उसमें प्रशासनिक खर्चा कितना है, लॉ एण्ड ऑर्डर के दमनकारी साधनों पर खर्चा कितना और कल्याणकारी राज्य की जो दुहाई दी जाती है उस कल्याणकारी राज्य के लिए हकीकत में खर्चा कितना ? मेरे मित्र गोपीलालजी बोलते २ कह गये कि काफी ढूंढा और पाया कि उन्होंने शायद ६ या ७ करोड का आंकडा ही उसके अन्दर दिया है। स्पीच में १२ का आंकडा दिया गया था। उन्होंने कहा कि बजट में हकीकत में ६ या ७ करोड ही हैं। मेरा कहना है कि वह ६ या ७ करोड भी असलियत में जो हैं वह उससे कहीं कम है। सबसे बडा खर्चा यहां इस प्रान्त में जो हो रहा है वह पुलिस पर हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ओर फाइनेन्स मंत्रीजी ने कहा कि हमें मजबूरी से यह खर्चा करना पड़ रहा है। लॉ एन्ड ऑर्डर तो हमें कायम रखना ही है, जनता की सुरक्षा तो हमें करनी ही है इसलिए कोई चारा नहीं, सिवाय इसके कि हमको बड़ी भारी तादाद में पुलिस पर खर्चा करना पड़ता है। लेकिन खर्चा हो ही नहीं रहा है ऐसी बात नहीं है, निरन्तर बढ़ रहा है, और इस कल्याणकारी राज्य के बजट में जो अलग अलग मदें हैं उन मदों से साफ हो जाता है कि खर्चा अगर किसी भी मद में ज्यादा हो रहा है तो वह पुलिस पर हो रहा है।

अब दूसरी चीजों की तरफ आप गौर करें कि खर्चा जो और प्रशासनिक कार्यों पर हो रहा है उनकी क्या हालत है ? सेक्रेटेरियेट से लगा कर और बाकी नीचे के विभागों पर जो खर्चा हो रहा है उनका जिक्र करना मैं शायद इतना आवश्यक नहीं समझता। यदि टॉप से ही शुरू किया जाय तो राजप्रमुख के भाषण के सिलसिले में बहस होते समय मैंने बताया था कि हमारे मंत्रियों का एवरेज खर्चा ५ या ५ १/२ हजार आता है। इस साल के बजट में भी वह ३॥ हजार के ऊपर रखा गया। एवरेज खर्चा और कम हुआ है तो भी मोटरों के खर्चे पर जहां ३ हजार का आइटम मुझे नजर आया तो मैं जरा चौकन्ना हुआ। यह बजट बनाने म जादूगरी का काम करना मुमकिन है, लेकिन यह ३ हजार रुपये में मोटरों का खर्चा कैसे चला लिया जायगा, इसमें कौनसी करामात और कौनसी जादूगरी हुई है यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरा यह कहना है कि यह दिखाने की कमी है। मैं चेलेन्ज देकर कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आगे चल कर सप्लीमेंन्ट्री मांग रखनी होगी और वह इसलिए होगी कि आज आलोचना नहीं हो, आज चैक नहीं हो। तनख्वाह बढाने की गुंजाइश है। मैंने तो सुना है कि तनख्वाह बढाने के बारे में विचार भी हो गया और शायद करीब करीब फैसला ही हो गया है। आज उसके अन्दर, उस मद के अन्दर खर्चा कर रहे हैं २,११,००० रु० का तो मोटरों के सवाल को फिलहाल मौकूफ कर दें। इस प्रकार से प्रशासनिक मामलों में खर्चा उधर बढा। अब आप जरा सेक्रेटेरियेट के खर्चे का जरा मुलाहिजा करें। उसमें ३२ व्यक्ति, चीफ सेक्रेटरी, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरी इत्यादि मिलाकर हैं क्योंकि बजट में तादाद भी दी गई है। इन ३२ व्यक्तियों के लिए करीब ६-७ लाख रुपये के खर्चे का प्रोवीजन है, और बाकी के जो मुलाजिम सुपरिन्टेन्डेंट से लगाकर लोअर डिवीजन क्लार्क, चपरासी, पियान, फर्राश, जिनकी तादाद सैकड़ों तक की

[हरिकृष्ण व्यास]

है, उनके ऊपर ७८ लाख का खर्चा है। मैंने हिसाब लगा कर एवरेज लगाने की कोशिश की तो यह नजर आया कि इस जादूगरी में चीफ सेक्रेटरी से लगाकर असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज तक का एवरेज १० हजार रुपये आता है तो सुपरिन्टेन्डेंट आदि सब का मिलाकर अगर एवरेज निकाला जाय तो वह १००) रुपये के नजदीक पहुंचेगा। अगर चपरासी और दूसरे लोगों का एवरेज निकाला जाय तो वह ४०) रु० के पास पहुंचेगा। खाली सेक्रेटेरियेट के ऊपर यह खर्चा है, लेकिन उसका प्रॉपोर्शन आप देखिये कि कुल ३२ व्यक्तियों के ऊपर करीब २ आधा खर्चा किया जाता है और बाकी के ४०० के नजदीक आदमियों के ऊपर आधा खर्च किया जाता है। इसमें कितना मार्जिन है। उसके बावजूद हकीकत यह है कि प्रशासनिक खर्च पर हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसा बयान माननीय फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब ने दिया है। यह जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं सेक्रेटेरियेट के यह कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर विभाग के अन्दर इस तरह की चीज हम पायेंगे।

अब मैं आपको ऐसे दूसरे विभागों की मिसाल देना चाहता हूं जो कि मेरे माननीय मित्र गोपीलालजी ने कल्याणकारी विभाग बतलाये हैं। उनमें एक विभाग वेटरिनरी विभाग भी है। उसके सम्बन्ध में आप बजट के आंकड़े पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उस विभाग के २ अंग हैं। एक अंग का ताल्लुक एक डिप्टी डाइरेक्टर से और दूसरे अंग का ताल्लुक दूसरे डिप्टी डाइरेक्टर से और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट का जो काम है वह एक डिप्टी डाइरेक्टर के मातहत रखा गया है। उसके अन्दर चार अफसर हैं, गौशाला डेवलपमेंट आफिसर, दूसरे इस प्रकार के अफसर और एक्सपर्ट हैं, एक डिप्टी डाइरेक्टर, एक असिस्टेंट डाइरेक्टर और फिर ४ अफसर। मैंने फिर इसके और नीचे देखने की कोशिश की कि इसके मातहत स्टाफ कितना होगा ? क्योंकि हरेक ऑफिसर के नीचे देखभाल करने के लिए स्टाफ होगा ही, तो मैंने देखा कि स्टाफ करीब करीब वहां से नदारद है। यह एक ऐसा विभाग है जिसके अन्दर अफसर ही अफसर हैं। यह कैसा कल्याणकारी राज्य है जिसमें देखभाल करने वाले अफसरों की काफी बड़ी तादाद है, बड़ी २ तनख्वाह वाले डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, कई २ एक्सपर्ट हैं लेकिन काम काज करने वाला उनके मातहत स्टाफ ही नहीं है। काम की बात जाने दीजिये कि काम क्या करते हैं।

तीसरा यह है कि जो दिखावा किया जाता है कि हम खर्चा कर रहे हैं आम लोगों के हित के लिए वह दिखावा भी इस तरह का है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ज्यादा है, उसमें प्रशासनिक खर्चा ज्यादा है। उसमें भी नीचे के लोगों की जेब में पहुंच जाय। इस प्रकार का खर्चा ज्यादा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, इसी तरह की चीजें जन-स्वास्थ्य विभाग में और बिजली विभाग में हो रही हैं, जिनके विषय में मिसाल के तौर पर जिक्र करना चाहूंगा।

समय तो हो गया है, अगर आप आज्ञा दें तो नेक्स्ट डे कन्टीन्यु करूंगा।

श्री अध्यक्ष--You finish it to day and continue for 15 minutes more.

श्री एच. के. व्यास--I will take 15 minutes on the next day.

श्री अध्यक्ष--Onoe you have begun, you may finish it.

श्री एच. के. व्यास--The time is over.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य तथा अर्थ मंत्री)--He is not prepared perhaps.

श्री अध्यक्ष--15 minutes will be given to you on the next day.

Before we depart I have to inform that I have received certain representations on behalf of members regarding the revised calendar of meetings. I have considered this matter and have to announce that the revised calendar of meetings issued on the 19th March will be further revised and accordingly the General Discussion on the Budget will take place on the 24th, and if necessary on the 25th also and the Voting on Demands for Grants on the 25th, 26th and if necessary on the 27th March 1953. There will thus be no meetings on the 21st, 22nd and 23rd and the days now announced by me for the General Discussion as also for Voting on Demands for Grants would not be subject to any further revision, except that, if desired, meetings of the House may be held in the afternoons also.

कुछ माननीय सदस्य--No objection.

श्री अध्यक्ष--It may be mentioned that at the close of the Voting on demands on the 30th March 1953 the Hon'ble Minister for Finance shall introduce the relevant Appropriation Bill. The Appropriation Bill will thus be taken up for consideration and for passing on the 31st March.

It may be repeated for information that the calendar of meetings would be revised accordingly and the same as revised will not be subject to any change afterwards.

We will have thus no meeting tomorrow, and on the 28th as we had formerly scheduled.

We continue to meet at 8-15 A. M. as we have been doing ?

कुछ सदस्य--Yes.

श्री अध्यक्ष—We now adjourn to 24th, the 23rd being a holiday on account of Ram Naumi. So we shall meet on the 24th at 8-15 A. M. (इसके पश्चात् सदन १२.५० (मध्यान्ह) बजे, मंगलवार दिनांक २४-३-५३ के प्रातः ८.१५ बजे तक के लिये स्थगित होगया) ।

सभा भवन,
जयपुर,
२० मार्च, १९५३.

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिन्हें मुद्रित कराने की संबंधित मंत्रियों की अनुमति है)

५५५. (३६/डी.सी.एम.) श्री मोतीराम, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १०७—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला गंगानगर में कितने थानेदार पुलिस ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है ?

(ख) इन्हें, अन्ट्रेन्ड होते हुए भी, थानों में क्यों रखा हुआ है; जब कि ट्रेन्ड थानेदार इस महकमे में मौजूद हैं ?

(ग) स्पेशल थानेदार किस आधार पर नियुक्त किये जाते हैं ?

(घ) क्या कोई ऐसा थानेदार भी है कि जिसे एक थोड़े से समय में ही हिन्दूमल कोट से अलवर और वहां से तुरन्त ही झुन्झुनू और वहां से गंगानगर जिले के थाना हनुमानगढ़ में बदला गया है ? यदि ऐसा हुआ तो क्यों ? इस अदला-बदली में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

(ङ) क्या वर्तमान थानेदार हनुमानगढ़ ट्रेन्ड हैं ? अगर नहीं तो उसे किस आधार पर वहां लगाया हुआ है ?

उत्तर

जिला गंगानगर के सब पुलिस थानेदार स्थानीय ट्रेन्ड हैं और उनमें से ५० प्रतिशत के लगभग प्रान्तीय पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पास हैं।

२. स्पेशल थानेदार का पुलिस में कोई पद नहीं है।

३. थानेदार मुकन्दसिंह का स्थानान्तर निम्नलिखित कारणों से एक से अधिक स्थानों पर हुआ है:—

(क) बीकानेर रेन्ज से जयपुर रेन्ज में पुलिस के एकीकरण की नई स्कीम के अन्तर्गत बीकानेर डिविजन में २१ थानेदार स्वीकृत संख्या से अधिक थे जिनकी सूची में इस थानेदार का नाम था अतः उसको बीकानेर रेन्ज से जयपुर रेन्ज में बदलना पड़ा अन्य २० थानेदारों के साथ।

(ख) अलवर से झुन्झुनू तथा झुन्झुनू से जयपुर।

(ग) जयपुर से हनुमानगढ़ शासन संबंधो के कारण से।

इस अदला बदली से सरकार का लगभग ३०० रुपया व्यय हुआ।

(४) मौजूदा थानेदार श्री मुकन्दसिंह स्थानीय ट्रेन्ड हैं।

५५६. (४४. डो.सी.एम.) श्री लालूराम, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ८४-क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस वर्ष कितने केस चोरी के बरामद हुए, कितने पकड़े ग और कितने फैसले किए गए ?

(२) जिला टोंक में कितने चोरी के केस पकड़े, कितने बरामद हुए और कितने केसेज के फैसले सुनाये गये ?

उत्तर

१. २५८९ मुकद्दमात चोरी के साल ५२ में बरामद हुए जिनमें से ८३९ सजायाब हुए और और २४४ रिहा (बरी) हुए। इन कुल मुकदमात में ३७५९ आदमी पकड़े गए हैं।

२. जिला टोंक में साल ५२ में ९५ मुकदमात चोरी के बरामद हुए जिनमें १८७ आदमी पकड़े गए। बरामद शुदा मुकदमात में से २० सजायाब हुए और १५ रिहा (बरी) हुए।

५७९. (७५/डी.सी.एम.) श्री धर्मचन्द, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ३६--क्या गृह मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भ्रष्टाचार मिटाने के संबन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

(२) क्या सरकार इसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाने को तैयार है ?

(३) यदि हां, तो वह क्या है ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

Effective steps have been taken towards eradication of the evil. The problem is not to enact more strict legislation, but to bring home the guilty to the accused in a Court of Law under the existing provisions of the Indian Evidence Act.

५८०. (७४/डो.सी.एम.) श्री कपिलदेव अग्रवाल, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ७१-क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

मौजा टाई, थाना मंडावा, जिला झुन्झुनू में ताजिरी पुलिस ठाकुर छतूसिंह या किसी और पर नियुक्त की गई थी ? यदि हां तो:—

(क) कब और कितने समय तक ?

(ख) उसका कितना खर्च हुआ ?

(ग) उक्त ताजिरी पुलिस का खर्चा वसूल किया गया या नहीं ?

(घ) यदि नहीं, तो उसके लिए क्या चेष्टा की गई और की जा रही है ?

उत्तर

जी, हाँ ।

(क) १४ अक्टूबर सन् १९४४ में, १४ अक्टूबर सन् १९४५ तक ।

(ख) ४१८६..१. ६. ।

(ग) इसमें से १४७.६.६. वसल किया गया। बाकी ४०३८.१.१ माका बिल वसूल होने के कारण छूट दे दिया गया ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५७४ देखिये)

प्रश्न

चीफ कन्जवटर ने सन् ५२ में किन किन स्थानों का किन किन कारणों को लेकर भ्रमण किया ?

उत्तर

सन् ५२ में निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया।

भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बारां, बून्दी, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, अलवर, देहरादून, इन्दौर।

निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त स्थानों का दौरा किया।

इन्सपेक्शन के लिये।

फ़ोरेस्ट मिनिस्टर से मिलने के लिये जयपुर आये।

एडहॉक कमेटी डेजर्ट कन्ट्रोल का दौरा फोरेस्ट कॉलिज देहरादून के उम्मीदवारों को मौखिक परिक्षा लेने देहरादून गये।

रेवेन्यु सेक्रेटरी से मिलने जयपुर।

एडवाइजरी बोर्ड शिवपुरी स्कूल की मीटिंग में शरीक होने इन्दौर गये।

प्रश्न

उपर्युक्त भ्रमण किन किन स्थानों पर मोटर से कहां से कहां तक एवं ट्रेनों में किन स्थानों पर किया ?

उत्तर

उपर्युक्त स्थानों का दौरा कभी ट्रेन तथा कभी मोटर द्वारा किया गया। इन्दौर व देहरादून ट्रेन से गये।

प्रश्न

उपर्युक्त भ्रमण में कितना रुपया वर्ष भर में खर्च हुआ ?

उत्तर

चार हजार चार सौ गुनतीस रुपया ग्यारह आना छः पाई

प्रश्न

क्या यह सत्य है कि इन भ्रमणों में अधिकतर कार्य शिकार करने का ही था ?

उत्तर

जी नहीं।

(कृपया प्रश्न ५७८ देखिये)

१. हिज हाईनेस महारावल डूंगरपुर को निम्नलिखित वन निजी संपत्ति में दिये गये हैं।

१. राजधानी रकबा १३ वर्ग मील

२. पालीसोडा रकबा ७ वर्ग मील

३. कैलाश रेंज रकबा ३/४ वर्ग मील

२. अलवर, बांसवाडा, बून्दी, जोधपुर, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, व उदयपुर के शासकों को भी इसी प्रकार निजी संपत्ति में वन दिये गये हैं।

३. राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये गये राजस्थान फोरेस्ट एक्ट के शीघ्र ही लागू होने की आशा है। इस बिल के द्वारा संधिपत्रांतर्गत राज्यों के शासकों व अन्य संबन्धियों के शिकार करने, मछली पकड़ने व उन अन्य अधिकारों की रक्षा की गई है जिनको शिकारगाहों, वनों व अन्य क्षेत्रों में संधिपत्रों तथा तत्संबंधी अन्य लेखों द्वारा मान्यता दी गई है। इन अधिकारों का उल्लेख निजी संपत्ति की सूचियों में भी है। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में साधारण कानून व नियम शासकों पर भी लागू होंगे।

४. हिज हाईनेस महारावल डूंगरपुर के निजी वनों में जो ग्राम बसे हैं उनका संबंध उनसे ही है। राजस्व विभाग द्वारा कोई लगान इन गावों से वसूल नहीं किया जाता है।

———————

Page No.86

परिशिष्ट ३

अतारांकित प्रश्नोत्तर

(सदन की मेज पर रखा गया)

८. (६६/एल. एम.) श्री हरिकृष्ण व्यास, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १६०—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर डिविजन में बाडमेर के पास कपूर्डी की मुल्तानी मिट्टी (मेट) की खानियां का ठेका जो ३० सितम्बर सन् १९५० ई० में खतम हुआ, जब से अभी तक उसका दूसरा ठेका दूसरे ठेकेदारों की बड़ी २ ऑफरें होते हुए भी क्यों नहीं दिया गया ?

(२) इस ठेके को दुबारा ठेके पर नहीं देने से सरकार को कितने लाख रुपयों का नुकसान हुआ ?

(३) ३० सितम्बर सन् १९५० ई० में मेट का ठेका खतम होने पर इस ठेके को लेने के लिये कितने ठेकेदारों की दरख्वास्तें आई ?

(अ) उनके नाम बतलावें ?

(ब) इस ठेके की सबसे ज्यादा ऑफर किस ठेकेदार ने दी ?

(स) और वह ऑफर कितने लाख रुपयों तक की थी ?

(ड) और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपये मन की रोयल्टी ऑफर हुई ?

(४) ज्यादा से ज्यादा रुपयों की ऑफर इस ठेके के देने वाले ठेकेदार को यह ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

(५) उसी पुराने ठेकेदार को टेम्पोरेरी तीन दफा बिल्कुल कम में ठेका क्यों दिया गया; जब कि दूसरे ठेकेदारों की १) रु० मन की रोयल्टी देने की ऑफर थी और इस पुराने ठेकेदार को सिर्फ ।–) मन में और फिर ।॥–) मण में ही क्यों दिया गया है ?

(६) माइनिंग मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्दर जो ठेकों की मोनोपोली तोड़ दी गई है तो फिर इसी ठेके पर मोनोपोली क्यों रक्खी गई है और बार २ इसी ठेकेदार को ठेका क्यों दिया जाता है ?

(७) ३० सितम्बर सन् १९५० में जब मेट का ठेका खतम हुआ उस वक्त उस ठेकेदार के पास स्टॉक में कितने मन मेट थी ?

(८) बाडमेर व कपुर्डी में जहां कि सारा एरिया मुल्तानी मिट्टी का ही है वहां पर सरकार ने जान बूझ कर मुल्तानी मिट्टी का एरिया लीज पर क्यों दिया है ; जब कि दूसरे ठेकेदारों को लीज पर देना बराबर मना करते रहे हैं ? क्या इससे सरकार को आमदनी की हानि नहीं हुई ?

(६) क्या सरकार इस ठेके के मुतअल्लिक कोई जांच कराने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. मुल्तानी मिट्टी का दूसरा ठेका इसलिये नहीं दिया गया कि इस बीच में खनिज नियम (Mineral Concession Rules) लागू हो गये थे और सरकार द्वारा उसको नये प्रकार से देने की पोलीसी (Policy) विचाराधीन थी ।

२. अन्तरिम काल में पहिले की अपेक्षा कुछ अधिक ही आमदनी हुई है इसलिये नुकसान का प्रश्न नहीं उठता ।

३. जोधपुर खनिज विभागीय कार्यालय में १२ दरख्वास्तें ठेकेदारों की आई ।

(अ) १. मैं० रामजस धनराज
२. मैं० मुरलीधर मांगीलाल
३. मैं० टीकमदास मानकराम, बाडमेर
४. मैं० गब्बार एन्ड को०, कलकत्ता
५. श्री रामलाल कछावा
६. श्री प्रयाग प्रसाद
७. मैं० मूलचन्द खेमराज मल,बाडमेर
८. मैं० एन० खाजूलाल एन्ड को०, जयपुर
९. मैं० लीलचन्द खेमराज
१०. श्री हुकमसिंह
११. मैं० गोविन्द प्रसाद एन्ड सन्स, बीकानेर
१२. राय बहादुर सेठ मूलचन्द नेमीचन्द

(ब) मैं० रामजस धनराज

(स) वह ऑफर २०१) रु० फी दस टन रोयल्टी की थी ।

(ड) इस प्रश्न का उत्तर (स) में दे दिया गया है

४. गवर्नमेन्ट इन दरख्वास्तों को मिनरल कन्सेशन रूल्स के लागू होने के कारण व मेंट के नये ठेके की पोलीसी निर्धारित हुये बगैर विचार नहीं कर सकती थी ।

नहीं ।

५. टैम्पोरेरी मियाद इसलिये दी गई थी कि इस बीच में मजदूर वर्ग काम पर लगे रहें और सरकार को पोलीसी निर्धारित करने के लिये कुछ और अवकाश मिल सके ।

६. नये ठेकेदारों की दरख्वास्तों पर विचार इसलिये नहीं किया गया कि इससे मिनरल कन्सेशन रूल्स की अवहेलना हो सकती थी । २४। फी टन की रॉयल्टी इसलिये रक्खी ।

———